RNI No. DELHIN/2022/85477 | पेज - 32

नई दिल्ली, 10 अगस्त - 23 अगस्त, 2026

विकास की पत्रकारिता का अग्रदूत

ब्लिट्ज इंडिया

वर्ष : 4, अंक : 44 https://hindi.blitzindiamedia.com/ ₹30/-

जीएसटी कलेक्शन में बंपर उछाल, जुलाई में आंकड़ा 2.11 लाख करोड़ के पार 13

पेपर लीक : विपक्ष का 'चुनिंदा आक्रोश'
प्रधान संपादक की कलम से
दीपक द्विवेदी 2

सुरक्षित और परीक्षित ईन्धन है ई20 16-17

सभी शादीशुदा बेटियां दया के आधार पर नौकरी देने की नीति में शामिल 12

पीएम मोदी का पोस्ट हटाने पर मेटा को पड़ी सख्त मार...

जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफी

दुनिया को संदेश : नहीं चलेगी सोशल मीडिया की मनमानी

दीपक द्विवेदी

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी समाचार सेवा 'बीबीसी' को सबक सिखाने के बाद दिग्गज सोशल मीडिया 'मेटा' को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सख्ती का जोरदार संदेश दिया है। मेटा को भारत में कार्यवाही से पहले ही भारतीय कानूनों की ताकतों का एहसास दिला दिया है। इसी माहौल को भांपते हुए मेटा कंपनी के मालिक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सरकार से सार्वजनिक माफी मांगी है। मोदी सरकार का सोशल मीडिया के खिलाफ यह कड़ा कदम दुनिया की अन्य सभी शीर्ष सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि मनमानी नहीं चलेगी और सभी को भारतीय कानूनों का पालन एवं सम्मान करना होगा।

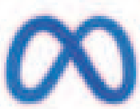

भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी कंपनियों की बढ़ती ताकत और उनके एल्गोरिदम की मनमानी पर एक मजबूत संदेश दिया है। कोई भी डिजिटल मंच, चाहे कितना ही बड़ा और प्रभावशाली क्यों न हो, वह देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता और न ही अपने फैसलों की जवाबदेही से बच सकता है।

आपकी जानकारी के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट को फेसबुक पर गलती से प्रतिबंधित किए जाने और उसके बाद मेटा की ओर से माफी मांगे जाने की घटना अब केवल एक वीडियो या तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं रह गई है। इसने डिजिटल संप्रभुता, सोशल मीडिया की जवाबदेही और दुनिया की विशाल टेक कंपनियों के बढ़ते प्रभाव को लेकर चल रही वैश्विक बहस को नई दिशा दी है।

- डिजिटल मीडिया की 'लक्ष्मण रेखा' तय
- भारतीय कानून का करना होगा सम्मान

भारत सरकार ने इस मामले को सामान्य तकनीकी गलती मानकर छोड़ने के बजाय मेटा से उच्च स्तर पर जवाब मांगा था। कंपनी के वरिष्ठ वैश्विक अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रोक आखिर कैसे लगी ? मामला संसद की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति तक पहुंचा और डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठे।

सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने बाद में गलती स्वीकार करते हुए पोस्ट को बहाल किया। कंपनी के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कैपलन ने प्रधानमंत्री की पोस्ट पर गलती से लगी रोक के लिए मेटा की ओर से माफी मांगी। कंपनी ने यह भी माना कि उसके प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल, डीपफेक और कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी चूक हुई हैं। सरकार ने मेटा से कहा कि वह आईटी अधिनियम के तहत खुद को सिर्फ एक इंटरमीडियरी नहीं कह सकती। - शेष पेज 31 पर

ई20 : आत्मनिर्भर भारत की नई क्रांति

भारत ने बचाई ₹1.98 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा

विनोद शील

नई दिल्ली। ई20 सिर्फ नया पेट्रोल नहीं बल्कि नए भारत की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भर भारत की नई क्रांति है जो अन्नदाता के ऊर्जादाता बनने का शुभारंभ है। भारत ने ऐसे ही इसकी घोषणा नहीं की बल्कि पूरी तैयारी के बाद ई20 ईन्धन (20 फीसद एथेनॉल और 80 फीसद पेट्रोल का मिश्रण) लागू किया गया है।

इसके लिए एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई। डिस्टिलरी विस्तार को वित्तीय सहायता दी गई। ऑयल कंपनियों ने एथेनॉल की सुनिश्चित खरीद की। एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक प्रमुख ऑटोमोटिव अनुसंधान और प्रमाणन संगठन है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह भारत में बिकने वाले सभी वाहनों के परीक्षण, सुरक्षा मानकों और माइलेज को प्रमाणित करता है), ऑटो कंपनियों और विशेषज्ञों के साथ व्यापक परीक्षण किए गए।

तो पेट्रोल 125 प्रति लीटर होता

ई20 ब्लेंडिंग पर केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती तो ईरान-अमेरिका युद्ध के चरम के दौरान भारत में पेट्रोल ₹125 प्रति लीटर तक पहुंच सकता था।

ईन्धन की उपलब्धता, इंजन की तैयारी और वैज्ञानिक परीक्षण सफल होने के बाद ही ई20 ईन्धन को चरणबद्ध तरीके से देशभर में लागू किया गया। इसलिए जरूरी है कि अफवाहों पर ध्यान न देकर सही का चयन किया जाए क्योंकि भारत ही नहीं; अन्य देशों में भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग किया जा रहा है।

ई20 ईन्धन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, विदेशी मुद्रा बचाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का एक दूरदर्शी कदम है। इससे किसानों और डिस्टिलरी उद्योगों को ₹1.66 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। - शेष पेज 31 पर

पेपर लीक : विपक्ष का 'चुनिंदा आक्रोश'

दीपक द्विवेदी
एडीटर-इन-चीफ

प्रधान संपादक की कलम से

भारत में प्रतियोगी और अकादमिक परीक्षाएं करोड़ों युवाओं के लिए केवल रोजगार या उच्च शिक्षा का जरिया नहीं हैं बल्कि यह उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान का एकमात्र रास्ता हैं। जब इन परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, तो केवल एक प्रश्नपत्र नहीं बिकता, बल्कि लाखों परिवारों के सपने, उनकी वर्षों की मेहनत और देश की पूरी व्यवस्था पर से भरोसा टूट जाता है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और यूजीसी-नेट को लेकर पूरे देश में भारी हंगामा हुआ। संसद से लेकर सड़कों तक विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा जो कि लोकतंत्र में एक सजग विपक्ष का स्वाभाविक कर्तव्य भी है लेकिन जब यही संकट गैर-भाजपा शासित राज्यों जैसे कर्नाटक, पंजाब और झारखंड में सामने आता है तो विपक्ष की यह मुखरता अचानक एक सुविधाजनक मौन या लचर बहानों में बदल जाती है। राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से चुनी गई यह चयनात्मक संवेदनशीलता और दोहरा मानदंड युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है।

राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश बनाम राज्यों में चुप्पी

नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के आरोपों पर विपक्ष का आक्रामक होना पूरी तरह तर्कसंगत था। राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर था और केंद्रीय एजेंसियों की विफलता पर सवाल उठना लाजिमी था लेकिन नैतिक और राजनीतिक संकट तब खड़ा होता है जब ठीक वैसी ही या उससे भी अधिक गंभीर धांधलियां कर्नाटक, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में होती हैं और वहां विपक्ष या तो मौन साध लेता है या फिर पूरी घटना को दबाने की कोशिश करता है।

उदाहरण के लिए, झारखंड में 'झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा' (जेएसएससी-सीजीएल) का पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इसके बाद उपजे आक्रोश और राज्य सरकार की ढिलाई ने लाखों युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया। इसी तरह, पंजाब और कर्नाटक में भी सरकारी भर्तियों और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और लीक के गंभीर मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में केपीटीसीएल भर्ती और पुलिस सब-इंस्पेक्टर घोटाले ने पूरे तंत्र की कमियों को उजागर किया था। इन राज्यों में जब छात्र सड़कों पर लाठियां खा रहे थे, तब राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक को 'राष्ट्रीय संकट' बताने वाले नेता अपने ही राज्यों की व्यवस्था पर आत्ममंथन करने के बजाय बगलें झांकते नजर आए।

> **विपक्ष को यह समझना होगा कि विश्वसनीयता केवल सवाल उठाने से नहीं, बल्कि एक समान मापदंड अपनाने से आती है।**

दोषारोपण की राजनीति और संघीय ढांचे का बहाना

विपक्ष के इस दोहरे मानदंड के पीछे विशुद्ध रूप से चुनावी और राजनीतिक हित छिपे हैं। जब मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) का होता है, तो विपक्ष इसे सीधे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की नीतिगत विफलता से जोड़ देता है लेकिन जब बात उनके अपने प्रभाव या गठबंधन वाले राज्यों की आती है तो इसे 'प्रशासनिक चूक' या 'स्थानीय स्तर के अपराधियों की साजिश' बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। यह प्रवृत्ति इस कड़वे सच को उजागर करती है कि राजनीतिक दलों के लिए युवाओं का भविष्य एक साझा राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं बल्कि सरकार को घेरने का एक राजनीतिक हथियार मात्र है। यदि विपक्ष वास्तव में परीक्षाओं की शुचिता को लेकर चिंतित होता तो वह अपने शासित राज्यों में एक ऐसा कड़ा और पारदर्शी मॉडल स्थापित करता जो केंद्र सरकार के लिए एक मिसाल बनता।

छात्रों के विश्वास और देश के भविष्य पर चोट

पेपर लीक की घटनाएं चाहे नई दिल्ली से संचालित हो रही हों, रांची से, बेंगलुरु से या चंडीगढ़ से; इनका शिकार होने वाला छात्र हमेशा एक ही होता है। वह छात्र किसी राजनीतिक दल का वोटर होने से पहले इस देश का नागरिक है जिसने दिन-रात एक करके पढ़ाई की है। जब विपक्षी दल इस मुद्दे पर 'चुनिंदा आक्रोश' दिखाते हैं तो वे अनजाने में उस पूरे आपराधिक तंत्र को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं जो पेपर लीक के पीछे सक्रिय है। यह दोहरा रवैया छात्रों के मन में पूरी लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा करता है।

राजनीति से ऊपर उठें

पेपर लीक व परीक्षाओं में धांधली राष्ट्रीय महामारी का रूप ले चुकी है। यह किसी एक दल की सरकार की विफलता नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र और प्रशासनिक ढांचे की सामूहिक सड़न का परिणाम है। इसका समाधान तब तक संभव नहीं जब तक कि राजनीतिक दल इस पर राजनीति करना बंद नहीं करते। विपक्ष को समझना होगा कि विश्वसनीयता केवल सवाल उठाने से नहीं, बल्कि समान मापदंड अपनाने से आती है। यदि नीट पर मंत्री का इस्तीफा हुआ तो राज्यों में पेपर लीक पर भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई व जवाबदेही तय हो। युवाओं को एक ऐसे 'जीरो टॉलरेंस' मॉडल की जरूरत है जहां पेपर लीक करने वालों को देशद्रोही की श्रेणी में रखकर सजा दी जाए, चाहे वे किसी भी राज्य में सक्रिय हों।

नॉर्थ-ईस्ट बना विकसित भारत का नया ग्रोथ इंजन

12 साल में बदली तस्वीर, बेहतर कनेक्टिविटी और तेज विकास के साथ उत्तर-पूर्व रच रहा सफलता की नई कहानी

ब्लिट्ज विशेष

एक समय था जब भारत के उत्तर-पूर्व को देश का सबसे दूर-दराज और विकास में पीछे छूटा हुआ इलाका माना जाता था लेकिन आज वही उत्तर-पूर्व भारत की सबसे बड़ी विकास गाथाओं में से एक बन चुका है। पिछले 12 वर्षों में बेहतर नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, मजबूत कनेक्टिविटी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले प्रयासों ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है।

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम- ये आठों राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और रणनीतिक स्थिति के कारण आज भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर-पूर्व अब केवल सीमावर्ती क्षेत्र नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है।

सरकारी योजनाओं से मिली नई रफ्तार

वर्ष 2014 के बाद उत्तर-पूर्व के विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के माध्यम से हजारों विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं बल्कि हर राज्य की जरूरत के अनुसार संतुलित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है।

पीएम-डिवाइन (पीएम-डीईवीआईएनई) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन), एनईएसआईडीएस उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (नॉर्थ ईस्ट

स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम), नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) और असम-त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज जैसी योजनाओं ने सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है।

एक्ट ईस्ट नीति से बढ़ा दुनिया से जुड़ाव

भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने उत्तर-पूर्व को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएं व्यापार, पर्यटन और आर्थिक सहयोग को नई दिशा दे रही हैं। सीमा क्षेत्रों में भी आधुनिक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है।

कनेक्टिविटी ने बदल दी विकास की रफ्तार

उत्तर-पूर्व में सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है और रेल नेटवर्क लगातार नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है।

बोगीबील ब्रिज, ढोला-सादिया ब्रिज, नोने ब्रिज और सेला टनल जैसी परियोजनाओं ने लोगों की यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान, सुरक्षित और तेज बना दिया है।

उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डे और क्षेत्रीय हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास से परिवहन और नदी पर्यटन को भी नई गति मिली है।

खुल रहे नए अवसर

अब विकास केवल सड़क और पुल तक सीमित नहीं है। भारतनेट और अन्य डिजिटल योजनाओं के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाया गया है। मोबाइल टावरों के विस्तार से दूर-दराज के क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं।

हर क्षेत्र में हो रहा समावेशी विकास

उत्तर-पूर्व में आज कृषि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर लागू की गई योजनाओं ने इस क्षेत्र को अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाया है।

एक नजर में

- उत्तर-पूर्व के आठों राज्यों में तेज विकास
- हजारों विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता
- पीएम-डिवाइन और अन्य योजनाओं से आधारभूत ढांचे को मजबूती
- सड़क, रेल, हवाई और जलमार्गों का तेज विस्तार
- एक्ट ईस्ट नीति से दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ बेहतर संपर्क
- भारतनेट और डिजिटल योजनाओं से गांवों तक इंटरनेट की पहुंच
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका में लगातार सुधार

जैविक खेती को मिली नई पहचान

पूर्वोत्तर भारत आज केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए ही नहीं, बल्कि जैविक खेती और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी देश के लिए एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं ने यहां के किसानों को आधुनिक कृषि, बेहतर बाजार और नई व्यावसायिक संभावनाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऑर्गेनिक खेती को मिला बड़ा प्रोत्साहन

मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट (एमओवीसीडी-एनईआर) योजना ने पूर्वोत्तर में जैविक खेती को नई गति दी है। इस योजना के तहत किसानों को केवल ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और बाजार तक की पूरी वैल्यू चेन से भी जोड़ा गया है।

इस वर्ष मई तक लगभग 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है जिससे करीब 2.70 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है।

किसानों को मिले नए बाजार

कृषि उड़ान योजना ने पूर्वोत्तर के किसानों के लिए नए अवसर खोले हैं। अब फल, सब्जियां, फूल और अन्य जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पाद हवाई मार्ग से देश के विभिन्न बाजारों तक कम समय में पहुंचाए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ी है।

इस योजना के तहत देश के 58 हवाई अड्डे जुड़े हुए हैं जिनमें से 25 हवाई अड्डे पूर्वोत्तर क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करते हैं।

वन धन विकास योजना से आदिवासी परिवारों को मिला संबल

वन-धन विकास योजना ने पूर्वोत्तर के वन आधारित जीवन और आजीविका को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के माध्यम से विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को वन उत्पादों के मूल्यवर्धन, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिली है।

स्थानीय उत्पादों को मिली नई पहचान

पूर्वोत्तर के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को अब भौगोलिक संकेतक (जीआइ) टैग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। मार्च तक पूर्वोत्तर के 89 उत्पादों को जीआइ पंजीकरण मिल चुका था। इसके अलावा अगले दो वर्षों में 150 और उत्पादों को जीआइ टैग देने के लिए चिन्हित किया गया है। इससे स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचने और उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है।

कृषि उत्पादों के विपणन के लिए कार्यरत एनईआरएएमएसी ने किसानों को बाजार से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2021 तक एनईआरएएमएसी द्वारा विपणन किए जाने वाले प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों की संख्या 38 से बढ़कर 75 से अधिक हो गई।

पीएम बोले- युवाओं ने देश का मान बढ़ाया

ब्लिट्ज विशेष

यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था
प्रधानमंत्री ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 136वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस ऐसी तारीख है, जिस के लिए दिन याद रखने की जरूरत नहीं होती।

पीएम ने देश के युवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा- हमारे युवा भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स , केमेस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड हुए। इनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री ने कहा- पिछले रविवार विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। हम सभी ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के इस ऐतिहासिक पल को देखा। यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वह कर दिखाया, जो कभी लगभग असंभव लगता था। उन्होंने अपने असाधारण कौशल, जुनून और धैर्य का परिचय दिया।

पीएम के 'मन की बात' की बड़ी बातें

कारगिल विजय दिवसः पीएम ने कहा- यह ऐसी तारीख है, जिसे दिन याद रखे बिना भी याद रखा जाता है। कारगिल में जवानों ने कठिन चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानी। दिल्ली से द्रास तक शौर्य विजय यात्रा निकाली जा रही है।

आईएनएस महेंद्रगिरी और पिनाकाः पीएम ने कहा- भारत रक्षा तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल हुआ और पिनाका मिसाइल का भी सफल लॉन्च हुआ।

कैच द रेन और जल संरक्षणः पीएम ने कहा कि जहां पानी गिरे, उसे वहीं रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश में 4 हजार तालाब बने और कई राज्यों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आज बचाई गई पानी की हर बूंद भविष्य की पूंजी है।

कॉमनवेल्थ गेम्स और खिलाड़ियों की उपलब्धियांः मोदी ने कहा- ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की। उन्होंने पीवी सिंधु के जापान ओपन जीतने और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट जीत का जिक्र किया।

विक्रम-1 और युवा इनोवेटर्सः पीएम ने कहा- विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण भारत के स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है और युवाओं ने वह कर दिखाया, जो कभी असंभव लगता था।

साइंस ओलंपियाडः पीएम ने कहा- भारतीय छात्रों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियानः पीएम ने अहमदाबाद में एक घंटे में 3.5 लाख और यूपी में एक दिन में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने का जिक्र किया। लोगों से प्रकृति संरक्षण में भागीदारी की अपील की।

प्लास्टिक मुक्त भारतः पीएम ने बिहार के सीतामढ़ी में प्लास्टिक कचरे से बेंच बनाने की पहल का उदाहरण दिया। गणेशोत्सव पर पीओपी और प्लास्टिक की बजाय मिट्टी की गणेश प्रतिमा अपनाने की अपील दोहराई।

लोकल प्रोडक्ट्स, हैंडलूम और खादीः पीएम ने कश्मीर की वागु चटाई, बिजनौर की हर्बल चाय, नेशनल हैंडलूम डे और खादी की बढ़ती बिक्री का जिक्र करते हुए लोकल उत्पाद खरीदने की अपील की।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम और हर घर तिरंगाः पीएम मोदी ने कलाम को याद किया, गुरु पूर्णिमा और स्वतंत्रता दिवस का जिक्र करते हुए 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।

मोदी बोले- 12 सालों में खादी की बिक्री छह गुना बढ़ी

पीएम ने कहा- कुछ दिनों बाद देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। हाथ से बने उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों के हुनर और मेहनत का प्रतीक हैं। आज पोचमपल्ली, पटना और कच्छ जैसे क्षेत्रों के हैंडलूम उत्पादों को नई पहचान मिल रही है।

मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और इसकी बिक्री छह गुना बढ़कर 8 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने लोगों से खादी खरीदने की अपील की। साथ ही त्रिपुरा के सूरज कुमार देव वर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पारंपरिक चोंग पैंग वाद्य यंत्र और त्रिपुरा के अन्य लोक वाद्य यंत्रों को फिर से लोकप्रिय बनाने का काम किया है।

कार्यक्रम के अंत में मोदी ने कहा कि कुछ ही सप्ताह बाद स्वतंत्रता दिवस है। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले लोगों को याद करना चाहिए और 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही लोगों से भविष्य के 'मन की बात' कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजते रहने की अपील भी की।

मोदी ने मणिपुर के वैज्ञानिक डॉ. रोनाल्डो मीनांशम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने युवा आकाशगंगाओं (यंग गैलेक्सीज) की खोज की है। उन्होंने इस नई आकाशगंगा का नाम 'लोकटक प्रोटोक्लस्टर' रखा, जो मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर है। इससे मणिपुर का नाम दुनियाभर में पहुंच रहा है।

पीएम ने कहा- आज प्लास्टिक प्रदूषण हमारे देश के लिए एक खतरा बना हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में कचरे की रीसाइक्लिंग कर बेंच बनाई जा रही है। 1 बेंच में 40 किलो प्लास्टिक लगाई जा रही है। इसे स्कूल और पार्कों में लगाया जा रहा है। यहां स्थानीय इकाई के साथ प्रशासन की भी भूमिका है। इससे हमें पता चलता है कि रिड्यूस, रियूज और रीसाइकल देश का नारा बनता जा रहा है।

पीएम बोले- लोकल प्रोडक्ट्स और पारंपरिक हुनर को नई पहचान मिल रही है।

पीएम ने कहा- मुझे देखकर खुशी होती है कि देश में ओलंपियाड और हैकाथॉन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। कश्मीर की पाम्पोरी चटाई वागु को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं उसमें भी इसकी झलक मिलती है। इसे कश्मीर के दलदली इलाके की घास से हाथों से बुनकर बनाया जाता है। ये चटाई अनोखी भी है और इसे बनाने में 4 दिन लगते हैं। पहले ये कश्मीर के हर घर में दिखती थी लेकिन अब ये कम हो गई है लेकिन कश्मीर के गुलाम हुसैन जी ने इसको फिर से शुरू किया और इस कौशल को भी उन्होंने खूब बढ़ाया।

पीएम ने कहा- हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है। ये हर मौके का हिस्सा बन जाती है। आप सब भी जानते हैं कि चाय से मेरा रिश्ता क्या है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव की महिलाओं ने हर्बल चाय तैयार की है। इसमें गिलोय और इलायची शामिल है। इस चाय ने लोगों के बीच खास पहचान बना ली है। विदेश से आए लोगों ने भी इसमें खूब रुचि दिखाई। ये सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुई थी।

पीएम ने गुजरात के गिर जंगल में हॉर्नबिल पक्षी की वापसी का भी जिक्र किया, जिसे पर्यावरण संरक्षण की सकारात्मक पहल बताया गया।

महिला टीचर की सराहना

मोदी ने केरल के एर्नाकुलम की एक महिला टीचर की सराहना की, जो फुटबॉल के नियमों और मैचों की घटनाओं के जरिए बच्चों को संस्कृत सिखा रही हैं।

ब्लिट्ज ब्यूरो

'विद्यालय ने मुझे अक्षर दिए और गरीबी ने ज्ञान का प्रकाश'

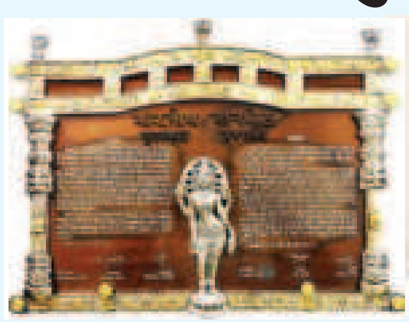

ज्ञानपीठ पुरस्कार पर विशेष

नई दिल्ली। तमिल कवि, उपन्यासकार और गीतकार आर. वैरामुत्तु को 60 वां ज्ञानपीठ पुरस्कार चिन्मय मिशन सभागार में विद्वान एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने प्रदान किया। 11 लाख रुपये की राशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा वाला यह सम्मान उन्हें उनके 73वें जन्मदिन पर मिला।

'साठवें ज्ञानपीठ ने मानो मुझे साठ ग्राम अमृत से भरी एक शीशी सौंप दी हो,' वैरामुत्तु ने कहा। उन्होंने तमिल में भाषण दिया, जिसका सार हिंदी में प्रस्तुत किया गया। यह अमृत अकेले मेरा नहीं है। यह उन सभी महान साहित्यकारों का है जो मुझसे पहले आए।

14 मार्च 2026 को घोषित इस सम्मान के साथ वैरामुत्तु देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बन गए। उनसे पूर्व 1975 में अकिलन और 2002 में जयकांतन को यह सम्मान मिला था। दोनों उपन्यासकार थे। तमिल से वैरामुत्तु पहले रचनाकार हैं जिन्हें मुख्यतः कवि के रूप में यह सम्मान मिला है। मेरे विद्यालय ने मुझे अक्षर दिए और गरीबी ने ज्ञान का प्रकाश, उन्होंने सभा से कहा। दोनों ने मिलकर मुझे साहित्य का सेवक बना दिया।

एक जन्मदिन से जन्मा पुरस्कार

इस पुरस्कार की स्थापना उद्योगपति साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से की थी , जो 1944 में स्थापित एक सांस्कृतिक संगठन है। एक राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार का विचार उनके समक्ष रखा गया था। रमा जैन ने उसी वर्ष नवंबर में कोलकाता स्थित अपने निवास पर लेखकों को एकत्र किया और 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में लगभग 300 लेखकों ने बैठकर योजना को अंतिम रूप दिया।

वर्ष 1965 का पहला पुरस्कार मलयालम कवि जी. शंकर कुरुप को उनकी कृति ओडक्कुषल "बांस की बांसुरी" के लिए मिला। उन्हें 19 नवंबर 1966 को विज्ञान भवन में एक लाख रुपये प्रदान किए गए। आरंभ के सत्रह वर्षों तक ज्ञानपीठ किसी एक उत्कृष्ट कृति पर दिया जाता रहा। 1982 में अठारहवें पुरस्कार से चयन मंडल ने लेखक के संपूर्ण कृतित्व का मूल्यांकन आरंभ किया।

डूबे हुए गांव का कवि

वैरामुत्तु का जन्म 13 जुलाई 1953 को मेट्टूर में हुआ। लगभग साठ घरों की एक बस्ती, जो तब मदुरै जिले में थी और अब थेनी जिले में है। 1957 में वैगई बांध परियोजना ने उनका गांव अपने में समेट लिया और परिवार वडुगपट्टी चला आया।

यही जलमग्नता आगे चलकर उनके सर्वाधिक चर्चित उपन्यास 'कल्लिक्का ट्टु इदिगासम' का विषय बनी, जिसे 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और जो अब तक 22 भाषाओं में पहुंच चुका है। उनका पहला काव्य संग्रह 1972 में आया, जब वे 19 वर्ष के थे। 1980 में निर्देशक भारती राजा उन्हें सिनेमा में लाए। साढ़े सात हजार से अधिक गीत और कविताएं लिखने के बाद आज उनके नाम सर्वश्रेष्ठ गीत के सात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, देश के किसी भी गीतकार से अधिक। इसके अतिरिक्त उन्हें 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।

'साहित्य के लिए एक विश्वविद्यालय'

पांच दशक की साहित्य यात्रा पर दृष्टि डालते हुए वैरामुत्तु ने सभा के समक्ष चार प्रश्न रखे- नई पीढ़ी में पठन-संस्कृति कैसे विकसित हो, भारतीय साहित्य को उसका वैश्विक स्थान कैसे मिले, तकनीक के इस युग में मातृभाषाएं कैसे जीवित रहें, और साहित्य को रोजमर्रा के जीवन से कैसे जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि भारत में हर तकनीक के लिए विश्वविद्यालय है; साहित्य के लिए भी एक होना चाहिए।

जेन जी पर यूपी में फटाफट काम शुरू

योगी सरकार का नई पीढ़ी की एनर्जी को नया आयाम देने वाला प्लान

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी के प्रदर्शन की देश और दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जेन जी पर फटाफट काम शुरू हो गया है। सरकार उन योजनाओं को प्रमुखता से सामने ला रही है जिनके जरिए यूपी में युवाओं को उद्यमी बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर कई योजनाएं पहले से चल रही हैं। सीएम युवा और यूथ अड्डा, यूपी सरकार की ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं। इनका उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाले से आगे बढ़ाकर रोजगार देने वाला बनाना है। इसके तहत युवाओं को वित्तीय मदद के साथ-साथ स्किल, तकनीक और बाजार में मंच मुहैया कराकर उद्यमिता का नया इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है।

बना यूथ अड्डा

जानकारों का कहना है कि जेन जी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यूथ अड्डा को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्र के बजाय एक समग्र उद्यमिता इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इसके तहत बिजनेस आइडिया से लेकर वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी मॉडल, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अनुभवी उद्यमियों का मार्गदर्शन, सब कुछ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्लान है। यूथ अड्डा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सरकारी सेवा वितरण की पारंपरिक सोच को बदलता है। यहां युवा केवल किसी योजना का लाभार्थी नहीं, बल्कि अवसर का आकांक्षी भी। सरकार का दावा है कि यूथ अड्डा के तहत जेन जी की जरूरतों के अनुरूप सेवाएं विकसित की गई हैं।

स्टार्टअप और उद्यमिता की ओर

योगी सरकार ने महसूस किया कि उद्यमिता की शुरुआत नौकरी मिलने के बाद नहीं, बल्कि कॉलेज और तकनीकी संस्थानों के दिनों से ही होनी चाहिए। इसलिए यूथ अड्डा का फोकस विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक और आईटीआई के विद्यार्थियों पर रखा गया है। इसके तहत छात्रों को प्रेरित किया जा रहा है वे डिग्री पूरी होने के बाद केवल नौकरी के लिए आवेदन करने के बजाए यह सोचें कि वे किस समस्या का समाधान कर सकते हैं और उससे किस प्रकार सफल उद्यम स्थापित किया जा सकता है। योगी सरकार ने यह भी समझा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था तकनीक आधारित होगी। इसी कारण यूथ अड्डा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स और आधुनिक डिजिटल टूल्स पर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि प्रदेश का युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके।

सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, पूरे बिजनेस सफर में साथ

बताया जा रहा है कि यूथ अड्डा केवल ट्रेनिंग देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। यहां युवाओं को बिजनेस आइडिया तैयार करने, परियोजना रिपोर्ट बनाने, बैंक ऋण प्राप्त करने, उद्यम पंजीकरण, जीएसटी, डिजिटल ब्रांडिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वॉट्सएप बिजनेस, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और व्यवसाय विस्तार तक लगातार मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 100 से अधिक तैयार फ्रेंचाइजी मॉडल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूह

यूथ अड्डा के जरिए सरकार प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रयास कर रही है ताकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी समान अवसर मिल सकें। महिला स्वयं सहायता समूहों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का सहयोग देने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों को व्यावसायिक पहचान दिलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पूरे साल चलता रहेगा उद्यमिता का अभियान

यूथ अड्डा को साल भर सक्रिय रहने वाले उद्यमिता मंच के रूप में विकसित किया गया है। यहां बैंकर्स मीट, टेक फेस्ट, स्टार्टअप क्लिनिक, बिजनेस आइडिएशन वर्कशॉप, फाउंडर्स टॉक, नारी शक्ति श्रृंखला, कॉलेज आउटरीच कार्यक्रम और सफल उद्यमियों के अनुभव साझा करने जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

यूपीकॉन निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका

इस पूरी पहल के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीकॉन) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूपीकॉन के एमडी प्रवीण सिंह के मुताबिक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के अंतर्गत यूपीकॉन द्वारा संचालित यूथ अड्डा को प्रदेश में उद्यमिता के एक सशक्त मंच के रूप में विकसित किया जा रहा है। यूपीकॉन युवाओं को प्रशिक्षण, मेंटरशिप, परियोजना परामर्श, बैंकिंग सहायता, डिजिटल सशक्तिकरण और उद्योग जगत से जुड़ाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें सफल उद्यमी बनाकर यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति देना और एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने में सहभागी बनाना है।

उत्तर प्रदेश बना टेक्सटाइल निवेश का नया केंद्र

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल एक्सपो 'भारत टेक्स 2026' में उत्तर प्रदेश ने देश के सबसे आकर्षक टेक्सटाइल और गार्मेंट मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विशेष 'उत्तर प्रदेश राज्य सत्र' में राज्य के वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान और वरिष्ठ अधिकारियों ने देश-विदेश के निवेशकों के समक्ष यूपी की निवेश-अनुकूल नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से विकसित होते औद्योगिक इकोसिस्टम की भव्य तस्वीर पेश की।

उत्तर प्रदेश सरकार के हथकरघा, वस्त्र एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश समृद्ध पारंपरिक हथकरघा विरासत को आधुनिक तकनीक और 'टेक्निकल टेक्सटाइल्स' से जोड़ रहा है। सरकार नीतिगत सुधारों और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के माध्यम से निवेश आकर्षित कर रही है।

4 कंपनियों को ₹5.17 करोड़ की वित्तीय सब्सिडी हस्तांतरित

राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए 'उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति-2022' के तहत चार प्रमुख टेक्सटाइल इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन राशि वितरित की।

- के.डी. प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड (मेरठ): ₹2.37 करोड़
- जी.ओ. पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड (मुरादाबाद): ₹1.26 करोड़
- पैट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड (बुलंदशहर): ₹80 लाख
- विनटेक्स इंडस्ट्रीज (बुलंदशहर): ₹74 लाख

इस वित्तीय सहायता से इन औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन विस्तार, मशीनों के तकनीकी उन्नयन और स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगारों के सृजन को सीधा बल मिलेगा। नया निवेश धरातल पर उतारने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को त्वरित बनाने के लिए चार बड़ी कंपनियों को आधिकारिक रूप से 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' प्रदान किए गए।

इंदौर, सूरत और अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी ट्रेनों में भीड़ कम नहीं हो रही है। यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी हो रही है। कई ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची है।

इसे ध्यान में रखकर कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजरत निजामुद्दीन-इंदौर स्पेशल ट्रेन और उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

सप्ताह में दो दिन चलने वाली इंदौर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन (09309) 31 जुलाई तक चलनी थी। अब यह 30 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को चलेगी। वापसी की दिशा में हजरत निजामुद्दीन-इंदौर स्पेशल (09310) 31 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार व सोमवार को चलेगी।

उधना (सूरत) -अयोध्या कैंट स्पेशल (09093) प्रत्येक शुक्रवार को 28 अगस्त तक चलेगी। वापसी दिशा में अयोध्या कैंट-उधना स्पेशल (09094) 29 अगस्त तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी।

वहीं, उधना-अयोध्या कैंट स्पेशल (09097) प्रत्येक मंगलवार को 25 अगस्त तक चलेगी। अयोध्या कैंट-उधना स्पेशल (09098) 26 अगस्त तक विस्तार दिया गया है। यह प्रत्येक बुधवार को रवाना होगी।

ब्लिट्ज ब्यूरो

जनधन योजना में यूपी नंबर-1 तो राजस्थान चौथे स्थान पर

वित्तीय समावेशन में राजस्थान की ऊंची उड़ान, खातों में ₹24,933 करोड़

जयपुर। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अब 3.86 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं, जिनमें ₹24,933.35 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय (सीएमओ) ने भी इन आंकड़ों को साझा करते हुए इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

जमा राशि के मामले में राजस्थान का अव्वल प्रदर्शन

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनधन खातों में जमा राशि के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यूपी के खातों में ₹67,206.59 करोड़ जमा हैं। इसके बाद बिहार ₹30,760.45 करोड़ के साथ दूसरे और पश्चिम बंगाल ₹25,485.44 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान ₹24,933.35 करोड़ की जमा राशि के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र ₹22,031.73 करोड़ के साथ पांचवें नंबर पर है।

राजस्थान का चौथे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों तक पहुंच रहा है।

3.86 करोड़ खातों में 2.19 करोड़ महिलाओं के

जनधन योजना में राजस्थान की एक और बड़ी उपलब्धि महिलाओं की भागीदारी है। राज्य में मौजूद 3.86 करोड़ जनधन खातों में से 2.19 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। यानी कुल खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है।

सीएमओ के अनुसार, जनधन योजना ने महिलाओं, खासकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है और वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खातों में

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका काफी हद तक समाप्त हुई है।

ओवरड्राफ्ट की सुविधा

साल 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाताधारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्थान में अब तक 2.87 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

रॉकेट की गति से चल रहा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट

पहला चरण 15 अगस्त 2027 से होगा शुरू

ब्लिट्ज ब्यूरो

अहमदाबाद। देश में पहली बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई-अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे पूरे रेल कॉरिडॉर को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इसका पहला चरण 15 अगस्त 2027 से शुरू होगा। ट्रैक को पूरा करने का काम रॉकेट की रफ्तार से चल रहा है और भारतीय रेलवे की ओर से लगातार इसे लेकर अपडेट शेयर किए जा रहे हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया पर गुजरात के भरूच में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वहां चल रहे काम के साथ ही स्टेशन के डिजाइन और लुक की झलक देखने को मिलती है। ये भरूच के दाहेज बाईपास रोड पर बनाया जा रहा है। स्टेशन का बाहरी

स्वरूप दिखाने के साथ ही रेलवे ने पोस्ट में पूरे रूट की जानकारी भी शेयर की है।

स्टेशन पर तेज निर्माण की दिखी झलक

भरूच स्टेशन की जो तस्वीरें रेलवे की ओर से शेयर की गई हैं, उनमें स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म, ट्रैक समेत अन्य कामों को मशीनों और मैनपावर द्वारा पूरा करते हुए दिखाया गया है।

इन सुविधाओं को फाइनल टच

स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे वेटिंग लाउंज, नर्सरी, दुकानें उपलब्ध होंगी। कई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं, जिनमें बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन के बगल में कारों, दोपहिया वाहनों, ऑटो और बसों के लिए यात्री पिक-अप और ड्रॉप सुविधा के लिए बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।

320 किलोमीटर की रफ्तार

यहां बता दें कि भारत की ये पहली बुलेट ट्रेन जब फुल स्पीड में होगी, तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। ऐसे में मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी में अन्य हाई स्पीड ट्रेनों से लगने वाला छह घंटे का समय भी बुलेट ट्रेन के जरिए सिर्फ 2 घंटे के आसापास रह जाएगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरेगा और इसमें 12 प्रमुख स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा, जिनमें मुंबई (बीकेसी), ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं।

महाराष्ट्र में ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस पर पूर्ण विराम

नए परमिट और रिन्यूअल बंद, डांस बार कानून के तहत कार्रवाई

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस व्यवस्था पर बड़ा फैसला लेते हुए नए परमिट जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसी के साथ यह भी फैसला लिया गया है कि पहले से जारी ऑर्केस्ट्रा लाइसेंसों का नवीनीकरण भी अब नहीं किया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग ने परिपत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि डांस बार संबंधी कानून की पाबंदियों से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा लाइसेंसों का वैकल्पिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा था।

शासनादेश

गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य में महाराष्ट्र होटल व बार

रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और उनमें कार्यरत महिलाओं की गरिमा की रक्षा अधिनियम, 2016 पहले से लागू है। इस कानून के लागू होने के बाद डांस बार और नृत्य प्रस्तुतियों पर सख्त नियम लागू किए गए, जिससे डांस प्रदर्शन लाइसेंसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ प्रतिष्ठान प्रतिबंधों से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का वैकल्पिक रूप में उपयोग कर रहे थे। इसी दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने ऑर्केस्ट्रा प्रतिष्ठानों को भी वर्ष 2016 के इसी कानून के दायरे में लाने का फैसला किया।

इसके तहत अब ऑर्केस्ट्रा से संबंधित लाइसेंस महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के बजाय वर्ष 2016 के विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही नियंत्रित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने पहले ही दी थी मंजूरी

इस बदलाव से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव को 2 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद गृह विभाग ने आधिकारिक परिपत्र जारी कर नए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण पर रोक के निर्देश लागू कर दिए।

सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य कानून के दुरुपयोग को रोकना और मनोरंजन प्रतिष्ठानों के संचालन में पारदर्शिता एवं नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है।

चलती बस के आगे सीना तानकर खड़ी हो गई एसीपी मोनिका शुक्ला

भोपाल। भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रदर्शनकारी किसान जब बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक स्कूल बस धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी। बस में कोई ड्राइवर नहीं था, जबकि कुछ किसान बस की छत पर खड़े थे और कुछ लोग नीचे से उसे धक्का दे रहे थे। स्थिति कभी भी बड़ी घटना में बदल सकती थी। मौके पर तैनात एसीपी मोनिका शुक्ला ने जो किया, उसने उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश कर दी।

नहीं की खतरे की परवाह

किसानों की भीड़ के बीच जब बस धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी तो एसीपी मोनिका शुक्ला तुरंत दौड़कर वहां पहुंचीं। खतरे की परवाह किए बिना वह दोनों हाथों से बस को रोकने की कोशिश करने लगीं। सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे और पीछे से बस को धक्क ा दिया जा रहा था लेकिन मोनिका शुक्ला अपनी जगह से नहीं हटीं। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर बस को रोकने की कोशिश जारी रखी। उनके साहस को देखकर मौके पर मौजूद कुछ किसान और पुलिसकर्मी भी मदद के लिए आगे आए। आखिरकार बस रुक गई और हादसा टल गया।

1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लिया संकल्प

मुंबई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने 17 जुलाई को महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन (उमेद) के तहत 'महिला बचत समूह

रजिस्ट्रेशन अभियान' शुरू कर दिया है।

इसके तहत 1 करोड़ लखपति दीदी संकल्प अभियान को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उमेद के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर श्रीधर दुबे पाटील ने बताया, यह अभियान वर्ष 2026 से 2029 तक पूरे राज्य में चलेगा। इसके तहत, उन ग्रामीण महिलाओं को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो अब तक किसी भी बचत समूह से नहीं जुड़ी है। पाटील ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 6 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का संकल्प लिया है।

गुजरात सरकार जनरल वर्ग को देगी बड़ा तोहफा

ईडब्ल्यूएस में बड़े बदलाव की तैयारी

ब्लिट्ज ब्यूरो

अहमदाबाद। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। भाजपा की भूपेंद्र पटेल सरकार सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए अधिकतम आमदनी की सीमा में बड़ा इजाफा कर सकती है। सरकार आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना कर सकती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग ईडब्लूएस के दायरे में आ जाएंगे और इस वर्ग के लिए सरकार की योजनाओं और आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात सरकार के न्याय और अधिकारिता विभाग ने गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकनॉमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ अधिक लोगों को देने के लिए आमदनी की सीमा को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है

कि एक दशक पहले कॉर्पोरेशन के गठन के समय तय की गई सीमा में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया था और अब इसे 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने की योजना है।

कुछ ही दिनों में घोषणा कर सकती है सरकार

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि विभाग यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अनारक्षित वर्ग के लिए इस सीमा को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। आमदनी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये सालाना करने पर विचार हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले कुछ सप्ताह में ही इसकी घोषणा हो सकती है।

कुछ ही दिनों में घोषणा कर सकती है सरकार

कार्पोरेशन की अधिकतर योजनाओं में आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित है, जबकि कुछ में 8 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव का मकसद सामान्य वर्ग के लोगों को भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बराबर लाभ देना है।

ईडब्लूएस के लिए लोन में भी एक बड़ा बदलाव संभव

सरकार कार्पोरेशन के तहत संपत्ति गिरवी रखे बिना लोन देने की शुरुआत करने पर भी विचार कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए कई लोन योजनाओं में किसी भी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ईडब्लूएस को ऐसा लाभ नहीं मिलता है।

पर्यटन को ग्लोबल पहचान दिलाने का प्लान तैयार

मुंबई। राज्य के पर्यटन स्थलों को ग्लोबल पहचान दिलाने का प्लान प्रशासन ने तैयार कर लिया है। पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने पर्यटन स्थलों की प्रभावी ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए आधुनिक मार्केटिंग, डिजिटल प्रचार के नए अभियान चलाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के पर्यटन स्थलों की पहचान को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया जाना चाहिए।

बंगाल में चुनाव से पहले हुआ खेला लाखों फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट हुए थे जारी

एक्शन में शुभेंदु सरकार

ब्लिट्ज ब्यूरो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े फर्जीवाड़े के संकेत मिले हैं। चुनाव से पहले राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया हुई थी। अब इसमें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साल 2025 में अचानक बड़ी संख्या में बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उस समय ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार थी। इस असामान्य उछाल को देखते हुए बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पूरे राज्य में सघन जांच के आदेश दे दिए हैं।

पंचायत और नगर पालिकाओं से जब्त होंगे रजिस्टर

इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों से जुड़े सभी रजिस्टर जब्त कर लें। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा मेंटेन किए गए सभी रजिस्टरों को इकट्ठा किया जा रहा है। डेटा जुटाने के बाद दो से तीन दिनों में ये रजिस्टर स्थानीय निकायों को वापस कर दिए जाएंगे।

बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पूरी जांच प्रक्रिया को 'शुद्धिकरण अभियान' करार दिया है। असली और फर्जी प्रमाणपत्रों की पहचान करने के लिए अगले तीन से चार महीनों तक इस डेटा की गहराई से जांच की जाएगी।

टेस्ट चेक में सामने आया 1.8 लाख फर्जी सर्टिफिकेट का आंकड़ा

मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के मुताबिक, एक शुरुआती जांच (टेस्ट चेक) में ही भारी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट मिलने की पुष्टि हुई है। जांचे गए 46,998 'डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट' (देरी से बनवाए गए प्रमाणपत्र) में से कम से कम 11,390 फर्जी पाए गए।

वहीं, लगभग 11 लाख 24 हजार डिजिटाइज्ड सर्टिफिकेट्स की जब जांच की गई, तो उनमें से करीब 1 लाख 80 हजार प्रमाणपत्र फर्जी निकले। अकेले दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप और दार्जिलिंग के माटीगाड़ा जैसी दो जगहों पर ही 4,000 से 6,000 के बीच ऐसे संदिग्ध सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं।

अचानक कैसे बढ़ गया प्रमाणपत्रों का आंकड़ा?

सरकारी आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि साल 2025 में जन्म प्रमाणपत्र जारी होने की दर में अप्रत्याशित उछाल आया है। साल 2023 में राज्य में कुल 1,21,453 बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,81,591 पर पहुंच गया लेकिन 2025 में इसमें भारी उछाल आया और पूरे राज्य में 10,50,441 जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए।

अब सिर्फ सरकारी अधिकारियों को ही मिला अधिकार

इस बड़े फर्जीवाड़े की आशंका के बीच सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि अब से केवल अधिकृत सरकारी अधिकारी ही जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से भविष्य में जवाबदेही आसानी से तय की जा सकेगी।

इन तीन जिलों में जारी हुए सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि प्रमाणपत्र जारी होने का सबसे बड़ा आंकड़ा तीन मुस्लिम बहुल जिलों- मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में देखा गया है। गौरतलब है कि मुस्लिम बहुल जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम कटने के मामले भी असमान रूप से अधिक रहे हैं।

निवेश-रोजगार पर जोर देगी सम्राट सरकार

ब्लिट्ज ब्यूरो

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार के पहले 100 दिनों में कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए। अब सरकार का अगला चरण इन नीतियों को जमीन पर उतारने का होगा। फोकस बिहार में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कार्ययोजना तैयार की है, ताकि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

औद्योगिक, निवेश और व्यापार-अनुकूल नीतियां आने वाले समय में बड़े निवेश और रोजगार सृजन का आधार बनेंगी। बिहार को पूर्वी भारत के उभरते औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह अहम कदम है। उद्योगों को सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मजबूत किया जाएगा। लाइसेंस, एनओसी और अन्य मंजूरियां समयबद्ध तरीके से देने के साथ भूमि आवंटन और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन पर जोर रहेगा।

बिहार सरकार ने मांगा मदरसा शिक्षकों का ब्योरा

574 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ भी एक्शन

ब्लिट्ज ब्यूरो

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के मदरसा शिक्षकों का पूरा ब्योरा मांगा है। इन शिक्षकों का पूरा ब्योरा अब ई-शिक्षा कोष पर अपलोड होगा। सरकार ने राज्य के गैर सरकारी स्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूरा ब्योरा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करने को कहा है। इस संबंध में पहले दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को इस संबंध में निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि तीन दिनों के भीतर संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएं।

विशेष माध्यमिक शिक्षा निदेशक सचिन्द्र कुमार ने पत्र जारी किया है। इसके अनुसार, मदरसों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का विवरण जुटाया जाएगा। इसे एक्सल शीट में मदरसा बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद मदरसा बोर्ड इन आंकड़ों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके बाद शिक्षक व कर्मी के लिए पोर्टल पर एक विशिष्ट आइडी तैयार की जाएगी।

वक्फ संपत्तियों से हटाया जा रहा कब्जा

इधर बिहार में वक्फ की 500 से ज्यादा संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ भी एक्शन जारी है। इस बात की जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी है। राज्यसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की 63 और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 वक्फ संपत्तियों यानी कुल 574 वक्फ संपत्तियां वर्तमान में अवैध कब्जे में हैं।

इन संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यहां पर वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्यसभा में भाजपा के सांसद डॉ. भीम सिंह के प्रश्न का वह उत्तर दे रहे थे।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि इस साल 21 जुलाई तक देशभर में बिहार सहित विभिन्न राज्यों की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण यूएमईईडी केंद्रीय पोर्टल 2025 पर किया जा रहा है। जिन राज्यों में वक्फ बोर्डों ने उचित कारण बताते हुए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है, उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज अपलोड करने के लिए समय विस्तार भी दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में मिला दुर्लभ येलो पफबॉल मशरूम

वैज्ञानिक भी हैरान, स्टडी जारी

ब्लिट्ज ब्यूरो

डिब्रूगढ़। अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) की एक टीम ने जेडुआ गांव के रूटीन फील्ड विजिट के दौरान एक पीले पफबॉल मशरूम को देखा और रिकॉर्ड किया। यह जिले में इस प्रजाति को देखे जाने और रिकॉर्ड किए जाने के शुरुआती मामलों में से एक हो सकता है और अरुणाचल प्रदेश की ज्ञात फंगल विविधता में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है।

केवीके के प्लांट पैथोलॉजी एक्सपर्ट डॉ. दीप नारायण मिश्रा ने इसके खास पीले, गोले के आकार के फ्रूटिंग बॉडी और पफबॉल जैसी बनावट के आधार पर इस नमूने की पहचान शुरुआती तौर पर 'बोविस्टा कोलोराटा' के रूप में की।

पहली बार दिखा ऐसा मशरूम

डॉ. मिश्रा ने कहा कि उपलब्ध लिट्रेचर की शुरुआती समीक्षा से पता चलता है कि लोंगडिंग जिले से इस प्रजाति का कोई रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है। यह जानकारी अरुणाचल प्रदेश की ज्ञात मैक्रो-फंगल विविधता में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पक्की टैक्सोनॉमिक पुष्टि के लिए माइक्रोस्कोपिक जांच और मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन जरूरी होगा।

खूब हेल्दी होता है येलो पफबॉल मशरूम

पफबॉल मशरूम में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, जरूरी अमीनो एसिड, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और संभावित फार्मास्युटिकल गुणों वाले बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स की मौजूदगी भी दर्ज की गई है।

जहरीला भी हो सकता है

इतिहास में, पफबॉल स्पोर का इस्तेमाल कुछ पारंपरिक संस्कृतियों में घाव पर लगाने के लिए प्राकृतिक मैटीरियल के तौर पर किया जाता रहा है, क्योंकि इनमें नमी सोखने और खून का थक्का जमाने के गुण होते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि जंगली मशरूम को कभी भी एक्सपर्ट की सही पहचान के बिना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कच्ची जहरीली किस्में खाने योग्य पफबॉल जैसी ही दिख सकती हैं।

600 करोड़ घोटाले के आरोपी आईएएस को मलाईदार पोस्ट पर रखा, हाई कोर्ट नाराज

अदालत ने कांग्रेस सरकार से मांगा जवाब

ब्लिट्ज ब्यूरो

कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार ने काजू विकास निगम के कथित 600 करोड़ रुपए के घोटाले में मुकदमे का सामना कर रहे एक सीनियर नौकरशाह को अहम सरकारी पदों पर बनाए रखा था। कोर्ट ने सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में आरोपी अधिकारी को महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता केएम शाहजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए. बदहर की बेंच ने सरकार को चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

बेंच ने सीबीआई केस के मुख्य आरोपी डॉ. केए रतीश के केरल खादी बोर्ड के सेक्रेटरी, केरल स्टेट रुड्रोनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और केरल खादी वर्कर्स वेलफेयर

फंड बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर बने रहने पर गंभीर चिंता जताई।

अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, 'क्या सरकार ने भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोपी को तीन महत्वपूर्ण संस्थानों का प्रमुख नियुक्त किया है?' साथ ही यह भी कहा कि इन पदों पर भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि रतीश पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि आपराधिक मुकदमा लंबित होने के बावजूद ऐसी नियुक्तियां कैसे उचित थीं।

विजिलेंस जांच के दौरान भी 11 साल तक रहे एमडी

याचिका में बताया गया है कि सीबीआई केस में सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद भी रतीश अपने पदों पर बने हुए हैं। यह मामला केरल राज्य काजू विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान काजू के आयात में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कंपनीज एक्ट के नियमों के उलट जरूरी विजिलेंस मंजूरी न होने के बावजूद 11 साल से ज्यादा समय तक पब्लिक सेक्टर कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया है।

काजू आयात घोटले का क्या मामला

हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब भ्रष्टाचार के आरोपों और बार-बार अदालती दखल के बावजूद अलग-अलग सरकारों द्वारा रतीश को सार्वजनिक क्षेत्र के अहम पदों पर बनाए रखने को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई का यह मामला कथित तौर पर 600 करोड़ रुपए के काजू आयात घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रतीश मुख्य आरोपी हैं। सरकारी कंपनियों में अपने कार्यकाल के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के अन्य आरोप भी लगे हैं।

कुंभ वायरल गर्ल को सुरक्षा दे पुलिसः हाईकोर्ट

कोच्चि। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चित मोनालिसा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केरल हाईकोर्ट ने मोनालिसा को एक बार फिर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। मोनालिसा ने दावा किया है कि अलग-अलग समूहों के लोग उसका लगातार पीछा कर रहे हैं और वह जहां भी जाती है, वहां की जानकारी प्रसारित कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को उसे पुलिस सुरक्षा देने वाले अपने पुराने आदेश को रद कर दिया था, जब पुलिस की ओर से यह सूचित किया गया कि उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जब भी लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस से संपर्क करे, उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

हाईकोर्ट में क्यों की सुरक्षा की गुहार?

लड़की के वकील पीएस अनीशाद ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पलारीवट्टोम थाने के थाना प्रभारी को पक्षकार बनाया और निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक लड़की को पुलिस सुरक्षा दी जाए। इसके बाद युवती ने पलारीवट्टोम थाने में आवेदन देकर अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई।

थलपति विजय की शराब नीति विपक्ष के निशाने पर

तमिलनाडु में 23 साल बाद शराब की बिक्री प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की अटकलें

ब्लिट्ज ब्यूरो

चेन्नई। तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार राज्य में 23 साल बाद शराब की बिक्री प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है। ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कषगम(टीवीके) सरकार, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में 'तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन' (तस्मैक) के शराब आउटलेट्स के प्राइवेटाइजेशन पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 2003 के बाद से तमिलनाडु में शराब की प्राइवेट रिटेल बिक्री की दिशा में यह पहला बड़ा बदलाव होगा। 2003 में एआईएडीएमके सरकार ने शराब की बिक्री को निजी कंपनियों को सौंप दिया था।

प्रस्ताव से सरकार का इनकार

हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ऐसी चर्चाएं हैं कि इस कदम का रास्ता साफ करने वाला कानून विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि विजय सरकार तस्मैक के कामकाज का प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी कर रही है। उनका तर्क है कि इस कदम से शराब की खपत बढ़ेगी। न कि शराबबंदी के लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।

अंबुमणि रामदास ने कड़ी आलोचना की

इस कथित प्रस्ताव की 'पट्टली मक्कल काची' (पीएमके) के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी शराब आउटलेट्स का प्राइवेटाइजेशन करने से शराब की खपत और बढ़ेगी और शराबबंदी का मकसद कमजोर होगा। एक बयान में अंबुमणि ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र किया जिनमें दावा किया गया है कि तमिलनाडु के 4048 तस्मैक आउटलेट्स में से लगभग 2500 आउटलेट्स प्राइवेट ऑपरेटर्स को सौंपे जा सकते हैं जो कि ज्यादातर शहरी इलाकों में हैं।

क्या बोले अंबुमणि रामदास?

उन्होंने तर्क दिया कि राज्य का ध्यान प्राइवेटाइजेशन के बजाय शराब की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और अंततः पूरी तरह शराबबंदी लागू करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का शराब की बिक्री में शामिल होना वाकई शर्मनाक है। हालांकि, इसका समाधान सभी शराब की दुकानों को बंद करना और पूरी तरह शराबबंदी लागू करना है। न कि शराब की रिटेल बिक्री प्राइवेट कंपनियों को सौंपना।

थलपति विजय ने आम यात्रियों की तरह किया मेट्रो का सफर

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने गत दिवस चेन्नई मेट्रो रेल के फेज-1 और फेज-2 परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों, परिचालन तैयारियों और भविष्य में प्रस्तावित विस्तार योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विजय ने अपना निरीक्षण गवर्नमेंट एस्टेट मेट्रो स्टेशन से नंदनम मेट्रो स्टेशन तक यात्रा कर शुरू किया। उन्होंने आम यात्रियों की तरह टिकट खरीदकर मेट्रो में सफर किया।

इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और उनके साथ सेल्फी भी ली। सीएम का यह अंदाज देख मेट्रो में सफर कर रहे लोग हैरान हो गए। इस दौरान उनके साथ वित्त, योजना एवं विकास मंत्री एन मैरी विल्सन, अलंदुर के विधायक एम.हरीश, मदुरवोयल के विधायक पी रेवंत चरण, मुख्य सचिव एम साईकुमार तथा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नंदनम स्थित चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। यहां उन्होंने ट्रेन संचालन की निगरानी, कंट्रोल सिस्टम और परिचालन व्यवस्था की समीक्षा की।

हरे-भरे जंगल और झरने: वो ट्रेनें जहां घंटों खिड़की पर थमती है नजर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और ट्रेन की खिड़की से बाहर खूबसूरत नजारों को घंटों निहारना पसंद करते हैं, तो साउथ इंडिया की कुछ रेल यात्राएं आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होंगी। यहां के रेल मार्ग घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, चाय बागानों, समुद्र तटों और शांत गांवों के बीच से गुजरते हैं। खास बात यह है कि इन रास्तों में कई ऐसे ट्रैक भी शामिल हैं जिन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत रेल मार्गों में गिना जाता है। कभी मौका मिले तो जरूर एक्सपीरियंस लें इन रेल यात्राओं का।

चेन्नई से रामेश्वरमः समुद्र के बीच से गुजरती ट्रेन

चेन्नई से रामेश्वरम तक का सफर भारत की सबसे अनोखी ट्रेन यात्राओं में शामिल है। इस मार्ग की सबसे बड़ी खासियत ऐतिहासिक पंबन रेल ब्रिज है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो दोनों ओर फैला नीला समुद्र दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो ट्रेन पानी के ऊपर चल रही हो। यह सफर धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का शानदार मेल है।

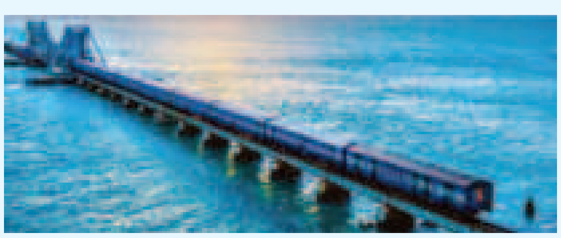

कोच्चि से कन्नूरः केरल की प्राकृतिक खूबसूरती

कोच्चि से कन्नूर तक की यात्रा भले ही ज्यादा लंबी न हो, लेकिन रास्ते में दिखने वाले नजारे मन मोह लेते हैं। नारियल के पेड़, हरे-भरे धान के खेत, शांत बैकवॉटर, छोटी नदियां और गांव इस सफर को बेहद खास बना देते हैं। मानसून के मौसम में यहां की हरियाली और भी खूबसूरत दिखाई देती है।

नीलगिरि माउंटेनः यह भारत की सबसे प्रसिद्ध ट्रेन यात्राओं में गिनी जाती है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल यह टॉय ट्रेन धीरे-धीरे पहाड़ियों की ओर बढ़ती है और यात्रियों को चाय के बागानों, घने जंगलों, झरनों, 16 सुरंगों और 250 से अधिक पुलों से होकर ले जाती है। ऊटी पहुंचते-पहुंचते मौसम भी सुहावना हो जाता है।

बेंगलुरु से गोकर्ण तक का सफर प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार अनुभव साबित हो सकता है। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों से होती है और आगे बढ़ते हुए कॉफी के बागान, नदियां, जंगल और घाटियां दिखाई देती हैं। गोकर्ण के पास पहुंचते ही समुद्र तटों के खूबसूरत नजारे मन मोह लेते हैं।

वर्कला से कन्याकुमारीः तीन समुद्रों का अद्भुत संगम

वर्कला से कन्याकुमारी तक का रेल सफर केरल और तमिलनाडु की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का मौका देता है। रास्ते में नारियल के पेड़ों की कतारें, गांव और ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है। कन्याकुमारी पहुंचने पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम इस यात्रा को और भी यादगार बना देता है।

भारत के पावर सेक्टर का नया दौर

भारत के पावर सेक्टर में 2026 ऊर्जा भंडारण के लिहाज से एक निर्णायक साल बनकर उभर रहा है, जहां सरकारी नीतियां, तकनीक और बढ़ती मांग एक साथ आ रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा के बढ़ते विस्तार के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस), बैकअप पावर और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव भारत के पावर ग्रिड को अधिक भरोसेमंद बनाने के साथ घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में नए निवेश के लिए भी बड़ा अवसर पैदा कर रहा है।

2026 ऊर्जा भंडारण में निर्णायक वर्ष

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250.52 गीगावाट हो गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 55.3 गीगावाट की नई गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई।

जुलाई 2025 में पहली बार कुल बिजली मांग को पूरा करने में 51.5 प्रतिशत हिस्सेदारी नवीकरणीय ऊर्जा की रही। वहीं, कुल बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 29.2 प्रतिशत रही। भारत ने 2025 में ही 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर ली, जो कि 2030 का लक्ष्य था।

सरकार 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रही है। भारत इसी वर्ष वार्षिक इंस्टॉलेशन के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनने की ओर बढ़ रहा है। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन के अनुसार, देश ने 14 महीनों में 50 गीगावाट सौर क्षमता जोड़कर 150 गीगावाट का आंकड़ा छू लिया है। पहले 50 गीगावाट तक पहुंचने में 11 साल लगे थे, जबकि 100 गीगावाट क्षमता तीन साल में हासिल हुई। मौजूदा गति से भारत हर साल करीब 50 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ रहा है।

इस रफ्तार से 2030 तक 300 गीगावाट सौर क्षमता हासिल कर 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पूरा करने की संभावना है।

सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज से मिल सकती है 90% बिजली

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, सौर ऊर्जा और सस्ती बैटरी स्टोरेज के जरिए भारत अपनी 90 प्रतिशत बिजली की जरूरत कम लागत में पूरी कर सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि यह मौजूदा बिजली दरों से भी सस्ता हो सकता है।

कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी

तमिलनाडु के कल्पक्कम में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसके साथ ही देश ने अपनी तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा योजना के दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस रिएक्टर में परमाणु विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई है, जिससे ऊर्जा उत्पादन संभव होगा। यह तकनीक जितना ईंधन खर्च करती है, उससे अधिक ईंधन उत्पन्न करती है।

रिएक्टर के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक व्यावसायिक संचालन में आने की उम्मीद है। यह उपलब्धि भारत के थोरियम भंडार के उपयोग और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार 100 गीगावॉट के पार पहुंचा सौर व पवन बिजली उत्पादन

देश की कुल बिजली आपूर्ति में हिस्सेदारी 42.79 प्रतिशत तक पहुंची

नई दिल्ली। भारत की बिजली व्यवस्था ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो कुछ साल पहले तक मुश्किल माना जाता था। 13 और 14 जुलाई को पहली बार देश में सौर और पवन ऊर्जा, यानी वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी (वीआरई), का उत्पादन 100 गीगावॉट के पार पहुंच गया। इतना ही नहीं, इन दोनों स्रोतों की हिस्सेदारी देश की कुल बिजली आपूर्ति में 42.79 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। 13 जुलाई को दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर सौर और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन 103.7 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। इससे एक दिन पहले शाम के समय पवन ऊर्जा उत्पादन भी 36.6 गीगावॉट के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर दर्ज किया गया।

यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इस साल भीषण गर्मी, लंबे हीटवेव और एयर कंडीशनर समेत शीतलन उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण देश की बिजली मांग दो बार 270 गीगावॉट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची लेकिन इस बढ़ती मांग के बीच रिन्यूएबल एनर्जी ने भी पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाई। 25 अप्रैल को जब बिजली मांग 270 गीगावॉट तक पहुंची, तब सौर ऊर्जा ने पीक डिमांड के दौरान 57 गीगावॉट और दोपहर में 81 गीगावॉट बिजली उपलब्ध कराई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था।

रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से अब तक कुल बिजली आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 35 से 42 प्रतिशत के बीच रही है। अगर जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा को भी शामिल कर लिया जाए, तो गैर-फॉसिल फ्यूल स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। भारत के लिए यह रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऐतिहासिक वर्ष है। उनके मुताबिक देश का बिजली ग्रिड अब 100 गीगावॉट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी को बिना किसी बड़ी बाधा के संभालने में सक्षम साबित हुआ है। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में जैसे-जैसे नई परियोजनाएं जुड़ेंगी, बिजली आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। हालांकि इसके लिए ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाना पहले से कहीं अधिक जरूरी होगा, ताकि चौबीसों घंटे स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराई जा सके।

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रह्मण्यम पुलिपाका के मुताबिक यह उपलब्धि कई वर्षों के निवेश, ट्रांसमिशन नेटवर्क, बिजली पूर्वानुमान और ग्रिड संचालन में हुए सुधारों का परिणाम है। उनका कहना है कि अब अगला चरण ऊर्जा भंडारण, ग्रिड की लचीलापन क्षमता, ट्रांसमिशन नेटवर्क और बिजली बाजार में सुधार पर केंद्रित होगा।

ऊर्जा विश्लेषण संस्था एंबर के वरिष्ठ ऊर्जा विश्लेषक नेशविन रोड्रिग्स इसे भारत की बिजली व्यवस्था में एक संरचनात्मक बदलाव मानते हैं। उनके अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी अब पारंपरिक बिजली उत्पादन की पूरक नहीं रह गई है, बल्कि देश की बढ़ती बिजली मांग पूरी करने का प्रमुख स्रोत बनती जा रही है।

हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि अब ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन और ग्रिड लचीलेपन पर तेजी से निवेश करना होगा, ताकि कम लागत वाली रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा उपयोग हो सके।

यह उपलब्धि दिखाती है कि यदि नीतियां ग्रिड संचालन की चुनौतियों का समाधान करती रहें, तो वह समय दूर नहीं जब भारत अपनी अधिकांश दैनिक बिजली जरूरत रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी कर सकेगा। हालांकि इसके साथ ऊर्जा भंडारण और स्वच्छ ऊर्जा उपकरणों से निकलने वाले कचरे के पुनर्चक्रण पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

यह सिर्फ नई क्षमता जोड़ने की नहीं, बल्कि वास्तविक बिजली आपूर्ति में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी का संकेत है। उनके मुताबिक अब अगली चुनौती बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण, अधिक लचीले ग्रिड और ऐसे बिजली बाजार विकसित करने की है, जो शाम के समय बढ़ने वाली मांग को भी स्वच्छ ऊर्जा से पूरा कर सकें।

यह रिकॉर्ड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अर्थशास्त्र यह दिखाता है कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी अब भविष्य की तकनीक नहीं रही। वह तेजी से देश की रोजमर्रा की बिजली जरूरतों का अहम आधार बनती जा रही है। अब अगली परीक्षा यह होगी कि इस बढ़ती स्वच्छ बिजली को हर मौसम, हर घंटे और हर राज्य तक भरोसेमंद तरीके से कैसे पहुंचाया जाए।

ब्लिट्ज ब्यूरो

युद्ध से मुनाफे की बारिश

ईरान संघर्ष के बीच तेल कंपनियों का मुनाफा ऐतिहासिक ऊंचाई पर

ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार का पूरा गणित बदल दिया है। पेट्रोलियम आपूर्ति बाधित होने से दुनिया भर में ईन्धन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और कई देशों में इसकी कमी भी महसूस की जा रही है। एक ओर आम उपभोक्ता महंगे ईन्धन और बढ़ती महंगाई का बोझ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया की कुछ बड़ी तेल कंपनियों के लिए यही संकट भारी मुनाफे का अवसर बन गया है।

बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रमुख तेल कंपनियां इस अवधि में असाधारण मुनाफा दर्ज कर सकती हैं। वैश्विक आपूर्ति में कमी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने इन कंपनियों को अपने उत्पाद अधिक दाम पर बेचने का अवसर दिया है।

हॉर्मुज में रुकावट, दुनिया भर में असर

छठे महीने में प्रवेश कर चुके ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला अधिकांश समुद्री परिवहन प्रभावित हुआ है। यह संकरा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का प्रमुख रास्ता रहा है।

एक विशेष मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आपूर्ति सीमित होने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रमुख मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च, अप्रैल और मई के अधिकांश समय में 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। एक समय यह कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का सीधा फायदा उन बड़ी तेल कंपनियों को मिला, जो वैश्विक बाजार में अपना उत्पाद अधिक कीमत पर बेचने की स्थिति में थीं।

आम उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के साथ पेट्रोल, डीजल और विमान ईन्धन भी महंगे हो गए। इसका सीधा असर वाहन चालकों से लेकर हवाई यात्रियों तक की जेब पर पड़ा।

कुछ देशों में ईन्धन की आपूर्ति इतनी कम हो गई कि सरकारों को नियंत्रण और राशनिंग जैसे कदम उठाने पड़े। ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में समय-समय पर ईन्धन की राशनिंग करनी पड़ी जबकि नेपाल और श्रीलंका में सरकारी कार्यालय बंद रखने तक की नौबत आ गई।

इस तरह दुनिया के कई हिस्सों में आम लोग ऊंची कीमतों और ईन्धन की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ बड़ी ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

छह यूरोपीय कंपनियों को 22 अरब डॉलर का मुनाफा

पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था 'ग्लोबल विटनेस' के मुताबिक, यूरोप की छह सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने वर्ष की पहली तिमाही में मिलकर करीब 22 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 43 प्रतिशत अधिक है।

'ग्लोबल विटनेस' में जीवाश्म ईन्धन मामलों के प्रमुख पैट्रिक गैली का कहना है, "दुनिया में कुछ वर्गों के लिए यह संकट बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है और तेल उत्पादक उनमें से एक हैं।"

उनके मुताबिक, एक तरफ तेल उत्पादक ऊंची कीमतों का लाभ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में करोड़ों लोग लगातार बिजली कटौती, बिजली की खपत पर पाबंदियों, ईन्धन की राशनिंग और खाद्य पदार्थों की कमी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं।

उर्वरकों की आपूर्ति में बाधा से खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऊर्जा संकट की इतनी बड़ी कीमत आखिर दुनिया के आम लोगों को क्यों चुकानी पड़े।

रिफाइनरियों के लिए बड़ा मौका

मौजूदा बाजार परिस्थितियों में एक्सॉन और शेवरॉन जैसी बड़ी ऊर्जा कंपनियां सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देती हैं। इसकी वजह यह है कि ये कंपनियां केवल तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन ही नहीं करतीं, बल्कि अपनी रिफाइनरियां भी संचालित करती हैं।

रिफाइनरियों में कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, विमान ईन्धन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में बदला जाता है। इस समय रिफाइनरियों को ऐतिहासिक रूप से ऊंचे 'क्रैक स्प्रेड' का फायदा मिल रहा है।

सरल शब्दों में कहें तो कच्चे तेल की खरीद कीमत और उससे तैयार पेट्रोल, डीजल तथा विमान ईन्धन जैसे उत्पादों की बिक्री कीमत के बीच का अंतर रिफाइनरी की संभावित कमाई को दर्शाता है।

जुलाई के अंत में करीब 80 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदने वाली कुछ रिफाइनरियों को प्रति बैरल 50 से 60 डॉलर तक की संभावित कमाई दिखाई दे रही थी। सामान्य परिस्थितियों में यह अंतर करीब 20 से 25 डॉलर प्रति बैरल रहता है। यानी मौजूदा परिस्थितियों में रिफाइनरियों का संभावित मुनाफा सामान्य स्तर से कहीं अधिक हो गया है।

> **तेल उत्पादक ऊंची कीमतों का लाभ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में करोड़ों लोग लगातार बिजली कटौती, ईन्धन की राशनिंग जैसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं**

अमेरिकी रिफाइनरियां फायदे की स्थिति में

जिन रिफाइनरियों के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध है, खासकर अमेरिकी रिफाइनरियां, वे मौजूदा हालात का सबसे अधिक लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

डीजल और विमान ईन्धन के उत्पादन में मुनाफे की संभावना विशेष रूप से बढ़ी है। अमेरिका में इन ईन्धनों की कीमतें हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अवरोध पैदा होने से पहले के मुकाबले करीब 41 प्रतिशत अधिक हैं।

अमेरिकी रिफाइनरियां फिलहाल लगभग अपनी पूरी उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रही हैं। दूसरी ओर, मध्य पूर्व और रूस की कुछ रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि एशिया की कई रिफाइनरियों को मध्य पूर्व से पहले जितना कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है। इस बदलते हुए वैश्विक समीकरण ने अमेरिकी रिफाइनरियों को और मजबूत स्थिति में ला दिया है।

किसी के लिए संकट, किसी के लिए अवसर

वैश्विक ऊर्जा संकट ने दुनिया के सामने एक बड़ा विरोधाभास खड़ा कर दिया है। एक ओर आम उपभोक्ता महंगे पेट्रोल-डीजल, बढ़ते परिवहन खर्च और ईन्धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर पर्याप्त कच्चे तेल की उपलब्धता वाली कुछ बड़ी तेल कंपनियों और रिफाइनरियों के लिए यही संकट असाधारण कमाई का अवसर बन गया है।

युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव से पैदा हुए ये हालात एक बार फिर बताते हैं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी संकट की कीमत सभी को समान रूप से नहीं चुकानी पड़ती। किसी के हिस्से में महंगाई, अभाव और अनिश्चितता आती है, तो किसी के हिस्से में उसी संकट से अप्रत्याशित मुनाफा।

कौन फायदे में, कौन नुकसान में?

मध्य पूर्व की कई ऊर्जा कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और प्राकृतिक गैस की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा लाभ नहीं उठा पा रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें फारस की खाड़ी से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निर्यात में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई कंपनियों के तेल क्षेत्र और तेल उत्पादन एवं प्रसंस्करण संयंत्र भी संघर्ष और हमलों के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं।

बदले हुए हालात में मध्य पूर्व की ऊर्जा कंपनियों के लिए ऊंची कीमतों से लाभ कमाने की तुलना में उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बनाए रखना कहीं बड़ी चुनौती बन गया है।

अमेरिका की टेनेसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और पेट्रोलियम उद्योग के विशेषज्ञ टिमोथी फिट्जगेराल्ड के अनुसार, मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ कंपनियों को खासा फायदा हो रहा है, जबकि कई अन्य कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

फिट्जगेराल्ड कहते हैं, "जब बाजार में अपना उत्पाद बेचने और उसकी पर्याप्त मात्रा पहुंचाने की आपकी क्षमता सीमित हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से आमदनी में भारी गिरावट आती है। दूसरी ओर परिवहन और सुरक्षा से जुड़ी लागत लगातार बढ़ती जाती है, जिससे कंपनियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है।"

फिट्जगेराल्ड के मुताबिक, एक्सॉन और शेवरॉन जैसी वैश्विक तेल कंपनियां भी वर्ष की पहली तिमाही में अपेक्षित मुनाफा नहीं कमा सकीं। इसकी मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कारोबार की प्रक्रिया थी, जिसके चलते बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उन्हें तत्काल नहीं मिल पाया।

उनके अनुसार, इन कंपनियों को तेल की ऊंची कीमतों का वास्तविक लाभ उठाने का पहला अवसर अप्रैल से मिलना शुरू हुआ। पूरी स्थिति यह बताती है कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के दौर में केवल तेल की ऊंची कीमतें ही अधिक मुनाफे की गारंटी नहीं हैं।

उत्पादन, आपूर्ति, परिवहन और सुरक्षा जैसे कारक भी अब ऊर्जा कंपनियों का नफा-नुकसान तय करने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए सरकार व इंडस्ट्री आए साथ

ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन एक नए दौर में, ग्लोबल लीडर बनने की ओर भारत

भारत में ग्रीन हाइड्रोजन अब भविष्य का विचार नहीं है; यह तेज़ी से बढ़ता हुआ आर्थिक अवसर बन रहा है। कॉमर्शियल-स्केल प्रोडक्शन से लेकर हाल ही में शुरू की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन तक, हमारी प्रगति उन क्षमताओं के दायरे को दर्शाती है

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने सरकारों, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडेमिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल पार्टनर्स से देश में ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।

फिक्की द्वारा आयोजित 'भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026' के दूसरे एडिशन में बोलते हुए, नए और रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री ने कहा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।नाइक ने कहा, आज सवाल यह नहीं है कि क्या ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन का आधार बनेगा, बल्कि यह है कि कौन से देश इस बदलाव का नेतृत्व करेंगे। हाइड्रोजन इकॉनमी में ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरने के लिए भारत की स्थिति अनोखी है।

उन्होंने कहा, आइए हम 'मेड-इन-इंडिया' ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ का दुनिया का भरोसेमंद प्रतीक बनाने के लिए मिलकर काम करें।

नाइक ने आगे कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ने एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार इकोसिस्टम बनाया है।

प्रोडक्शन इंसेंटिव, देश में

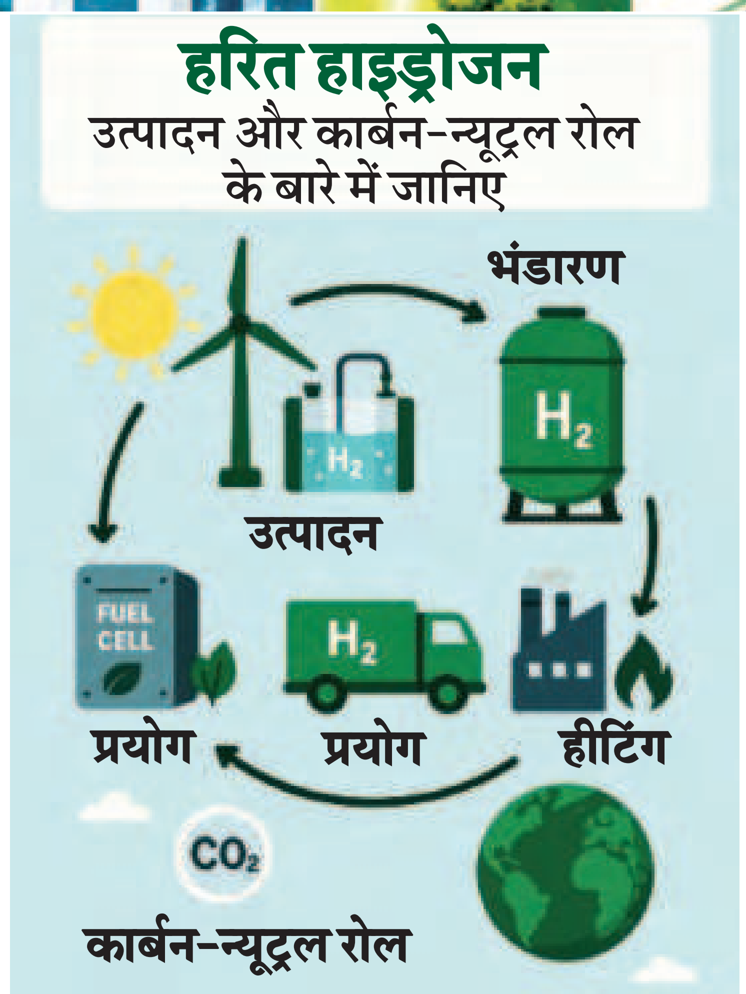

इलेक्ट्रोलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरियों और फर्टिलाइज़र में डिमांड पैदा करना, मोबिलिटी, शिपिंग और स्टील में पायलट प्रोजेक्ट्स और एक सक्षम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पॉलिसी के इरादे को कमर्शियल हकीकत में बदल रहे हैं।

उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन अब भविष्य का विचार नहीं है; यह तेज़ी से बढ़ता हुआ आर्थिक अवसर बन रहा है। कॉमर्शियल-स्केल प्रोडक्शन से लेकर हाल ही में शुरू की गई भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन तक, हमारी प्रगति उन क्षमताओं के दायरे को दर्शाती है जिनकी भारत को ग्लोबल हाइड्रोजन हब के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरत है।

नाइक ने आगे कहा कि ग्लोबल

आइए हम 'मेड-इन-इंडिया' ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ का दुनिया का भरोसेमंद प्रतीक बनाने के लिए मिलकर काम करें।

हाइड्रोजन हब बनने के लिए सिर्फ़ प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा की जरूरत होगी।

इसके लिए इनोवेशन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मज़बूत सप्लाई चेन, इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार्य स्टैंडर्ड्स, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और लंबे समय तक चलने वाली ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि सरकारों, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडेमिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल पार्टनर्स को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

इस कार्यक्रम में गुजरात के ऊर्जा राज्य मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल ने कहा कि उनका राज्य भारत का 'ग्रीन हाइड्रोजन ग्रोथ इंजन' बनने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के भरपूर स्रोतों, विश्व-स्तरीय बंदरगाहों, मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे और एक प्रगतिशील ग्रीन हाइड्रोजन नीति के साथ, यह राज्य उत्पादन, नवाचार और निर्यात के लिए एक एकीकृत इकोसिस्टम प्रदान करता है।

उन्होंने उद्योग जगत को भी आमंत्रित किया कि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने में गुजरात के साथ साझेदारी करें।

भारत में कनाडा के उच्चायोग में कॉमर्शियल मामलों के मंत्री एड जैगर ने कहा कि भारत का वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने का लक्ष्य विश्वसनीय और हासिल करने योग्य है।

फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाजार का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हासिल करना है।

उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए हम विश्व-स्तरीय निर्यात बुनियादी ढांचा बनाने, भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में काम कर रहे देशों के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदार बनने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

इस कार्यक्रम के दौरान फिक्की-ईवाई की रिपोर्ट 'टुवर्ड्स ए ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी: इंडियाज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक' जारी की गई, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े उत्पादों के विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनने के लिए भारत के रोडमैप पर प्रकाश डाला गया है।

जिंदल स्टेनलेस ने हाइड्रोजन ट्रेन के लिए दिया 40 प्रतिशत स्टील

- पर्यावरण अनुकूल परिवहन में भारतीय रेलवे का बड़ा कदम
- वंदे भारत और मेट्रो के लिए भी की आपूर्ति
- कंपनी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में दे रही योगदान

ब्लिट्ज ब्यूरो

हिसार। स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी जिंदल स्टेनलेस ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली ट्रेन के लिए कुल स्टेनलेस स्टील का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराया है।

जिंदल स्टेनलेस के ओडिसा के जाजपुर और हिसार संयंत्रों से विशेष रूप से आपूर्ति किए गए प्रीमियम आस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील ग्रेड एक्स5सीआरएनआई 1810 का इस्तेमाल इस हाइड्रोजन ट्रेन के निर्माण में किया गया है।

हाइड्रोजन प्रणोदन प्रणाली से लैस यह ट्रेन पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन अपनाने की भारतीय रेलवे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिंदल स्टेनलेस के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन में योगदान देना हमारे लिए गर्व की बात है। यह देश की स्वच्छ परिवहन व्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। जिंदल स्टेनलेस पिछले तीन दशकों से भारतीय रेलवे को स्टेनलेस स्टील की आपूर्ति कर रही है। कंपनी ने पहले एलएचबी कोच, वंदे भारत स्लीपर, भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन सहित कई मेट्रो और इंटरसिटी ट्रेनों जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्टेनलेस स्टील उपलब्ध कराया है।

हाइड्रोजन वाहनों से जुड़े 12 पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

दी जाएगी 410.77 करोड़ की सहायता

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। संसद को विगत दिवस बताया गया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) के तहत 70 हाइड्रोजन संचालित वाहनों को तैनात करने के लिए कुल 12 पायलट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 410.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में 27 बसें और 43 ट्रक शामिल हैं - जिनमें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) और हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन (एच2-आईसीई) वाहन शामिल हैं - साथ ही अलग-अलग राज्यों में 21 रूटों पर 16 हाइड्रोजन रीफ्यूलिंग स्टेशन (एचआरएस) भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए कुल आवंटित वित्तीय सहायता लगभग 410.77 करोड़ रुपये है, जिसमें से 41.582 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,

ये पायलट प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स+ आईओसीएल, आर आईएल +एएल, एचपीसीएल+वोल्वो, एनटीपीसी-जीईएल जैसी निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं।

एक अलग जवाब में, नाइक ने यह भी कहा कि इस मिशन के तहत, उर्वरक निर्माण को ग्रीन अमोनिया की खपत के लिए एक संभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, और इसी के अनुसार, उर्वरक विभाग ने पूरे भारत में 13 उर्वरक इकाइयों को आपूर्ति के लिए प्रति वर्ष 7.24 लाख टन ग्रीन अमोनिया की मांग का आकलन किया है।

एनजीएचएम के तहत, ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु योजना के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस स्कीम के तहत, ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन और सप्लाई के पहले साल में ₹8.82 प्रति किलोग्राम, दूसरे साल में ₹7.06 प्रति किलोग्राम और तीसरे साल में ₹5.30 प्रति किलोग्राम।

'मिशन ग्रीन हाइड्रोजन' के लिए भेल ने थिसेनक्रुप नुसेरा इंडिया से किया सहयोग

नई दिल्ली। सरकारी इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) ने कहा है कि उसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम के स्वदेशीकरण और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए थिसेनक्रुप नुसेरा इंडिया के साथ सहयोग किया है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि यह रणनीतिक साझेदारी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम के चरणबद्ध स्वदेशीकरण और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को संभव बनाएगी।

इसमें आगे कहा गया है कि यह सहयोग भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए भेल की प्रोजेक्ट पूरा करने की क्षमताओं को और मजबूत करेगा।

कंपनी ने फाइलिंग में कहा कि इससे 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' में भेल का योगदान भी बढ़ेगा और सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन मिलेगा।

सभी शादीशुदा बेटियां दया के आधार पर नौकरी देने की नीति में शामिल

ब्लिट्ज ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार सरकार की शर्त असंवैधानिक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति के आधार पर नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई विवाहित बेटियों को नौकरी के लिए पात्र मानना गलत है। अन्य विवाहित बेटियों को इससे बाहर रखना संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने बिहार सरकार की 10 दिसंबर 2014 की नीति की संबंधित शर्त को असंवैधानिक करार दिया।

'बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं किया जा सकता'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले भी कई मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि बेटे और बेटी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के विपरीत है। अदालत ने कहा कि करुणामूलक नियुक्ति के लिए केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को पात्र मानना और अन्य विवाहित बेटियों को बाहर रखना कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकता।

'शादी के बाद बेटी का मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता'

राज्य सरकार की इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि विवाह के बाद बेटी सामान्यतः अपने ससुराल चली जाती है। अदालत ने कहा कि कानून में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि शादी के बाद बेटी का अपने मायके या माता-पिता से संबंध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसलिए केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसे करुणामूलक नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

पिता की मौत के बाद नौकरी का दावा हुआ था खारिज

यह मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा था, जिसके पिता बिहार सरकार में कर्मचारी थे। पिता के निधन के बाद महिला ने करुणामूलक नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वह न तो तलाकशुदा है और न ही परित्यक्ता। इसके अलावा महिला के चाचा की ओर से कथित आपत्ति का भी हवाला दिया गया था। बाद में चाचा ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया था।

तकनीकी आधार पर दावा ठुकराना गलत

महिला की ओर से अदालत को बताया गया कि भले ही उसका तलाक कानूनी रूप से अंतिम रूप नहीं ले पाया हो, लेकिन वह अपने मायके में रह रही है और उसकी मां व भाई उसका सहारा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अत्यधिक तकनीकी (हाइपर टेक्निकल) दृष्टिकोण अपनाकर किसी पात्र व्यक्ति के दावे पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि चाचा की आपत्ति का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले और राज्य सरकार द्वारा महिला का आवेदन खारिज करने के आदेश को रद कर दिया। साथ ही बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला के करुणामूलक नियुक्ति के दावे पर सभी तथ्यों और योग्यता के आधार पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर उचित कार्रवाई करे।

आवारा पशुओं से हादसों पर मिलेगा मुआवजा

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने ऐसे हादसों पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने और आवारा पशुओं से संबंधित कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने सरकारों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम और मुआवजा व्यवस्था के लिए ठोस नीति बनाने को कहा है। दूरगामी प्रभाव वाला यह फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब के एक मामले में दिया है।

पर्यावरण संबंधी मंजूरी के बाद ही शुरू होंगी नई परियोजनाएं

राजेश दुबे

नई दिल्ली। विकास और पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गत दिवस एक अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भविष्य में किसी भी नई परियोजना को शुरू करने से पहले ही पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी। काम शुरू होने के बाद मंजूरी नहीं मिलेगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि यह फैसला केवल आगे से लागू होगा। पहले पर्यावरणीय मंजूरी पा चुकी परियोजनाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी।

इसके साथ ही पीठ ने वर्ष 2021 के उस सरकारी आदेश को रद कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को परियोजनाओं को काम होने के बाद या परियोजनाओं की समाप्ति के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देने का अधिकार दिया गया था।

पीठ ने कुल 49 याचिकाओं पर अपना यह फैसला सुनाया है। ये याचिकाएं उन परियोजनाओं से जुड़ी थीं। जिन्होंने पर्यावरण के नियम तोड़े थे और उन्हें बाद में मंजूरी दी गई थी।

केंद्र सरकार के वर्ष 2021 के आदेश के तहत कंपनियां बिना पर्यावरण मंजूरी के भी अपनी परियोजना शुरू कर सकती थीं और बाद में सरकार से मंजूरी ले लेती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस 2021 वाले आदेश को पूरी तरह खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद माफी मांगने की यह व्यवस्था गलत है। आगे से कोई भी कंपनी बिना पहले इजाजत लिए अपना काम शुरू नहीं कर पाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में 10000 मामले 10 साल से और हाई कोर्ट में 80000 केस 30 साल से लंबित

कई कारण गिनाए कानून मंत्री मेघवाल ने

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। साल 2011 से अब तक कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर 9800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन दशकों से लंबित मामलों के निपटारे पर इसका बहुत कम असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से ज्यादा मामले 10 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं।

इनमें 558 मामले 20 साल से ज्यादा और 26 मामले 30 साल से लंबित हैं। देश भर के 25 हाई कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले तीन दशकों से ज्यादा समय से लंबित हैं। पिछले हफ्ते संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मामलों के निपटारे की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डाली, जिसने इनके निपटारे के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है।

निपटारा कई बातों पर निर्भर करता है

उन्होंने आगे कहा कि अदालतों में मामलों का समय पर निपटारा कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें जजों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, कोर्ट का सहयोगी स्टाफ और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता; मामले के तथ्यों की जटिलता; सबूतों की प्रकृति; सभी पक्षों का सहयोग और नियमों व प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन करना शामिल है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने खाली पदों पर जजों की नियुक्ति में तेजी दिखाई है, लेकिन 25 हाई कोर्ट और निचली अदालतों में स्थिति वैसी नहीं है। अभी हाई कोर्ट में जजों के मंजूर पदों की संख्या 1,122 है, जिनमें से 341 पद खाली हैं। वहीं, निचली अदालतों में जजों के मंजूर पदों की संख्या 30,868 है, जिनमें से 7,311 पद खाली हैं।

कानून मंत्री ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए तय समय-सीमा का पालन न करने के लिए संबंधित हाई कोर्ट कॉलेजियम को जिम्मेदार ठहराया; यही बड़ी संख्या में खाली पदों का मुख्य कारण है। हाई कोर्ट कॉलेजियम में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए, जजों की नियुक्ति की सिफारिश भारत के चीफ जस्टिस करते हैं।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद करने का आदेश

आरबीआई ने जानकारी दी, नियमों के उल्लंघन पर बैंकिंग लाइसेंस रद हुआ था

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लाइसेंस रद किए जाने के कुछ महीनों बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने विगत दिवस इस कानूनी फैसले की जानकारी दी।

हाईकोर्ट ने एसबीआई के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरिकुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। नायर 8 जुलाई से बैंक के बोर्ड की सभी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में क्या कहा गया?

आरबीआई ने बयान में बताया कि दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने 8 जुलाई 2026 के आदेश और 22 जुलाई 2026 के आदेश के साथ यह निर्देश जारी किया है।

यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के तहत की गई है। कोर्ट ने लिक्विडेटर को बैंकिंग और कंपनीज एक्ट के तहत तय सभी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है।

अप्रैल 2026 में रद हुआ था बैंक का लाइसेंस

आरबीआई ने लगातार नियमों का पालन न करने की वजह से अप्रैल 2026 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया था। उस समय आरबीआई ने कहा था कि बैंक का कामकाज डिपॉजिटर्स के हितों के खिलाफ चलाया जा रहा।

लाइसेंस रद करने के साथ ही आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह बैंक को बंद कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगा।

क्या होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर?

ऑफिशियल लिक्विडेटर, कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया वह अधिकारी होता है जो कंपनी/बैंक की संपत्ति को कब्जे में लेकर, उसकी देनदारियों का हिसाब लगाता है और जमाकर्ताओं व कर्जदाताओं के पैसों का निपटारा करता है।

अरहर की देरी से बुआई भी लाभकारी

उन्नत किस्मों के चयन, वैज्ञानिक तकनीकों व कुशल प्रबंधन से होती है बंपर फसल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अरहर की खेती में सफलता केवल जल्दी बुआई पर नहीं, बल्कि उन्नत किस्मों के चयन, वैज्ञानिक तकनीकों और समय पर फसल प्रबंधन करने पर निर्भर करती है। किसान जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की जुलाई के अंत तक बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं।

खरीफ में अरहर किसानों की भरोसेमंद दलहनी फसल मानी जाती है, जो कम लागत में अच्छी आमदनी देती है। अरहर की जड़ों में मौजूद राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी को उर्वर बनाते हैं। यूपी में अरहर की खेती करीब तीन लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होती है। कम बारिश वाले क्षेत्रों के लिए भी यह उपयुक्त फसल है। देश में अरहर की औसत उपज मात्र 6.8 क्विंटल/हेक्टेयर है, जो वास्तविक क्षमता से कम है।

मगर, असल अंतर बुआई की तारीख से नहीं, बल्कि सही किस्म के चयन से आता है। जून या मध्य जुलाई तक बुआई न हो पाए तो जुलाई के अंत तक कम अवधि वाली उन्नत किस्में चुनकर वैज्ञानिक विधि से अरहर की खेती कर सकते हैं। इस समय बोई गई फसल सर्दियों में पाला-घने कोहरे से बच जाती है व बंपर उत्पादन मिलता है।

अभी बुआई का सर्दियों में मिलेगा फायदा

जुलाई के अंत में बोई जाने वाली अरहर की कम अवधि की किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं। इनके सीमित वानस्पतिक विकास से पौधा विशालकाय नहीं होता और दाने सुडौल बनते हैं। अक्तूबर में आने वाले फूल सूंडी के प्रकोप से बचे रहते हैं। नवंबर-दिसंबर तक फसल कटने से जनवरी के पाले-कोहरे का खतरा भी नहीं रहता और बंपर पैदावार मिलती है। गेहूं की बुआई के लिए समय पर खेत भी खाली हो जाता है।

कम अवधि वाली किस्मों का करें चयन

अरहर की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान व 600 से 1000 मिमी वर्षा उपयुक्त है। 125-145 दिन में पकने वाली कम अवधि की किस्में अपनाएं। इनमें उपास-120, पूसा अगेती, पूसा-74, पूसा-84, आईसीपीएल-88039, पूसा 991 व पूसा-992 शामिल हैं। इन किस्मों की जुलाई के बाद बुआई करेंगे तो आगे चलकर ठंड के महीनों में पौधों का वानस्पतिक विकास रुक जाएगा और पैदावार में भारी कमी हो सकती है।

राइजोबियम कल्चर से करें बीज उपचार

अरहर की फसल की अच्छी पैदावार के लिए बीजोपचार बेहद जरूरी होता है। किसान बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर और पीएसबी (फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया) से जरूर उपचारित करें। साथ ही ट्राइकोडर्मा विरिडे 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करें। इससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है और कई मिट्टी जनित रोगों से फसल को सुरक्षा मिलती है।

फफूंदजनित उकठा रोग से ऐसे बचाएं फसल

अधिक नमी और जलभराव के कारण अरहर में फफूंदजनित उकठा रोग फैल सकता है। रोग के लक्षण दिखें तो संक्रमित पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दें। खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। रोग नियंत्रण के लिए पौधों की जड़ों के पास कार्बेन्डाजिम 50 डब्ल्यूपी या थायोफेनेट मिथाइल का 1 ग्रा./ली. पानी की दर से घोल बनाकर ड्रेंचिंग करें। नियमित निगरानी से इन रोगों के प्रकोप को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

सही सिंचाई से बढ़ेगी पैदावार

अरहर सामान्यतः वर्षा आधारित फसल मानी जाती है, लेकिन लंबे समय तक बारिश न हो तो फूल आने और फलियां बनने के समय एक-एक जीवनरक्षक सिंचाई अवश्य करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई-गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। इससे पौधों की बेहतर वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ता है।

दक्षिणी हरियाणा में घट रहा कपास का रकबा

रेवाड़ी। कपास उत्पादन में दक्षिणी हरियाणा के अव्वल रहने वाले महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी जिलों में कपास की खेती लगातार घट रही है। सात वर्षों में महेंद्रगढ़ में कपास का रकबा 5.30 हजार हेक्टेयर कम हुआ है तो रेवाड़ी में करीब 70 फीसदी खेती घट गई है। चरखी दादरी में 10 सालों में छह हजार हेक्टेयर रकबा घटा है। अब चरखी दादरी में कपास का रकबा 17 हजार हेक्टेयर पर पहुंच गया है।

मौसम की अनिश्चितता और कीटों के प्रकोप व अधिक लागत के कारण अब किसान अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। कपास कभी इन तीनों जिलों की प्रमुख नकदी फसल मानी जाती थी। अब उत्पादन में उतार-चढ़ाव और बढ़ती लागत ने किसानों को निराश किया है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, वर्षा की अनिश्चितता और लंबे सूखे तो कभी अत्यधिक बारिश की स्थिति ने कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है।

गुलाबी सुंडी जैसे कीटों का प्रकोप भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। सिंचाई, कीट प्रबंधन, बिजाई व कीटनाशकों की बढ़ती लागत और बाजार में कीमतों की अनिश्चितता भी किसानों के लिए चिंता का विषय है। इन कारणों से किसान अब बाजरा, मूंग और ग्वार जैसी कम जोखिम वाली फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

प्राकृतिक खेती के लिए कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ जमीन चिह्नित

'हर पाई की भरपाई' योजना के तहत फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी सरकार

ब्लिट्ज ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ भूमि का क्लस्टर चिह्नित किया है।

इस परियोजना के तहत प्रतापगढ़, सिरझमा, बिछौली और मठाना गांवों के किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। यह पहल 'हर पाई की भरपाई' योजना के साथ लागू की जा रही है, जिसके तहत फसल नुकसान की भरपाई सरकार करेगी।

योजना के अनुसार इस क्लस्टर में आधुनिक तकनीक के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना में शामिल किसानों को कम से कम तीन वर्ष तक प्राकृतिक खेती करनी होगी। इसकी निगरानी स्थानीय कृषि विभाग और हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला मुख्यालय द्वारा की जाएगी।

फसल नुकसान का आकलन क्रॉप कटिंग प्रयोगों और फसल पकने के दौरान किए जाने वाले सर्वे के आधार पर किया जाएगा। पात्र किसानों को निर्धारित मानकों के अनुसार 'हर पाई की भरपाई' योजना का लाभ दिया जाएगा।

मोरनी ब्लॉक के 14 गांव पहले ही चुने जा चुके

राज्य सरकार इससे पहले पंचकूला जिले के मोरनी ब्लॉक के सभी 14 गांवों को प्राकृतिक खेती के लिए चयनित कर चुकी है। योजना के तहत किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 30 हजार का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही खेती करने वाले किसानों की भूमि और सिंचाई जल के नमूनों की नियमित जांच भी की जाएगी, ताकि प्राकृतिक खेती की गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

आंध्र से सीखा मत्स्य पालन, एक साथ पाल रहे 4 तरह की मछलियां

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। मछली पालन का व्यवसाय ग्रामीण स्तर पर आजीविका का बेहतर स्रोत बन गया है। खेती बाड़ी के साथ मत्स्य पालन में हर वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। कुछ किसानों का मानना है कि कृषि कार्य से कहीं ज्यादा मुनाफा मछली पालन से प्राप्त होने लगा है। यही वजह है कि आमलोग भी इस क्षेत्र की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। इसी कड़ी में जिले के मखदुमपुर के रहने वाले देव शरण प्रसाद ने आधुनिक मछली फर्म की शुरुआत की है। वो करीब एक एकड़ 14 डेसिमल में मछली पालन कर रहे हैं और उनका फार्म पूरी तरह हाई टेक है।

दरअसल, देव शरण मत्स्य पालन में आने से पहले आंध्र प्रदेश में काम कर रहे थे। उसी बीच वहां इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग देखा और जब घर लौटा तो शुरू कर दिया काम। 3 साल पहले मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया। उसमें अभी 4 प्रकार की मछलियां पाल रहे हैं। झींगा पालन के लिए भी जिले में चयन हुआ है और वो इस वर्ष से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। खास बात यह नहीं है कि वो मछली पालन कर रहे हैं, विशेष तो यह है कि जिस प्रकार से वो मत्स्य पालन कर रहे हैं, देखने लायक है।

देव शरण कहते हैं, "यह इंटीग्रेटेड फिश फार्म मॉडर्न फार्म है। इसमें हम 5 प्रकार का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मछली, झींगा, बकरी, गाय, मुर्गी और बटेर पालन शामिल है। सिर्फ डेढ़ एकड़ जमीन में हम ऐसा कार्य करेंगे। अब तक 10 लाख रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में लगा चुके हैं और चूंकि फार्म बिल्कुल हाई टेक है और सुनसान इलाके में है तो उसकी सुरक्षा भी सर्वोपरि है।

सीसीटीवी से हो रही निगरानी

हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब तक 5 सीसीटीवी कैमरे फार्म में इंस्टॉल करवा लिए हैं और 16 लगाने का लक्ष्य है। सभी 16 कैमरे फार्म में लाकर रखे हुए हैं। अब जैसे झींगा और मुर्गी फार्म शुरू होगा, बाकी सभी 11 कैमरे भी लगा दिए जाएंगे।

देव शरण, आधुनिक फिश फार्मिंग के उद्देश्य शेयर करते हुए कहते हैं कि हमारा उद्देश्य न सिर्फ मछली पालन करना है, बल्कि ऐसा उद्योग करना है जो बिल्कुल अलग हो। हर कोई एक ही चाल से चल रहा है, हम भी उस भीड़ में शामिल होंगे तो कितनी कमाई हो सकती है। यदि थोड़ा अलग करते हैं तो पहचान भी अलग होगी और कमाई भी अलग होगी।

एक खेत में एक कार्य होता तो एक आमदनी प्राप्त होती, लेकिन हमने इसे मल्टीपल में बदला है और उम्मीद है कि 5 तरफ से कमाई होगी। हम अन्य किसानों से अपील करना चाहेंगे कि आप कार्य किसी भी क्षेत्र के लिए करें, लेकिन थोड़ा हटकर करें। तभी दौलत और शोहरत दोनों मिल सकते हैं।

आस्था भट्टाचार्य

एयरोस्पेस में भारत की बड़ी छलांग

देसी स्टार्टअप ने टेस्ट किया दुनिया का सबसे एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल इंजन

चेन्नई। भारतीय एयरोस्पेस स्टार्टअप डी-प्रोपल्स ने इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल इंजन का टेस्ट किया है। यह इंजन भारत के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह आईआईटी मद्रास की तरफ से इनक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है जिसने अपने 5 केएन (किलोन्यूटन) एयर-ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (आरडीई) का एक सरकारी टेस्ट रिग डीआरडीओ फैसिलिटी में सफल परीक्षण पूरा किया है।

एयरोस्पेस कंपनी के फाउंडर और सीईओ सौरव झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंजन ने अब टीआरएल-5 लेवल को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि यह इंजन अब प्रयोगशाला के बुनियादी परीक्षणों से बाहर निकलकर वास्तविक प्रोटोटाइप के रूप में प्रमाणित हो चुका है और फिजिकल स्ट्रेस को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

भारत का पहला ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन

बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये इंजन भविष्य का इंजन है। इसे सुपरसोनिक मिसाइलों से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाएगा। यानि ब्रह्मोस से ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइलों में इसका इस्तेमाल हो सकता है।

कम हवा के प्रवाह में भी इस इंजन ने स्थिरता के साथ 5 केएन का दमदार थ्रस्ट पैदा किया है। यह थ्रस्ट एक छोटी क्रूज मिसाइल के इंजन के बराबर माना जाता है।

यह परफॉर्मेंस कम एयर मास फ्लो के साथ काम करने के बावजूद हासिल की गई जिससे पता चलता है कि आगे के टेस्ट कैंपेन में और ऑप्टिमाइजेशन से और भी ज़्यादा थ्रस्ट लेवल हासिल किए जा सकते हैं। यह उपलब्धि भारत के स्वदेशी प्रोपल्शन इकोसिस्टम के लिए खासकर अगली पीढ़ी के हाई-एफिशिएंसी इंजन के क्षेत्र में एक अहम कदम है।

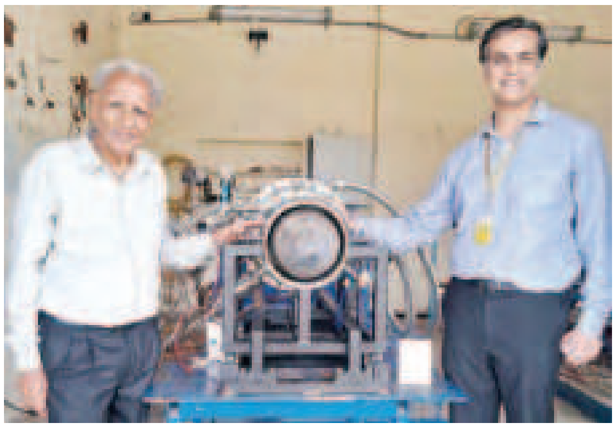

यह तकनीक इतनी खास क्यों ?

दरअसल पारंपरिक जेट इंजन ईन्धन को धीरे-धीरे जलाते हैं लेकिन आरडीई तकनीक में ईन्धन को लगातार होने वाले सुपरसोनिक धमाकों के जरिए जलाया जाता है। इससे इंजन की थर्मल एफिशिएंसी यानि ऊर्जा क्षमता 25% या उससे ज्यादा बढ़ जाती है और इंजन में चलने वाले पुर्जे बहुत कम हो जाते हैं जिससे मैकेनिकल जटिलता खत्म होती है।

आम रॉकेट या मिसाइल इंजन के नोजल घंटी के आकार के होते हैं जो सिर्फ एक निश्चित ऊंचाई पर ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसके विपरीत एयरोस्पाइक नोजल हवा के दबाव के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है जिससे यह कम ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक एक समान और बेहतरीन थ्रस्ट देता है। इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य की मिसाइलों, अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी), हाई-स्पीड एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम के लिए हो सकता है।

अभी कई चरण में और टेस्ट होना बाकी

टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल-5 (टीआरएल-5) का आम तौर पर मतलब होता है कि जरूरी टेक्नोलॉजी को असल कामकाजी हालात जैसे माहौल में इंटीग्रेट और टेस्ट किया गया है लेकिन असल इस्तेमाल के लिए अभी और डेवलपमेंट एंड्योरेंस टेस्टिंग और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत होगी। इस स्टेज तक पहुंचने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का जोखिम काफी कम हो जाता है।

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन जैसी एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में ज्यादा ध्यान खींच रही हैं क्योंकि देश तेज रफ्तार उड़ान और कॉम्पैक्ट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए ज्यादा कुशल विकल्प तलाश रहे हैं। सफल स्वदेशी डेवलपमेंट से भारत को उस क्षेत्र में महारत हासिल होगी जिस पर अभी कुछ ही देश और रिसर्च कर रहे हैं।

टीआरएल-5 तक पहुंचना

एक एडवांस्ड प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में बदलने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। सरकारी सुविधा में सफल टेस्ट इंजन के डिजाइन के अहम पहलुओं को वेरिफाई करता है और अत्याधुनिक एयरोस्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विकसित करने में कंपनी की बढ़ती क्षमताओं को दिखाता है। जैसे-जैसे प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की परिपक्वता के उच्च स्तर की ओर बढ़ेगा और टेस्टिंग व परफॉर्मेंस में सुधार की उम्मीद है।

एयरोस्पेस और डिफेंस में इसका उपयोग

हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें: यह इंजन क्रूज मिसाइलों की स्पीड, रेंज और मारक क्षमता को काफी बढ़ा सकता है।

हाई-स्पीड लड़ाकू ड्रोन: भविष्य के तेज गति से उड़ने वाले ऑटोनॉमस मिलिट्री ड्रोन्स को यह आसानी से पावर दे सकता है।

अंतरिक्ष यान और स्पेसक्राफ्ट: कम ईन्धन खपत के कारण इसे पुन: उपयोग किए जाने वाले स्पेस लॉन्च व्हीकल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

डी-प्रोपल्स कंपनी के बारे में जानिए

इस एयरोस्पेस स्टार्टअप की स्थापना जुलाई 2025 में हुई थी और इसके पीछे भारत के दिग्गज रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल हैं।

सौरभ झा इसके को-फाउंडर और सीईओ हैं जो पहले एक जाने-माने डिफेंस जर्नलिस्ट और थिंक-टैंक 'दिल्ली डिफेंस रिव्यू' के संस्थापक रह चुके हैं।

लंबी दूरी की मिसाइल 'कुशा' का पहला परीक्षण पूरा

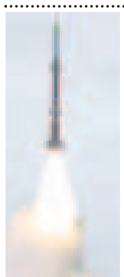

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'कुशा' का पहला सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया। यह पहला परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया, जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था। मिसाइल प्रणाली द्वारा इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट (नष्ट) किया गया।

'कुशा' मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) और बड़े दुश्मन विमानों सहित विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों को व्यापक दूरी और ऊंचाई के दायरे में निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस हथियार प्रणाली के सभी प्रमुख घटकों, जिनमें मिसाइलें, रडार, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर शामिल हैं, का विकास डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं और उद्योग साझेदारों द्वारा किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'कुशा' का सफल परीक्षण-उड़ान भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली विकसित करने की क्षमता को दर्शाता है जो केवल कुछ ही देशों के पास है। उन्होंने कहा कि इससे आयात पर निर्भरता भी खत्म होगी और देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा बदलाव आएगा।

भारतीय नौसेना में 2035 तक शामिल होंगे 200 जहाज

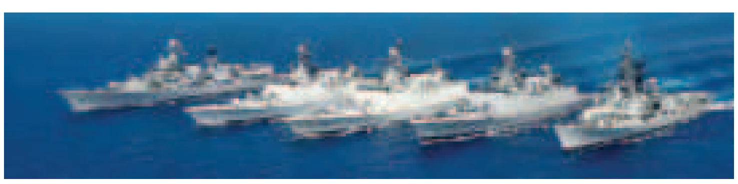

ब्लिट्ज ब्यूरो

बीजिंग। भारतीय नौसेना 2035 तक 200 से अधिक जहाजों का बेड़ा बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसका ताजा सबूत दो हफ्ते के भीतर दो युद्धपोतों की कमीशनिंग है। वर्तमान में भारतीय नौसेना लगभग 150 जहाजों और पनडुब्बियों का संचालन करती है। वहीं, लगभग 50 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय शिपयार्ड में निर्माणाधीन हैं। भारतीय नौसेना एक ब्लू-वाटर नेवी है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नौसेना न केवल अपने तटों की रक्षा कर सकती है, बल्कि गहरे खुले समुद्र में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम है।

चीन की नौसैनिक ताकत

चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीनी नौसेना में 800 से अधिक नौसैनिक पोत (डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट), तीन विमानवाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर) और परमाणु व डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां शामिल हैं।

इतनी बड़ी संख्या के बावजूद चीन अब भी बड़ी संख्या में युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।

पाकिस्तान की कमजोर नौसेना

पाकिस्तान की नौसेना काफी कमजोर है। उसे तटीय सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। इस कारण पाकिस्तानी नौसेना को ग्रीन-वाटर नेवी कहा जाता है। बजट की कमी के बावजूद पाकिस्तान ने तुर्की और चीन की मदद से अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण किया है।

पाकिस्तानी नौसेना के पास कोई विमानवाहक पोत या गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े युद्धपोत नहीं हैं।

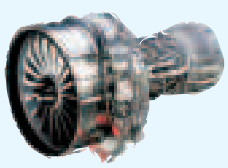

एचएएल व सैफरान में लीप इंजन टर्बाइन फोर्जिंग के लिए दीर्घकालिक समझौता

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने सीएफएम लीप इंजन कार्यक्रम के लिए सुपरअलॉय टर्बाइन रिंग फोर्जिंग के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंध के तहत, एचएएल बेंगलुरु स्थित अपने फाउंड्री और फोर्ज डिवीजन में उन्नत रिंग रोलिंग सुविधा में लगभग तैयार आकार के रिंग फोर्जिंग का निर्माण करेगी। इन घटकों का उपयोग लीप (एलईएपी) एयरो इंजनों के उच्च तापमान वाले घूर्णन खंड में किया जाता है और ये इंजन के प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

यह समझौता एचएएल के फाउंड्री एंड फोर्ज डिवीजन के महाप्रबंधक प्रवीण बी और सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खरीद) डोमिनिक डुप्यू द्वारा फार्नबोरो इंटरनेशनल एयरशो में एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रवि के और बैंगलोर कॉम्प्लेक्स के सीईओ जयकृष्णन एस की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

रवि के ने कहा कि यह समझौता एचएएल की तकनीकी और विनिर्माण क्षमताओं में वैश्विक एयरोस्पेस निर्माताओं के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लीप इंजन कार्यक्रम में एचएएल की भागीदारी वैश्विक नागरिक एयरोस्पेस बाजार में इसकी उपस्थिति को मजबूत करेगी और साथ ही भारत में भविष्य के एयरो-इंजन कार्यक्रमों के लिए उन्नत विनिर्माण क्षमताओं के विकास में सहयोग प्रदान करेगी।

डुप्यू ने कहा कि यह साझेदारी सैफरान की स्थानीय स्तर पर एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की रणनीति के अनुरूप है, क्योंकि यह बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए लीप इंजन उत्पादन को बढ़ा रही है। यह अनुबंध एचएएल व सैफरान के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का एक महत्वपूर्ण विस्तार है।

जीएसटी कलेक्शन में बंपर उछाल, जुलाई में आंकड़ा 2.11 लाख करोड़ के पार

घरेलू खपत और व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता का संकेत

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई 2026 का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। देश के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2026 में कुल ग्रॉस जीएसटी राजस्व 2,11,205 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल की समान अवधि (जुलाई 2025) के 1,83,065 करोड़ रुपये के मुकाबले 15.4% की वृद्धि दर्शाता है।

यह पिछले 14 महीनों में सबसे तेज बढ़ोतरी है और इस फाइनेंशियल ईयर में यह दूसरी बार है जब मासिक कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

घरेलू व इंपोर्ट टैक्स कलेक्शन में भी उछाल

जुलाई में घरेलू जीएसटी रेवेन्यू 10.1% बढ़कर ₹1.31 लाख करोड़ से ₹1.45 लाख करोड़ हो गया। इंपोर्ट से मिलने वाला जीएसटी रेवेन्यू 28.8% बढ़कर ₹66,511 करोड़ हो गया, जिससे महीने का कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ₹2.11 लाख करोड़ तक पहुंच गया।

बार-बार केवाईसी कराने और दस्तावेज जमा करने का झंझट खत्म

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। हर नए बैंक खाते, म्यूचुअल फंड या बीमा के लिए बार-बार केवाईसी दस्तावेज जमा करने की परेशानी अब काफी कम हो सकती है। यह संभव होगा सीकेवाईसी से।

ऐसे करें सीकेवाईसी कार्ड डाउनलोड

7799022129 पर मिस्ड कॉल दे या सीकेवाईसी के रजिस्टर्ड पोर्टल (https://www.ckycindia. in/) पर जाएं और विवरण भरें। मोबाइल पर मिले लिंक के जरिए अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें। सत्यापन पूरा होने के बाद एसएमएस में मिले लिंक से अपना सीकेवाईसी कार्ड डाउनलोड करें।

अगर आपने नया बैंक खाता खोला है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, तो संभव है कि आपको हर बार अपना आधार, पैन, पता और पहचान से जुड़े दस्तावेज फिर से जमा करने पड़े हों। अलग-अलग वित्तीय संस्थानों में यही प्रक्रिया दोहराना ग्राहकी के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है। अब आरबीआई इस परेशानी को कम करने के लिए ग्राहकों से अपने सीकेवाईसी यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर नंबर के बारे में जानने और उसका इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। देश में सीकेवाईसी के तहत अब तक 112 करोड़ से अधिक लोगों के केवाईसी डिजिटल रूप में दर्ज किए जा चुके हैं।

डाबर के '100% प्योर' दावे वाले प्रोडक्ट्स पर बैन टला

बिक्री रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे, डाबर हनी-घी बिकते रहेंगे

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने एफएसएसएआई के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें '100% प्योर', '100% नेचुरल' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे दावों वाले उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने को कहा था। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने केंद्र और एफएसएसएआई ने डॉबर के कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इनमें शहद और गाय का घी भी शामिल है। ये प्रोडक्ट 100% शुद्धता के दावे के साथ बेचे जा रहे थे।

डाबर से 15 दिनों के भीतर विशेष रिपोर्ट मांगी गई थी।

जांच में क्या पता चला था

एफएसएसएआई के अनुसार, कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे पाए गए थे। इनमें '100% नेचुरल', '100% प्योर', '100% प्योरिटी गारंटेड', '100% ऑर्गेनिक' और '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' जैसे लेबल शामिल थे। एफएसएसएआई का कहना था कि '100 प्रतिशत' दावों का यह उपयोग एफएसएस विनियम, 2018 का उल्लंघन करता है। ये दावे अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं।

नियमों के अन्य बड़े उल्लंघन

'जैविक भारत' लोगो: डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर बिना किसी वैध एफएसएसएआई ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के 'जैविक भारत' लोगो पाया गया।

कंपाउंड फूड्स पर गलत दावा: डाबर होममेड कोकोनट मिल्क को ₹100% प्योरिटी₹ के दावे के साथ बेचा जा रहा था। एफएसएस नियम, 2018 के तहत कंपाउंड फूड्स (मिश्रित खाद्य पदार्थों) के लिए ऐसा दावा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है।

एफएसएसएआई ने बताया कि उसने पहले भी डाबर को नोटिस जारी कर ऐसे भ्रामक '100%' दावों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.23 अरब डॉलर हुआ

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 6.118 अरब डॉलर बढ़कर 682.2354 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जिससे इसके लगातार मजबूत होने का संकेत मिल रहा है। इससे पहले 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.237 अरब डॉलर हो गया था। लगातार दूसरे सप्ताह आई इस बढ़ोतरी से देश की बाहरी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है।

स्वर्ण भंडार के नए आंकड़े

आरबीआई के अनुसार, समीक्षा अवधि में स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का मूल्य 1.308 अरब डॉलर बढ़कर 103.058 अरब डॉलर हो गया। वहीं, विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए) 4.873 अरब डॉलर बढ़कर 555.929 अरब डॉलर पर पहुंच गई।

आरबीआई ने बताया कि डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

देश में तेजी से बढ़ रही प्रभावशाली महिलाओं की संख्या

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में प्रभावशाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक साल में इनकी संख्या 21 फीसदी बढ़कर 117 पहुंच गई है, जिनके पास कुल 39 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। यह फिनलैंड की जीडीपी से भी अधिक है, जिसका आकार करीब 32 लाख करोड़ रुपये है। खास बात है कि इन महिलाओं में से लगभग 84 फीसदी (98) ने अपने दम (सेल्फ मेड) पर यह मुकाम हासिल किया है, जो विरासत में संपत्ति पाने वाली महिलाओं की तुलना में पांच गुना से अधिक है।

कौन सबसे युवा और सबसे उम्रदराज?

2026 की कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स सूची में 12 श्रेणियों को शामिल किया गया है। इसमें किरण मजूमदार शॉ और रोशनी नाडर मल्होत्रा जैसी दिग्गज उद्यमियों के साथ खेल, कंटेंट क्रिएटर्स, इंफ्लुएंसर्स समेत विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भी हैं। पैरा तीरंदाज शीतल देवी (19) सूची में सबसे युवा प्रभावशाली महिला हैं, जबकि दिग्गज उद्यमी रजनी बेक्टर (86) सबसे उम्रदराज हैं।

117 वुमन लीडर्स के पास 39 लाख करोड़

रोशनी नादर

किरण मजूमदार शॉ

रिपोर्ट की अन्य बड़ी बातें

- बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ के सर्वाधिक 10 लाख से अधिक लिंक्डइन फॉलोअर्स।
- 33 महिलाओं ने करियर के लिए एक से दूसरे राज्य का रुख किया।
- दो महिलाएं विदेश गईं।
- एचसीएलटेक की रोशनी नादर मल्होत्रा वेल्थ मल्टीप्लायर्स श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। उनकी संपत्ति 2.84 लाख करोड़ रुपये है।

किन शहरों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाएं?

मुंबई 26 प्रभावशाली महिलाओं के साथ शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली की 21 महिलाओं ने सूची में जगह बनाई है। बंगलूरू (16) तीसरे, गुरुग्राम (6) चौथे और पुणे (5) पांचवें स्थान पर हैं। हालांकि, 2025 के मुकाबले मुंबई की प्रभावशाली महिलाओं की संख्या 12 घटी है, जबकि दिल्ली में 8 बढ़ी है।

12 श्रेणियों में कौन-कौन रहीं अव्वल

- मीना बिंद्रा- फैशन लाइफस्टाइल
- तुषारा शंकर- सोशल चेंज मेकर
- रजनी बेक्टर- हर्टलैंड फाउंडर
- वैशाली निगम सिन्हा- न्यू इकोनॉमी
- सुनीता एवं प्रीथा रेड्डी- वेटरंस
- अवनि लेखरा- पैरालंपिक मेडलिस्ट
- सुधा मूर्ति- लेखक
- अनन्या बिरला- इंफ्लुएंसर्स
- फे डिसूज़ा- स्वतंत्र पत्रकार
- कनिका गुप्ता शोरी- स्टार्टअप फाउंडर
- रोशनी नादर मल्होत्रा- वेल्थ मल्टीप्लायर
- प्रिया नायर-पेशेवर सीईओ

सरकार ने कहा, सुरक्षित

पर्यावरण रक्षक : कार्बन डाइऑक्साइड

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के कारण लगभग 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। सरकार ने दावा किया कि ई20 सुरक्षित और परीक्षित ईन्धन है। इससे सरकार को अरबों डॉलर की बचत हुई और धरतीपुत्रों को करोड़ों रुपये की आय प्राप्त हुई।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने लोकसभा में सांसद एम. के. राघवन के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। प्रश्न में ई20 ईन्धन के उपभोक्ताओं, वाहन निर्माताओं और परिवहन क्षेत्र पर प्रभाव तथा इथेनॉल मिश्रण से उपभोक्ताओं को मिलने वाले आर्थिक लाभ के बारे में जानकारी मांगी गई थी।

सरकार के अनुसार, 2013-14 में औसत एथेनॉल मिश्रण केवल 1.53 प्रतिशत था, जो नवंबर 2025 से जून 2026 के दौरान बढ़कर लगभग 20 प्रतिशत तक पहुंच गया।

सरकार ने बताया कि एक प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ पुराने (लीगेसी) वाहन भी शामिल थे, लेकिन किसी में भी ई20 से जुड़ी इंजन क्षति नहीं पाई गई। एक प्रमुख दोपहिया निर्माता कंपनी ने भी इसी प्रकार के निष्कर्ष सामने रखे। सरकार ने स्वीकार किया कि ई10 के लिए डिजाइन किए गए कुछ वाहनों में ई20 के उपयोग से माइलेज 2 से 6 प्रतिशत तक कम हो सकती है, लेकिन यह प्रभाव ड्राइविंग की परिस्थितियों, वाहन चलाने की आदत और रखरखाव पर भी निर्भर करता है।

पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखने में मिली मदद

सरकार ने कहा कि पेट्रोल की खुदरा कीमतें बाजार आधारित प्रणाली के अनुसार तय होती हैं। फरवरी-मार्च 2026 के दौरान तेल विपणन कंपनियों को लगभग ₹21,300 करोड़ की अंडर-रिकवरी (हानि) उठानी पड़ी, क्योंकि खुदरा कीमतें बाजार स्तर से नीचे रखी गई थीं। सरकार ने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान फरवरी 2026 के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 70-80 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि भारत में ईन्धन की कीमतें केवल 7-8 प्रतिशत बढ़ीं। दिल्ली में उपभोक्ताओं को पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हुआ, जबकि बाजार आधारित संभावित कीमत करीब ₹125 प्रति लीटर हो सकती थी। सरकार के अनुसार, लगभग ₹70 प्रति लीटर की दर से एथेनॉल मिश्रित तेज की खरीद ने भी कीमतों को नियंत्रित रखने में योगदान दिया।

एक प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ पुराने (लीगेसी) वाहन भी शामिल थे, लेकिन किसी में भी ई20 से जुड़ी इंजन क्षति नहीं पाई गई।

देशभर में मिलने वाला सामान्य पेट्रोल ई20 है

सरकार ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पुष्टि की है कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला सामान्य पेट्रोल ई20 है। चूंकि ई10 पेट्रोल खुदरा स्तर पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए पंपों पर अलग से एथेनॉल प्रतिशत प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं माना गया। हालांकि, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए उपलब्ध ई85 ईन्धन वाले डिस्पेंसिंग यूनिट पर स्पष्ट लेबल लगाया जाता है। सरकार ने कहा कि ई85 ईन्धन की कीमत सामान्य मिश्रित पेट्रोल की तुलना में लगभग ₹20 प्रति लीटर कम रखी गई है, ताकि घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल का आर्थिक लाभ फ्लेक्स फ्यूल वाहन उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके।

2016 से पहले बनीं गाड़ियां नहीं झेल पाएंगी ई20 पेट्रोल

नई दिल्ली। ई20 पर जारी बहस के बीच केंद्र ने इस मुद्दे पर संसद में बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि एक अप्रैल, 2005 से पेश की गई और वर्ष 2016 से पहले बनी बीएस-3 गाड़ियों को ई20 ईन्धन से चलाने पर उसके कुछ रबर पुर्जे बदलने की जरूरत पड़ सकती है।

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ई20 ईन्धन के इस्तेमाल से गाड़ियों की माइलेज पर पड़ने वाले असर को लेकर जताई गई चिंता के बारे में ऑटोमोबाइल कंपनियों और गाड़ियों व इंजन की जांच करने वाली एजेंसियों ने साफ किया है कि गाड़ी का माइलेज सिर्फ ईन्धन के प्रकार के अलावा कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है।

सरकार ने बताया- स्टडी की गई थी

गडकरी ने कहा कि दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों पर ई20 के असर का

पता लगाने के लिए गहन सर्वे किया गया था।

इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं

उन्होंने कहा कि सर्वे में कार और दो पहिया गाड़ियों के इंजन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पाई गई। उनके अनुसार इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि पुरानी गाड़ियों के प्रदर्शन में भी कोई खास अंतर नहीं आया और न ही ई-20 ईन्धन के साथ चलाने पर उनमें कोई असामान्य टूट-फूट देखी गई।

मंत्री ने कहा कि गाड़ी चलाने में आसानी, स्टार्ट होने की क्षमता (स्टार्टबिलिटी), मेटल के साथ तालमेल (मेटल कम्पैटिबिलिटी) और प्लास्टिक के साथ तालमेल (प्लास्टिक कम्पैटिबिलिटी) जैसे पैमानों पर कोई समस्या नहीं देखी गई।

इन गाड़ियों में बदलने पड़ सकते हैं रबर पार्ट्स

उन्होंने कहा, सिर्फ एक अप्रैल, 2005 से पेश की गई और वर्ष 2016 से पहले बनी बीएस-थ्री गाड़ियों के परीक्षण के मामले में, रबर के कुछ पुर्जे और गास्केट को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे गाड़ी की नियमित होने वाली सर्विसिंग के दौरान आसानी से ठीक किया जा सकता है।'

कंपनियां वारंटी क्लेम देती रहेंगी

ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कहा है कि वे ई-20 ईन्धन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए वारंटी क्लेम देती रहेंगी।

पेट्रोल में एथेनॉल 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए जानकारी दी है कि पेट्रोल में एथेनॉल 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक साइंटिफिक स्टडी और संबंधित पक्षों से चर्चा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर देशभर में असंतोष फैला हुआ है और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बेहद जरूरी मुद्दे पर संसद में अपनी बात रखी है। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा एथेनॉल मिलाने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल, पिछले कुछ समय ई20 फ्यूल और इसमें एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की कथित सरकारी कोशिशों को लेकर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद सरकार ने ई 25 या ई 30 का विचार त्याग दिया था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में जानकारी दी कि भविष्य में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन और संबंधित पक्षों से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने यह भी साफ किया कि ई 85 फ्यूल केवल खास तौर से डिजाइन किए गए फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए है। इसका उद्देश्य देश भर में सामान्य पेट्रोल की एथेनॉल ब्लेंडिंग सीमा को 20 फीसदी से आगे बढ़ाना बिल्कुल नहीं है।

साइंटिफिक स्टडी और फील्ड वैलिडेशन के अनुसार, निर्धारित मानकों के तहत इस्तेमाल करने पर ई20 पेट्रोल एक सुरक्षित और तकनीकी रूप से बेहतर ईन्धन है। देश में ई15+ ब्लेंड का उपयोग 3.5 साल से और ई19-ई20 फ्यूल का इस्तेमाल ढाई साल से ज्यादा समय से हो रहा है।

और परीक्षित ईंधन है ई20

के उत्सर्जन में भी आई उल्लेखनीय कमी

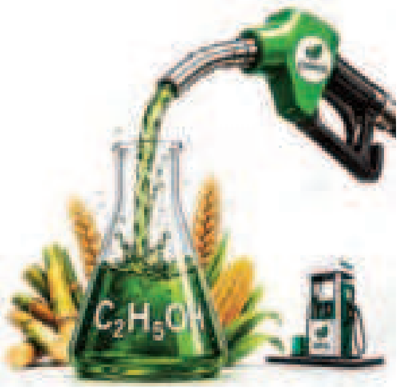

फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों ने तस्वीर बदल दी ब्राजील की

अमेरिका आज विश्व में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक

नई दिल्ली। देश में अब ई85 फ्यूल की बिक्री शुरू हो गई है। ई20 फ्यूल तो पहले से ही मिल रहा है। सरकार का मकसद साफ है, विदेशों से आने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना। आने वाले समय में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाई जाएगी। इस बीच, देश में एथेनॉल के फायदे और नुकसान पर बहस छिड़ी हुई है। भारत अकेला देश नहीं है जो एथेनॉल को ईन्धन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के कई देश, खासकर ब्राजील और अमेरिका, इस दिशा में दशकों पहले ही काम शुरू कर चुके हैं।

ब्राजील ने 1970 के दशक में ही एथेनॉल की ताकत को पहचान लिया था। 1973 के तेल संकट के बाद, देश ने पेट्रोल पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई। इसी के तहत, 1975 में ब्राजील सरकार ने 'प्रो-एल्कोहल' नाम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। इसका मकसद गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना था। शुरुआत में पेट्रोल में 10 से 25 फीसदी तक एथेनॉल मिलाया गया। 1970 और 1980 के दशक में, ब्राजील ने सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भी बनाई। सरकारी मदद और सब्सिडी के कारण ये गाड़ियां काफी पॉपुलर हुई। हालांकि, बाद में तेल की कीमतें गिरने और एथेनॉल की कमी के चलते इनकी लोकप्रियता घट गई।

ब्राजील की क्रांति

2003 में ब्राजील ने फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां (एफएफवी) पेश कीं, और इसने पूरी तस्वीर बदल दी। ये गाड़ियां किसी भी अनुपात में एथेनॉल और गैसोलीन के मिश्रण पर चल सकती थीं। इस टेक्नोलॉजी ने एथेनॉल इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी और लोगों का भरोसा भी बढ़ाया। 2008 तक, ब्राजील में बिकने वाली 80 फीसदी से ज्यादा नई कारें फ्लेक्स-फ्यूल वाली थीं। आज भी ब्राजील में ई18 से लेकर ई27.5 तक एथेनॉल मिला गैसोलीन अनिवार्य है। आज ब्राजील एथेनॉल का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।

अमेरिका में एथेनॉल का सफर

ब्राजील की तरह ही, अमेरिका भी बड़ा खिलाड़ी है। आज वह विश्व में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अमेरिका में एथेनॉल का इस्तेमाल 20वीं सदी की शुरुआत से ही हो रहा है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल 1970 के दशक में शुरू हुआ। शुरुआत में इसका इस्तेमाल लैंप जलाने के लिए होता था, बाद में गाड़ियों में भी होने लगा। अमेरिका ने मुख्य रूप से मक्के से बनने वाले एथेनॉल पर ध्यान दिया।

देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता 2,000 करोड़ लीटर

इसमें 900 करोड़ लीटर क्षमता चीनी उद्योग के पास

नई दिल्ली। देश के प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में खरीफ सीजन के दौरान मक्का का रकबा 13 प्रतिशत से अधिक घटने के कारण वर्ष 2026-27 में सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भरता बढ़ने की संभावना है। 30 सितंबर को चीनी सीजन समाप्त होने तक चीनी का समापन भंडार काफी कम रहने की आशंका जताई जा रही है। इससे वैकल्पिक मुख्य स्रोत के रूप में विशेषकर कुछ गैर-बासमती चावल किस्मों की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है, जिनकी मांग पहले ही बढ़ने लगी है।

सरकार को पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 1,100 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। देश में करीब 2,000 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन क्षमता विकसित की जा चुकी है, जिसमें लगभग 900 करोड़ लीटर क्षमता चीनी उद्योग के पास है, जबकि शेष क्षमता अनाज आधारित इकाइयों के पास है। ताजा फसल कवरेज

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष गन्ने की बुवाई लगभग पूरी हो चुकी है और 57.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती दर्ज की गई है, जबकि 2025 में अंतिम गन्ना क्षेत्रफल 58.84 लाख हेक्टेयर था।

शीर्ष तीन गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश में 28.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना बोया गया है, जो पिछले वर्ष 28.61 लाख हेक्टेयर था। महाराष्ट्र में यह बढ़कर 11.82 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 11.47 लाख हेक्टेयर था। कर्नाटक में गन्ना क्षेत्रफल 6.08 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 6.61 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इसके विपरीत, 24 जुलाई तक देशभर में मक्का का क्षेत्रफल 9.7 प्रतिशत घटकर 77.79 लाख हेक्टेयर रह गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 86.15 लाख हेक्टेयर था। हालांकि मध्य प्रदेश में मक्का का रकबा 8.2 प्रतिशत बढ़कर 25.61 लाख हेक्टेयर हो गया है।

धान की बुवाई के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश में 4.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ 57.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हुई है। पंजाब में 31.66 लाख हेक्टेयर, बिहार में 36.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ 17.58 लाख हेक्टेयर, असम में 73 प्रतिशत बढ़कर 11.68 लाख हेक्टेयर और आंध्र प्रदेश में 6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान बोया गया है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धान का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में 1 से 1.6 लाख हेक्टेयर कम है, लेकिन वर्तमान वर्षा के बाद इसमें सुधार की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में धान का क्षेत्रफल 29 प्रतिशत घटकर 19.54 लाख हेक्टेयर रह गया है।

माइलेज कम होने का ई20 पेट्रोल से लेना-देना नहीं : सरकार

कई देशों में हो रहा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल

नई दिल्ली। ई20 पेट्रोल को लेकर देशभर में तगड़ी बहस चल रही है। कई लोग इसकी वजह से माइलेज को लेकर शिकायत कर रहे हैं।

कोई इस पेट्रोल के समर्थन में है, तो कई लोग इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं। कुछ मशहूर यूट्यूबर्स ने इसकी शिकायत करते हुए बताया है कि इसको गाड़ी में भरवाने के बाद से माइलेज कम हो गई है। इसी तरह की कई और भी शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि इसका ई20 पेट्रोल से कोई लेना- देना नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले से भी कई अन्य देश इस पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां! दुनिया के कई देश पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कच्चे तेल पर निर्भरता कम होती है, प्रदूषण घटता है और किसानों को भी फायदा मिलता है। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आइये बताते हैं कि कौन सा देश कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर रहा है।

भारत का हाल

सबसे पहले भारत के बारे में ही बात करते हैं, यहां फिलहाल ई20 पेट्रोल लागू किया जा चुका है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ई30 ब्लेंडिंग हासिल करना है, ताकि तेल आयात पर निर्भरता कम हो और किसानों की आय बढ़ सके।

ब्राजील में 100% भी होता है इस्तेमाल

ब्राजील एथेनॉल ब्लेंडिंग के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। यहां साधारण पेट्रोल में करीब 30% एथेनॉल (ई30) मिलाया जाता है। इसके अलावा कई वाहन 100% एथेनॉल (ई100) से भी चलते हैं।

अमेरिका में ई10 और 15

अमेरिका में सबसे ज्यादा ई10 पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। यहां कुछ राज्यों में ई15 भी उपलब्ध है। वहीं, यूरोपीय संघ के कई देशों में ई10 पेट्रोल आम हो चुका है।

नेपाल और कनाडा भी लिस्ट में

भारत का पड़ोसी नेपाल पहले ही ई10 पेट्रोल लागू कर चुका है। वहीं कनाडा में अलग-अलग प्रांतों के नियमों के अनुसार ई5 से ई12 तक एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का उपयोग किया जाता है।

जापान है सबसे पीछे

जापान भी भारत की तरह ही एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। देश ने 2030 तक ई10 और 2040 तक ई20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय किया है।

तेल के लिए निर्भरता होगी कम

बता दें कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से केवल भारत ही नहीं बल्कि हर एक देश में पेट्रोलियम आयात पर खर्च कम हो सकता है, कार्बन उत्सर्जन घटता है और गन्ने, मक्का जैसी फसलों से जुड़े किसानों को नई बाजार संभावनाएं मिलती हैं।

मक्का की कम बुवाई से एथेनॉल होगा महंगा लेकिन नहीं घटाया जाएगा उत्पादन

नई दिल्ली। देशभर में मक्का की बुवाई में आई गिरावट से एथेनॉल उद्योग की लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एथेनॉल उत्पादन में कटौती नहीं होगी बल्कि उत्पादन लागत में वृद्धि देखने को मिलेगी।

24 जुलाई तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देशभर में मक्का की बुवाई का रकबा लगभग 10 प्रतिशत तक कम दर्ज किया गया है। जिन राज्यों में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है, उनमें महाराष्ट्र (15.6%), कर्नाटक (34%), उत्तर प्रदेश (37%), जम्मू-कश्मीर (11%), गुजरात (30%), तेलंगाना (25%), ओडिशा (34%), तमिलनाडु (48%) और मिजोरम (83%) शामिल हैं।

मक्का देश के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का प्रमुख कच्चा माल है। पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल उत्पादन में मक्का की भूमिका लगातार बढ़ी है। वर्ष 2024-25 में कुल एथेनॉल आपूर्ति में मक्का की हिस्सेदारी लगभग 48 प्रतिशत रही, जो एक महत्वपूर्ण स्तर है।

असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर निकली भर्ती

आवेदन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 29 अगस्त

ब्लिट्ज ब्यूरो

शिमला। हेल्थकेयर और मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रही महिला अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक बेहतरीन अवसर आया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 312 पदों को भरा जाएगा। यह नियुक्तियां 5 वर्ष के कॉन्ट्रेक्ट आधार पर की जाएंगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू हो गई है।

कौन कर सकता है आवेदन ?

आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह भर्ती मुख्य रूप से महिला अभ्यर्थियों के लिए है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास ये पात्रता होनी चाहिए:

शैक्षणिक योग्यताः अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास किया हो।

काउंसिल रजिस्ट्रेशन : अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल, शिमला में एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

डोमिसाइल/स्कूलिंग नियमः उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश की बोनाफाइड निवासी होनी चाहिए।

गैर-बोनाफाइड मामलों में, अभ्यर्थी ने 10वीं और 12वीं (10+2) की पढ़ाई हिमाचल स्थित संस्थानों से की हो।

आयु सीमा : आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार

के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

- नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 23 जुलाई
- ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 30 जुलाई
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: 29 अगस्त (रात 11:59 बजे तक)
- एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 4 दिनों के लिए खोली जाएगी।

आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया

आवेदन शुल्कः सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए कुल आवेदन शुल्क 800 रुपये (100 रुपये परीक्षा शुल्क + 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस) तय किया गया है। करेक्शन विंडो के दौरान संशोधन करने पर 100 रुपये अलग से शुल्क लगेगा।

सैलरीः चयनित सहायक स्टाफ नर्स को प्रति माह 25,000 रुपये का फिक्स्ड मानदेय दिया जाएगा।

चयन प्रक्रियाः अभ्यर्थियों का चयन 120 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) या ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें ?

इच्छुक अभ्यर्थी एचपीआरसीए के आधिकारिक पोर्टल hprca.hp.gov.in पर जाकर 'वन-टाइम रजिस्ट्रेशन' (ओटीआर) प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। अड़चनों से बचने के लिए समय रहते आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है।

बिना कॉलेज जाए करें पढ़ाई, जामिया ने 49 ऑनलाइन-डिस्टेंस कोर्सेज में खोले एडमिशन

22 अगस्त को होगी प्रवेश परीक्षा

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली की मशहूर केंद्रीय यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने एक बार फिर लाखों छात्रों के लिए घर बैठे पढ़ाई का दरवाजा खोल दिया है। जो लोग नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों या किसी और वजह से नियमित कॉलेज नहीं जा पाते उनके लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) ने सत्र 2026-27 के लिए कुल 49 डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

जामिया का यह सेंटर पिछले कई सालों से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) और ऑनलाइन लर्निंग

(ओएल) मोड में छात्रों को पढ़ाई का मौका दे रहा है और हर साल इसमें कोर्सेज की संख्या और दायरा बढ़ता ही जा रहा है।

आवेदन की आखिरी तारीख कब है ?

जो छात्र इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा देर सोचने की गुंजाइश नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त तय की गई है। यानी छात्रों के पास फॉर्म भरने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और फीस जमा करने के लिए सीमित समय ही बचा है।

इस बार दो नए कोर्सेज जुड़े लिस्ट में

हर साल की तरह इस बार भी सीडीओई ने अपनी कोर्स लिस्ट में कुछ नयापन जोड़ा है। इस सत्र से दो नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, बैचलर ऑफ साइंस (बायोसाइंसेज) और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)। खास बात यह है कि दोनों ही कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन मोड में पढ़ाए जाएंगे। इन नए कोर्सेज में दाखिला चाहने वाले छात्रों का चयन उनकी पिछली योग्यता परीक्षा के अंकों और एक इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

वहीं, एमबीए (ओडीएल) और बीएड जैसे कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी एक प्रवेश परीक्षा भी आयोजित करेगी, जो 22 अगस्त को होनी है। परीक्षा का सही वेन्यू और समय एडमिट कार्ड के जरिए उम्मीदवारों को बताया जाएगा।

किन-किन कोर्सेज में मिलेगा दाखिला

पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर छात्र हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, इस्लामिक स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एजुकेशन में एमए, साथ ही एमकॉम और एमबीए (ओडीएल) जैसे कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट स्तर पर बीए (जनरल), बीकॉम और बीबीए जैसे विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा डिग्री कोर्सेज के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ने कई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज के दरवाजे भी खोले हैं। इनमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पीजी डिप्लोमा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में डिप्लोमा, एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन और मास मीडिया में एडवांस्ड डिप्लोमा, और कंप्यूटर हार्डवेयर-नेटवर्क टेक्नोलॉजी व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हैं।

कैसे होगा चयन ?

ज्यादातर डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला योग्यता परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के जरिए दिया जाएगा लेकिन एमबीए (ओडीएल) और बीएड जैसे कोर्सेज के लिए स्थिति थोड़ी अलग है, इनके लिए यूनिवर्सिटी जामिया कैंपस में परीक्षा आयोजित करेगी। जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दाखिले की पुष्टि भेजी जाएगी। यूनिवर्सिटी के मुताबिक, दस्तावेजों की जांच और फीस जमा करने की प्रक्रिया 31 अगस्त से 10 सितंबर के बीच पूरी की जाएगी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यह डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो काम करते हुए आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं।

किसान की बेटी ने क्रैक किया यूपीएससी, अब कलेक्टर बनीं मिशा सिंह

इरादे पक्के हों तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं

ब्लिट्ज ब्यूरो

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह को शहडोल जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे रतलाम की जिला कलेक्टर और जबलपुर में एडीएम के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने तक का उनका सफर उन तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। अगर इरादे पक्के हों और मेहनत में ईमानदारी हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। इस बात को तेजतर्रार आईएएस अधिकारी मिशा सिंह ने सच कर दिखाया है।

शुरुआती शिक्षा तक का सफर

मिशा सिंह का जन्म एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले किसान परिवार में हुआ था। जमीन से जुड़े माहौल और माता-पिता के संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व को बचपन से ही एक मजबूत आधार दिया। उनके पिता एक किसान हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। मिशा बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थीं। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया और सफलतापूर्वक एलएलबी की डिग्री हासिल की।

वकालत से सिविल सर्विसेज की ओर झुकाव

कानून की पढ़ाई के दौरान मिशा को देश की प्रशासनिक व्यवस्था, जनसेवा और समाज में बदलाव लाने वाले अधिकारियों के काम को करीब से समझने का मौका मिला। उन्होंने महसूस किया कि वकालत के जरिए तो वे लोगों को न्याय दिला ही सकती हैं, लेकिन यदि वे प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बनती हैं, तो बड़े पैमाने पर समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। इसी विचार ने उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया।

नाकामियों से नहीं हारी हिम्मत

यूपीएससी की तैयारी का रास्ता आसान नहीं था। देश भर के लाखों मेधावी छात्रों के बीच अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शुरुआती प्रयासों में असफलता मिलने के बावजूद मिशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना, उत्तर लेखन में सुधार किया और नए सिरे से रणनीति बनाई। आखिरकार, उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 2015 में अपने तीसरे प्रयास में 64वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली।

मध्य प्रदेश में बतौर आईएएस सेवाएं

यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश कैडर आवंटित हुआ। अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों और जिलों में पूरी निष्ठा के साथ काम किया। बतौर कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के मोर्चे पर कई सराहनीय पहल कीं।

विदेश में एमबीबीएस से पहले जांच लें मान्यता, नहीं मिलेगी प्रैक्टिस की अनुमति

हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने छात्रों और अभिभावकों को किया सतर्क

दीपक सहगल

चंडीगढ़। विदेश से एमबीबीएस करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने अहम चेतावनी जारी की है। काउंसिल ने सतर्क किया है कि विदेशी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता और नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पालन जरूर जांच लें। लाइसेंसिएट (एफएमजीएल) नियम 2021 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों से पढ़ाई करने पर भारत में डॉक्टर के रूप में पंजीकरण और प्रैक्टिस में परेशानी आ सकती है। काउंसिल ने कहा कि विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए पढ़ाई कम से कम 54 महीने एक ही संस्थान में पूरी होना जरूरी है। इसके बाद 12 महीने की इंटर्नशिप भी उसी विदेशी विश्वविद्यालय में करनी होगी। क्लिनिकल ट्रेनिंग अलग-अलग देशों या संस्थानों में नहीं बांटी जा सकती।

पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, निर्धारित विषयों का अध्ययन अनिवार्य है और संस्थान संबंधित देश की मेडिकल नियामक संस्था से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

काउंसिल अनुसार के उज्बेकिस्तान की कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इन नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। खासकर ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की टर्मेज शाखा और बेंगलुरु स्थित टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से संयुक्त रूप से संचालित ऑफशोर कैंपस मॉडल पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

काउंसिल ने छात्रों और अभिभावकों से कहा है कि किसी भी एजेंट या संस्थान के झांसे में न आएं।

कोई भी संस्थान बिना नीट उत्तीर्ण किए मेडिकल दाखिले की गारंटी नहीं दे सकता। फीस जमा करने से पहले संस्थान की मान्यता की जांच करें, एनएमसी के नियमों का पालन सुनिश्चित करें और जरूरत पड़ने पर भारतीय दूतावास या एनएमसी से जानकारी लें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तुरंत एनएमसी को करें।

काउंसिल ने स्पष्ट किया कि यह सलाह छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए जारी की गई है ताकि वे गलत संस्थानों में दाखिला लेकर भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करें।

इन विदेशी मेडिकल संस्थानों में दाखिले से बचने की सलाह

- बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट (बीएसएमआई) उज्बेकिस्तान
- समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (एसएसएमयू), उज्बेकिस्तान
- ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी (टीएसएमयू), उज्बेकिस्तान
- टीएसएमयू की टर्मेज शाखा, उज्बेकिस्तान
- टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेंगलुरु (टीएसएमयू टर्मेज शाखा का ऑफशोर कैंपस मॉडल)
- सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, बेलीज
- कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बेलीज
- वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, बेलीज

नीट यूजी ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दी क्लीन चिट, याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगा दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह फैसला उन लाखों छात्रों और उनके परिजनों के लिए अहम है जो दोबारा मूल्यांकन और संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करवाने की मांग पर अड़े हुए थे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ा यह विवाद बीते काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ था और अब कोर्ट के इस रुख के बाद एनटीए को बड़ी राहत मिलती दिख रही है।

यह मामला जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई के लिए पहुंचा था। याचिका दाखिल करने वालों ने दलील दी थी कि एनटीए की तरफ से दिए गए ग्रेस अंक पूरी तरह मनमाने ढंग से बांटे गए हैं, इसलिए इन्हें फौरन रद किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत के सामने अपनी-अपनी दलीलें विस्तार से रखीं लेकिन आखिरकार पीठ ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करने लायक नहीं पाया और मामले को खारिज कर दिया।

क्या थी याचिकाकर्ताओं की असली मांग?

याचिका में मुख्य निशाना एनटीए की तरफ से बांटे गए ग्रेस मार्क्स ही थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के जवाब एनसीईआरटी की किताबों में दर्ज तथ्यों से मेल नहीं खाते, फिर भी उम्मीदवारों को इसके एवज में ग्रेस अंक थमा दिए गए जो सरासर गलत है। इसी आधार पर मांग की गई थी कि इन कथित मनमाने अंकों को तुरंत निरस्त कर बिना ग्रेस मार्क्स के एक नई और संशोधित मेरिट सूची जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने परीक्षा की पवित्रता और एनसीईआरटी के तय मानकों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। वहीं दूसरी तरफ एनटीए के वकीलों ने भी एजेंसी का पक्ष मजबूती से रखा।

विक्रम-1 मिशन में निभाई अहम भूमिका; स्पातिका अब विदेश में पूरा करेंगी अगला ड्रीम

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। आईआईटी से पढ़ाई के बाद लाइफ सेट मानी जाती है लेकिन यहां तक पहुंचना भी कई छात्रों का सपना रहा है। आईआईटी से पढ़ाई के बाद कुछ छात्र प्रोग्रामिंग सीखकर एप बनाना चाहते हैं, तो कुछ बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी करने का सपना देखते हैं लेकिन स्पातिका प्रसाद की कहानी अलग है। ये वो शख्सियत हैं, जिन्होंने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 मिशन के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने में योगदान दिया, जिसने रॉकेट लॉन्च मिशन में अहम भूमिका निभाई। अब वो एक नए सफर में निकल चुकी हैं, जो विदेश में जाकर पूरा होगा। इन दिनों इनकी कहानी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

आईआईटी मद्रास से स्पेस मिशन तक

स्पातिका प्रसाद ने स्काईरूट एयरोस्पेस में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए विक्रम-1 मिशन के लिए अहम सॉफ्टवेयर विकसित करने में योगदान दिया। विक्रम-1 भारत का पहला निजी (प्राइवेट) ऑर्बिटल रॉकेट मिशन है। हालांकि उनका काम पर्दे के पीछे था, लेकिन मिशन को सफल बनाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। मीडिया ने आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम्स के हवाले से बताया कि स्पातिका प्रसाद ने रॉकेट के लिए फ्लाइट सीक्वेंस सॉफ्टवेयर, प्री-लॉन्च ग्राउंड चेक सॉफ्टवेयर और ऑनबोर्ड-इन-द-लूप सिमुलेशन सिस्टम विकसित करने के साथ उनकी टेस्टिंग का काम किया। ये सभी सिस्टम लॉन्च से पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि रॉकेट उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है।

जब विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, तो यह स्पातिका के लिए सिर्फ एक सफल मिशन नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत, तकनीकी कौशल और सपनों की बड़ी उपलब्धि भी थी।

स्काईरूट एयरोस्पेस में काम करने के साथ-साथ स्पातिका ने आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम की पढ़ाई भी पूरी की। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस और विश्लेषणात्मक सोच जैसे विषयों में अपनी समझ को और मजबूत किया।

स्पातिका की यह जर्नी बताती है कि आज के दौर में इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग यानी एक से अधिक विषयों की पढ़ाई एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे उभरते क्षेत्रों में सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती जा रही है।

नीदरलैंड्स में करेंगी मास्टर्स की पढ़ाई

अब स्पातिका प्रसाद अपने करियर की एक और बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें नीदरलैंड्स की आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला मिल गया है। वह वहां अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत करेंगी।

कबाड़ बीनने वाले सुनील लोहार बनेंगे डॉक्टर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। जब जिंदगी इंसान की सबसे कठिन परीक्षा ले रही होती है, तब या तो इंसान टूटकर बिखर जाता है या फिर कड़े संघर्ष से इतिहास रच देता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले सुनील लोहार की कहानी ऐसा ही उदाहरण है, जो हर उस विद्यार्थी का हौसला बढ़ाता है जो अभावों के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कबाड़ की दुकान चलाने वाले और सड़कों से कबाड़ बीनने वाले सुनील लोहार ने देश की सबसे कठिन चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट यूजी में शानदार सफलता हासिल करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर दिखाया है।

6 महीने के मासूम बेटे को खोने का गहरा दर्द

2020 में 12वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई रोक दी थी। वे पिता का हाथ बंटाने के लिए कबाड़ी के काम में लगे थे। सुनील लोहार की सफलता के पीछे एक बेहद भावुक और दर्दभरी कहानी छिपी है। आर्थिक तंगी के कारण सुनील का परिवार बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहा था। उनके जीवन में सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनके 6 महीने के मासूम बेटे का सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण निधन हो गया। पैसों की कमी और अस्पताल में समय पर डॉक्टरी सहायता न मिल पाना मासूम की जान जाने की वजह बना। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने सुनील के दिल और दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख दिया।

मासूम बेटे की मौत के बाद सुनील ने रोने के बजाय एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे खुद पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी गरीब पिता को पैसों या इलाज के अभाव में अपने बच्चे को न खोना पड़े। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ सुनील कबाड़ बीनने और दुकान संभालने का काम करते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद वे रात-रात भर जागकर नीट की तैयारी में जुट जाते थे। उनके पास न तो कोई महंगी कोचिंग लेने के पैसे थे और न ही शानदार पढ़ाई का माहौल, लेकिन उनके पास था अपने बेटे की याद में लिया गया फौलादी संकल्प।

दिन में कबाड़ का काम, रात में नीट की पढ़ाई

सुनील की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें समाज के तानों और आर्थिक संकट का सामना रोज करना पड़ता था। दुकान पर आने वाले ग्राहक और आसपास के लोग अक्सर उनके डॉक्टर बनने के सपने का मजाक उड़ाया करते थे लेकिन सुनील ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं भटकने दिया। पुरानी किताबों और सीमित संसाधनों के सहारे उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। जब नीट का परिणाम घोषित हुआ, तो सुनील की मेहनत रंग लाई और उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 5,680 हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया। उन्होंने कट-ऑफ पास करते हुए मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर ली।

सुनील लोहार की यह सफलता सभी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए एक संदेश है कि कोई भी परिस्थितियां आपके सपनों से बड़ी नहीं हो सकतीं। जब आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो असफलता भी आपके सामने घुटने टेक देती है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में किसी की नौकरी पर नहीं आएगी आंच

उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। यूपी की योगी सरकार ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शीर्ष अदालत से कहा है कि 2020 में भर्ती हुए 67867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा यह कवायद सिर्फ 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति मामले तक सीमित रहेगी। भविष्य में होने वाली किसी भर्ती में इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने शीर्ष अदालत में 8,270 ऐसे अभ्यर्थियों की संशोधित सूची भी पेश की है जो अभी सेवा में नहीं हैं।

भर्ती प्रक्रिया की विवरण

राज्य सरकार ने कहा कि 19 मई को आदेश के बाद, राज्य के सक्षम अधिकारियों ने हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार मेधा सूची को दोबारा तैयार करने सहित कई विस्तृत प्रक्रियाएं पूरी कीं। हलफनामे में कहा गया कि मौजूदा कार्यवाही में 20 जुलाई को एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें संशोधित मेधा सूची में जगह पाने वाले अन्य लोगों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पूरी की है, बिना पहले से नियुक्त लोगों को हटाए। हलफनामे में कहा गया कि यह इस शर्त पर है कि मौजूदा

रिक्तियां हों, उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता पूरी करते हों और इस प्रक्रिया को भविष्य के मामलों में मिसाल के तौर पर न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अदालत का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला

- यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69 हजार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया।
- 6 जनवरी 2019 में परीक्षा आयोजित की गई।
- इसके अगले दिन कटऑफ तय की गई, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी रखा गया।
- मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर 18 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट, जहां शीर्ष अदालत ने सरकार के इस कट-ऑफ फैसले को सही ठहराया।
- जून 2020 में सरकार ने 67 हजार 867 अभ्यर्थियों की पहली चयन सूची जारी कर उन्हें स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया (एसटी वर्ग के 1133 पद योग्य उम्मीदवार न मिलने से खाली रह गए थे)।

क्यों हुआ विवाद

विवाद की दो अहम वजहें थीं। आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) के वे मेधावी उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य कटऑफ से अधिक अंक पाकर अनारक्षित श्रेणी में जगह बनाई, आरोप था कि उन्हें अनारक्षित सीटों पर सही स्थान नहीं मिला।

दूसरी तरफ दलील दी गई कि जिन आरक्षित अभ्यर्थियों ने टीईटी या एटीआरई परीक्षा में 5% अंक छूट का लाभ लिया है, उन्हें जनरल कैटेगरी में माइग्रेट नहीं किया जाना चाहिए। इसी दौरान 5 जनवरी 2022 को 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की एक सूची जारी की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।

13 मार्च 2023 को सिंगल बेंच ने कहा कि 60 फीसदी से 65 फीसदी के बीच अंक पाने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को जनरल माइग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा।

13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला रद कर दिया।

डिवीजन बेंच ने कहा- 69 हजार पदों के लिए नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। जो रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जनरल मेरिट में आते हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही गिना जाए। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाए। क्षैतिज आरक्षण स्पेशल कैटेगरी जैसे- महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर को हर जाति के भीतर मौका देने की व्यवस्था है।

सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी थी नई मेरिट लिस्ट

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 9 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के मताबिक संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है।

सीएफए कोर्स से मिलने वाली नौकरी कर देगी मालामाल

इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है सीएफए

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। जब भी कॉमर्स या फाइनेंस में पढ़ाई करने वाले छात्रों से उनके ड्रीम करियर के बारे में पूछा जाता है, तो सबसे पहला जवाब चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) ही होता है। सालों से हमारे यहां इन्हीं दोनों कोर्सेस का भारी दबदबा रहा है। युवाओं को लगता है कि बस यही दो रास्ते हैं जो सफलता तक जाते हैं लेकिन, जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाए जिसकी डिमांड न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो? और जो आपको ऐसी शानदार नौकरी दिलाए कि आप सच में मालामाल हो जाएं? जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएफए यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स की। आज के दौर में यह कोर्स युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है।

क्या है यह कोर्स?

सीएफए एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसे अमेरिका का 'सीएफए इंस्टीट्यूट' आयोजित करवाता है। अगर आप इसे फाइनेंस की दुनिया का गोल्ड मेडल कहें, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सीए या सीएस जहां मुख्य रूप से अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स और कंपनी लॉ पर फोकस करते हैं, वहीं सीएफए का पूरा जोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, शेयर बाजार, वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपको पैसों से पैसा बनाना अच्छा लगता है और बड़ी-बड़ी कंपनियों को निवेश की सही सलाह देने में दिलचस्पी है, तो यह कोर्स खासतौर पर आपके लिए ही बना है।

कौन कर सकता है यह कोर्स?

इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के लिए आपको कोई अलग से बहुत बड़ी या खास डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल (फाइनल ईयर) में पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं।

जरूरी बात कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते।

कैसे पार करें ये नैया?

सीएफए कोई ऐसा आम कोर्स नहीं है जिसे आप रातों-रात गाइड पढ़कर पास कर लेंगे। इसे काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसे तीन लेवल्स में बांटा गया है-

1. लेवल 1 : इसमें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात होती है। यह शुरुआत है, इसलिए थोड़ी आसान लगती है।

2. लेवल 2 : यह थोड़ा एडवांस और मुश्किल लेवल है। यहां एसेट वैल्यूएशन और फाइनेंशियल एनालिसिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है।

3. लेवल 3 : यह सबसे बड़ा और आखिरी पड़ाव है। इसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लानिंग की एकदम गहरी बारीकियां सिखाई जाती हैं।

जब आप ये तीनों लेवल पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनेंस के फील्ड में लगभग 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस (काम का तजुर्बा) दिखाना होता है। इसके बाद जाकर आपको सीएफए का फाइनल टैग मिल जाता है।

वो सैलरी जो कर देगी मालामाल

अब सीधे आते हैं सबसे काम की बात पर कि आखिर यह कोर्स आपको मालामाल कैसे करेगा? आज के समय में हर बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल बैंक और बड़े-बड़े रईस लोगों को ऐसे एक्सपर्ट्स की सख्त जरूरत है जो उनके पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकें। एक सीएफए की नौकरी ठीक यही होती है। कोर्स पूरा करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, या फाइनेंस डायरेक्टर जैसी टॉप लेवल की पोजीशंस पर काम कर सकते हैं।

अब बिना अनुमति डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री पर छिन जाएगा प्रिंसिपल का पद

ब्लिट्ज ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्य पद पर पदोन्नति के नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

अब यदि किसी पदोन्नत प्राचार्य ने नौकरी में रहते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रमोशन के लिए किसी डीम्ड विश्वविद्यालय के ऑफ कैंपस अध्ययन केंद्र से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से स्नातकोत्तर या अन्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है तो उनकी पदोन्नति बिना किसी पूर्व सूचना के रद कर दी जाएगी और मूल पद पर भेज दिया जाएगा।

विगत दिवस लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करते हुए 96 स्नातकोत्तर अध्यापकों (पीजीटी) और पांच हेडमास्टरों सहित कुल 101 शिक्षकों को कार्यवाहक आधार पर प्राचार्य (स्कूल कैडर) पद पर पदोन्नत कर विद्यालय आवंटित किए हैं।

महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश के बाद अब डीम्ड विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने वाले प्रधानाचार्यों की जांच होगी। इस तरह के नए और पुराने प्रधानाचार्यों की सूची तैयार कर निदेशालय को सौंपी जाएगी। अवैध शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदोन्नति का कोई अधिकार मान्य नहीं होने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।

70 प्रतिशत अच्छे सेवा रिकॉर्ड पर पदोन्नति

प्राचार्य पद पर पदोन्नति 70 प्रतिशत या उससे अधिक अच्छे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर दी गई है। नई तैनाती के बाद सभी प्राचार्यों को एससीईआरटी हरियाणा का अनिवार्य स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण पूरा करना होगा। वहीं, यदि किसी वरिष्ठ शिक्षक की पदोन्नति दस्तावेजों में देरी के कारण बाद में होती है तब भी उसकी वरिष्ठता उसके जूनियर से ऊपर ही मानी जाएगी।

30 दिनों के भीतर देना होगा विकल्प

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने पदोन्नत पीजीटी शिक्षकों से 30 दिन के भीतर लिखित रूप में विकल्प मांगा है। शिक्षकों को तय करना होगा कि वे पीजीटी पद पर ही कार्य जारी रखना चाहते हैं या टीजीटी या सीएंडवी पद पर वापस जाकर अपने जूनियर के समान मुख्याध्यापक (हेडमास्टर) पद पर पदोन्नति के लिए विचार कराना चाहते हैं।

कमी मिली तो मूल पद पर भेजा जाएगा

यदि किसी अधिकारी के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम 2016 के तहत विभागीय कार्रवाई लंबित है या वेतन वृद्धि रोकने जैसी सजा प्रभावी है तो उसकी पदोन्नति निरस्त की जा सकेगी। सभी पदोन्नत प्राचार्य एक वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24752 पदों पर भर्ती

न परीक्षा और न इंटरव्यू, निरक्षर भी पात्र

ब्लिट्ज ब्यूरो

जयपुर। राजस्थान में 24752 सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 183 से अधिक नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम) में संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के तहत यह भर्ती निकली है। इसके आवेदन 15 अगस्त से लिए जाएंगे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर है। आवेदन एसएसओ आईडी या राजस्थान स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। आवेदन के समय लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। चयन लॉटरी से होगा। परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होंगे। कोई भी अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकेगा।

एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन पत्र निरस्त (रद) कर दिए जाएंगे। 5 साल तक संविदा पर काम करने और संतोषजनक सेवा देने के बाद इन कर्मचारियों को स्थाई (नियमित) कर दिया जाएगा।

आयु सीमा और योग्यता

आयु: 1 जनवरी 2027 के अनुसार आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी।

शैक्षणिक योग्यता: इस भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यानी निरक्षर भी योग्य है।

मूल निवास: आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र/राज्य सरकार के उपक्रम, या अधिकृत ठेकेदार/संस्था में न्यूनतम 1 वर्ष का सफाई कार्य का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए और यह 1 अगस्त 2026 के बाद का जारी किया हुआ ही मान्य होगा।

चयन प्रक्रिया: इस भर्ती में न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू लिया जाएगा।

लॉटरी सिस्टम से होगा चयन

चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के जरिए होगी, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाला जाएगा। लॉटरी से पहले दस्तावेजों की जांच होगी।

प्राथमिकता: सबसे पहले उसी निकाय के अनुभवी स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

■ सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये।
■ आरक्षित वर्ग और दिव्यांगों के लिए 400 रुपये।
■ वेतन और नौकरी की शर्तें (स्थायीकरण)

यह भर्ती 'राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022' के तहत की जा रही है। संविदा के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को 7,410 रुपये प्रतिमाह का नियत मानदेय दिया जाएगा।

आरक्षण की व्यवस्था

भर्ती में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण तय किया गया है।

इसके अलावा दिव्यांगों के लिए 4% और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान है।

सबसे अधिक पदों वाले नगर निकाय

■ जयपुर: 4,811 पद
■ कोटा: 1,357 पद
■ बीकानेर: 1,084 पद
■ जोधपुर: 890 पद
■ सीकर: 480 पद
■ भरतपुर: 450 पद
■ अलवर: 426 पद
■ भिवाड़ी: 350 पद
■ धौलपुर: 340 पद
■ चूरू: 320 पद
उदयपुर: 300 पद
■ भीलवाड़ा: 296 पद
■ अजमेर: 290 पद
■ झुंझुनूं: 287 पद
■ पाली: 287 पद

एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा।

यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग

आएंगे ज्यादा प्रश्न, 2107 वैकेंसी का विज्ञापन जल्द

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। दो घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न हल करने होते थे लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में दो घंटे में ही 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेपर में नकारात्मक अंकन (नेगेटिव मार्किंग) लागू कर दी गई है। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर एक तिहाई या एक नंबर काट लिए जाएंगे। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्नपत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित 90 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 30 कुल 120 प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। सभी प्रश्न तीन-तीन अंक के होंगे और पूरा प्रश्नपत्र 360 अंकों का होगा। इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 30 जबकि विषय से संबंधित 70 प्रश्न कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। दो-दो अंकों के प्रत्येक प्रश्न थे और पूरा पेपर 200 नंबर का था। प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों की मानें तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था और विषय से संबंधित 70 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर हिन्दी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें शामिल हैं और प्रश्न केवल 70 पूछे जाते थे।

एडेड कॉलेजों में प्राचार्य के 111 पदों पर मंगलवार को चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद आयोग जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है और दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है।

टीजीटी-पीजीटी में पहली बार पूछेंगे जीएस के प्रश्न

प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। मई और जून में आयोजित भर्ती परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न पूछे गए थे। अब दो घंटे की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक पद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आगामी भर्ती में हिंदी विषय के सर्वाधिक 195 पदों पर चयन होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 44 विषयों में कुल 2107 रिक्त पदों का ब्योरा भेजा है। सह-शिक्षा महाविद्यालयों में 1699, जबकि महिला महाविद्यालयों में 408 पद खाली हैं। प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों ने एक भी रिक्त पद की सूचना नहीं भेजी है।

खास बात यह है कि एडेड महाविद्यालयों में चार साल बाद होने जा रही भर्ती में सात विषयों में 100 या अधिक पद शामिल हैं। रसायन विज्ञान 178, बीएड 176, अंग्रेजी में 111, वनस्पति विज्ञान 104, अर्थशास्त्र 103 और संस्कृत में 100 पद हैं। चयन आयोग पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी विषयों का पाठ्यक्रम जारी कर चुका है। अब उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों से चर्चा के बाद विज्ञापन जारी होगा।

13 विषयों में दस से कम पद

रिक्तियों की जो सूचना भेजी है उनमें कई विषय ऐसे हैं जिनमें दस से कम पद हैं। एशियन कल्चर, मानव विज्ञान एवं संगीत वादन सितार में केवल एक-एक, कृषि सांख्यिकी व कुक्कुट पालन में दो-दो, कीट विज्ञान में चार, कृषि एवं पादप प्रजनन व कृषि प्रसार में पांच-पांच, भूगर्भविज्ञान में छह, उद्यान विज्ञान में सात, कृषि रसायन व कृषि वनस्पति में आठ-आठ जबकि संगीत वादन तबला में नौ पद हैं। कुक्कुट पालन के पद अलग से विज्ञापित नहीं होंगे।

प्रस्तावित नई भर्ती में 17 विषय ऐसे हैं जिनमें 50 से अधिक पदों पर चयन होगा। सात विषयों में तो 100 या अधिक पद हैं लेकिन दस विषय ऐसे हैं जिनमें 50 से 100 के बीच हैं।

वाणिज्य 99, भौतिक विज्ञान 98, भूगोल 96, राजनीतिशास्त्र 94, प्राणि विज्ञान 91, समाजशास्त्र 81, मनोविज्ञान 71, विधि के 61, इतिहास 60 और गणित में 51 पद हैं।

20 हजार शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन बस एक कदम दूर

ब्लिट्ज ब्यूरो

पटना। बीपीएससी टीआरई 4 के तहत शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव विगत दिवस बिहार सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस विभाग के मंत्री हैं। इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति चौथे चरण की प्रक्रिया अब अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गयी है। टीआरई-4 के माध्यम से 20 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभाग ने टीआरई-4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी, ताकि नियुक्ति में किसी प्रकार का विलंब न हो। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ कुछ रिक्तियां प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी आएंगी।

बीपीएससी ने वायरल विज्ञप्ति को फर्जी बताया

बीपीएससी ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही टीआरई फोर की विज्ञप्ति को फर्जी करार दिया है। इसकी सूचना आयोग के जनसंपर्क अधिकारी ने दी। बताया कि अब तक आयोग के पास रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। जैसे ही आयोग के पास वैकेंसी आएगी, इसकी सूचना जारी की जाएगी।

क्या लिखा है वायरल विज्ञप्ति में

बिहार लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग- 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, वर्ग 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक तथा शिक्षा विभाग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समवेत विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाईट पर

आयोग का बयान

सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से उक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की जा रही है, जिसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्ति से संबंधित सूचना प्रदर्शित की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति पूर्णतः फर्जी, भ्रामक एवं असत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं? एटीएम जाएं

किचन में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल के लिए जल्द आ रहीं रिटेल वेंडिंग मशीनें

भारत ने तय समय से पहले ही पूरे देश में ई20 लागू कर दिया है। फिर भी, इसकी रफ्तार कम होने के बजाय, एथेनॉल के नए इस्तेमाल की खोज तेज हो रही है। खाना पकाने का ईंधन, फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और एक्सपोर्ट, ये सभी प्राथमिकता की सूची में ऊपर आ रहे हैं।

ब्लिट्ज ब्यूरो

भारत की एथेनॉल कहानी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। एक दशक से ज़्यादा समय से, ध्यान पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने पर था। आज, नीति निर्माता फ्यूल टैंक से कहीं आगे की सोच रहे हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एथेनॉल को मुख्यधारा के खाना पकाने के ईंधन के रूप में पेश करने के लिए एक फ्रेमवर्क पर काम कर रही है और एक ऐसे रिटेल मॉडल पर भी विचार कर रही है जहां उपभोक्ता किचन

स्टोव में इस्तेमाल के लिए खास 'एथेनॉल एटीएम' के ज़रिए कैनिस्टर में एथेनॉल खरीद सकें। यह प्रस्ताव भविष्य की बात लग सकता है, लेकिन यह भारत की बायोफ्यूल रणनीति में हो रहे बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है।

भारत ने तय समय से पहले ही पूरे देश में ई20 को लागू कर दिया है। अब एथेनॉल के नए इस्तेमाल की खोज तेज हो रही है। खाना पकाने का ईन्धन, फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और एक्सपोर्ट, ये सभी प्राथमिकता की सूची में ऊपर आ रहे हैं।

इन सभी पहलों के पीछे यह तथ्य है कि भारत ने एक ऐसा एथेनॉल उत्पादन इकोसिस्टम बनाया है जो इसे खपाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध मांग से बड़ा होता जा रहा है। निकट भविष्य में मांग तेजी से बढ़ने की भी उम्मीद है।

सफलता और चुनौती

एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा पहलों में से एक रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक दशक पहले के मुश्किल से 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात को कम करने, किसानों की आय में सुधार करने और एक बड़ा घरेलू बायोफ्यूल उद्योग बनाने में मदद मिली है। भारत ने तय समय से कई साल पहले ई20 लक्ष्य हासिल कर लिया और पहले से ही बायोफ्यूल अपनाने के अगले चरण पर चर्चा कर रहा है। 2014-15 के बाद से, एथेनॉल ब्लेंडिंग ने विदेशी मुद्रा में 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने में मदद की है, साथ ही किसानों और डिस्टिलरी के लिए अतिरिक्त आय भी पैदा की है।

उद्योग ने इन नीतिगत संकेतों पर भारी निवेश के साथ प्रतिक्रिया दी। चीनी मिलों ने डिस्टिलेशन क्षमता का विस्तार किया। अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादक आक्रामक रूप से बाजार में उतरे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में नई परियोजनाएं शुरू हुई । नतीजा यह है कि भारत को अब एथेनॉल क्षमता की अधिकता (ओवरहैंग) का सामना करना पड़ सकता है।

इस्तेमाल का इंतजार

खाना पकाने के ईन्धन के तौर पर एथेनॉल को बढ़ावा देने की बात क्षमता के नज़रिए से देखें तो ज्यादा समझ में आती है। केयर एज रेटिंग्स की मई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की एथेनॉल उत्पादन क्षमता सालाना 20 अरब लीटर से ज्यादा हो चुकी है। चालू वित्त वर्ष में 4 अरब लीटर की और क्षमता जुड़ने की उम्मीद है, जिससे कुल क्षमता लगभग 24 अरब लीटर हो जाएगी।

इसके मुकाबले, सरकार के ई20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सालाना लगभग 11 अरब लीटर एथेनॉल की खपत होती है। शराब, दवा और केमिकल बनाने वाली कंपनियां भी 3 से 3.5 अरब लीटर की मांग करती हैं। इसके बाद भी लगभग 7 अरब लीटर क्षमता बिना इस्तेमाल के रह जाती है। इंडस्ट्री के अधिकारी नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों में निर्यात के मौकों पर भी विचार कर रहे हैं, जहां ब्लेंडिंग के लक्ष्य तो हैं लेकिन घरेलू उत्पादन क्षमता कम है।

सच तो यह है कि भारत में एथेनॉल की बहुत ज्यादा अधिकता नहीं है। यहां ऐसी डिस्टिलरी और निवेश मौजूद हैं जो मौजूदा बाज़ार की जरूरत से कहीं ज्यादा एथेनॉल पैदा कर सकते हैं। इसीलिए अब बातचीत ब्लेंडिंग लक्ष्यों से हटकर खपत लक्ष्यों पर आ गई है। इससे पहले मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि ई20 प्रोग्राम के तहत बढ़ती मांग की तुलना में डिस्टिलरी क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ब्लेंडिंग की सीमा को 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाने पर बातचीत धीमी गति से चल रही है, इसलिए प्रोड्यूसर और पॉलिसी बनाने वाले पेट्रोल से आगे की सोच रहे हैं।

किचन बन सकता है मददगार

खाना पकाने के ईन्धन के तौर पर इस्तेमाल का प्रस्ताव एथेनॉल के लिए मांग का एक बहुत बड़ा नया ज़रिया बन सकता है। भारत घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हालांकि घरेलू उत्पादन बढ़ा है, फिर भी मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। ग्लोबल एनर्जी की कीमतों में हर उछाल का असर देश के आयात बिल और सरकार की सब्सिडी की गणना पर पड़ता है।

नीति बनाने वालों के नज़रिए से एथेनॉल एक आकर्षक विकल्प है। इसका उत्पादन देश में ही होता है और यह किसानों और ग्रामीण उद्योगों को सहारा देता है। इससे आयातित ईन्धन पर निर्भरता कम होती है। इसे पूरी तरह से एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर रहने के बजाय, एक विकेंद्रीकृत रिटेल मॉडल के जरिए भी बांटा जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नीति निर्माता खास डिस्पेंसिंग पॉइंट या एथेनॉल एटीएम पर विचार कर रहे हैं, जहां ग्राहक खास तौर पर डिजाइन किए गए कुकिंग स्टोव के लिए अपने कैनिस्टर रिफिल कर सकें। ऐसा सिस्टम एथेनॉल के लिए एक बिल्कुल नया रिटेल इकोसिस्टम बनाएगा। भले ही शुरुआत में इसका इस्तेमाल सीमित रहे, लेकिन इसकी अहमियत कहीं ज्यादा है। यह प्रस्ताव दिखाता है कि एथेनॉल को अब सिर्फ पेट्रोल में मिलाने वाले एजेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसे एक स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत के तौर पर पेश किया जा रहा है।

एक्सपोर्ट भी एक और जरिया

घरेलू खपत ही एकमात्र समाधान नहीं है जिस पर विचार किया जा रहा है। भारत पड़ोसी देशों को एथेनॉल एक्सपोर्ट करने पर तेज़ी से विचार कर रहा है, जहां ब्लेंडिंग के नियम तो हैं लेकिन पर्याप्त फीडस्टॉक या डिस्टिलेशन क्षमता नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया संभावित बाजार के तौर पर उभरे हैं। जिस देश को कुछ समय पहले तक एथेनॉल की कमी की चिंता थी, उसके लिए क्षेत्रीय एथेनॉल सप्लायर बनने का विचार एक बड़ा बदलाव है।

एक्सपोर्ट का विकल्प इसलिए भी अहम होता जा रहा है क्योंकि एथेनॉल वैल्यू चेन में पहले ही बड़ा निवेश किया जा चुका है। तेज़ी से बढ़ते ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए बनाई गई डिस्टिलरीज को अब इस बात का भरोसा चाहिए कि मांग बढ़ती रहेगी।

एविएशन हो सकता है अगला बड़ा क्षेत्र

खाना पकाने का ईन्धन भले ही सबसे नया विचार हो, लेकिन एविएशन आखिरकार भारतीय एथेनॉल के लिए सबसे अहम नए बाज़ारों में से एक बन सकता है। इस साल अप्रैल में, सरकार ने एविएशन फ्यूल के नियमों में बदलाव किया ताकि पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) को मिलाया जा सके। सरकार ने एक रोडमैप को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 2027 तक इंटरनेशनल उड़ानों में 1% एसएएफ मिलाने, 2028 में इसे बढ़ाकर 2% करने और 2030 तक 5% करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम एविएशन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और घरेलू एसएएफ इंडस्ट्री बनाने की भारत की कोशिश का हिस्सा है। एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए यह बात इसलिए अहम है क्योंकि कई कंपनियां इसके प्रोडक्शन के तरीके को अपना रही हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के पहचाने गए तरीकों में से एक है 'अल्कोहल-टू-जेट' प्रोसेस, जो एथेनॉल को जेट फ्यूल में बदलता है। दूसरे शब्दों में, एथेनॉल को अब सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट फ्यूल में मिलाने वाली चीज़ के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसे तेज़ी से एक बिल्कुल नई कैटेगरी के फ्यूल के लिए रॉ मैटीरियल (फीडस्टॉक) के तौर पर पेश किया जा रहा है।

इंडस्ट्री ने इस सोच के आधार पर निवेश करना शुरू भी कर दिया है। भारत का पहला इथेनॉल-टू-जेट फ्यूल प्लांट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और जीपीएस रिन्यूएबल्स द्वारा विशाखापत्तनम के पास बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि यह प्लांट इथेनॉल-बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर साल लगभग 1,800 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का प्रोडक्शन करेगा।

पॉलिसी बनाने वालों के लिए, एसएएफ कुछ ऐसा देता है जो पेट्रोल ब्लेंडिंग और खाना पकाने वाले फ्यूल से नहीं मिलता। दुनिया भर की एयरलाइंस पर एमिशन कम करने का दबाव बढ़ रहा है और वे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। अगर एथेनॉल बड़े पैमाने पर एविएशन सेक्टर में जगह बना पाता है, तो यह प्रोड्यूसर्स के लिए एक हाई-वैल्यू मार्केट बना सकता है, खासकर ऐसे समय में जब घरेलू क्षमता मांग से ज्यादा है।

कैफे -III से शुरू होगा अगला चरण

सरकार के हाल ही में जारी किए गए ड्राफ्ट 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी' (कैफे)-III नॉर्म्स पॉलिसी की दिशा के बारे में एक और संकेत देते हैं। पहली बार, इस फ्रेमवर्क में एथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल से जुड़े इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया गया है। आम तौर पर, फ्यूल-एफिशिएंसी नॉर्म्स पर चर्चा इलेक्ट्रिक वाहनों के इर्द-गिर्द होती रही है। ताज़ा प्रस्ताव बताते हैं कि पॉलिसी बनाने वाले एक बड़े इकोसिस्टम को बनाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसमें इथेनॉल, फ्लेक्स-फ्यूल वाहन और दूसरे बायोफ्यूल बड़ी भूमिका निभाएं।

इस बदलाव के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक बार जब ई20 हकीकत बन गया, तो अगली चुनौती हमेशा मांग पैदा करने की ही होनी थी। कैफे-III को कम से कम कुछ हद तक इस तरह डिजाइन किया गया है कि भविष्य की वाहन टेक्नोलॉजी ज्यादा एथेनॉल का इस्तेमाल कर सकें।

चीनी पॉलिसी से एनर्जी स्ट्रैटेजी तक

शायद सबसे अहम बात यह है कि एथेनॉल अब सिर्फ़ चीनी इंडस्ट्री का बाई-प्रोडक्ट नहीं रह गया है। अनाज-आधारित एथेनॉल का तेज़ी से विस्तार हुआ है और मक्का एक प्रमुख फीडस्टॉक के तौर पर उभरा है। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, अब एथेनॉल की ज्यादातर सप्लाई अनाज-आधारित स्रोतों से होती है। एथेनॉल इकोसिस्टम में अब पारंपरिक चीनी मिलों के साथ-साथ अनाज प्रोसेसर्स, डिस्टिलरी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और फ्यूल रिटेलर्स भी शामिल हो रहे हैं। गन्ने से हटकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी कम हो सकती हैं।

सेहतमंद कामयाबी

आयुष्मान भारत का प्रसार पूरे देश में अगले चरण को मजबूत करने पर जोर

भारत में लोगों का अपनी जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 2014-15 में 62.6 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 39.4 प्रतिशत हो गया। यह कमी उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनके लिए कभी अस्पताल में भर्ती होने का मतलब कर्ज में डूबना होता था।

हरविंदर आहूजा

जब पश्चिम बंगाल ने इस साल जून में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) के साथ समझौता किया, तो आयुष्मान भारत ने वह लक्ष्य हासिल कर लिया जो पहले किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल ने नहीं किया था: सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदगी। दिल्ली के एक साल पहले शामिल होने के साथ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो इस कार्यक्रम का बीमा वाला हिस्सा है, सचमुच पूरे भारत में फैल गई। सितंबर 2018 में रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए जाने के आठ साल बाद, यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है और भारत के 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' (सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा) की दिशा में एक अहम कदम है।

ऐतिहासिक स्तर की कामयाबी

इस उपलब्धि से जुड़े आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। 43 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 36,081 अस्पतालों के नेटवर्क में लगभग ₹1.73 लाख करोड़ की लागत वाले 11.6 करोड़ से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को मंज़ूरी दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा, 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर', अब 1.81 लाख से ज़्यादा केंद्रों तक पहुंच गया है, जो घर के पास ही स्क्रीनिंग, टेली-कंसल्टेशन और मुफ़्त जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 90 करोड़ हेल्थ अकाउंट का आंकड़ा पार कर लिया है, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं 'आयुष्मान वय वंदना' कवर, जिसे 2024 में 70 साल से ज़्यादा उम्र के हर नागरिक के लिए बढ़ाया गया था, पहले ही लाखों बुज़ुर्ग परिवारों तक पहुंच चुका है। सबसे अहम बात यह है कि भारत में लोगों का अपनी जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 2014-15 में 62.6 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 39.4 प्रतिशत हो गया, यह कमी उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जिनके लिए कभी अस्पताल में भर्ती होने का मतलब कर्ज में डूबना होता था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी, सहकारी संघवाद की एक शांत जीत है। स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, और अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाली सरकारों को एक मंच पर लाने के लिए धैर्यपूर्वक बातचीत और साझा मकसद की ज़रूरत थी। आम नागरिक के लिए इसका महत्व तुरंत समझ में आता है: एक राज्य में जारी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल सिद्धांत रूप में दूसरे राज्य के पैनल में शामिल अस्पताल में किया जा सकता है। इससे प्रवासी मजदूरों और यात्रा करने वाले परिवारों को पोर्टेबल सुरक्षा मिलती है, जो लंबे समय से चिकित्सा संबंधी अनिश्चितता के सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं।

सफलता के साथ अगला काम

ये ऐतिहासिक स्तर की उपलब्धियां हैं और ये आयुष्मान भारत को देश के कल्याणकारी ढांचे का एक मज़बूत स्तंभ बनाती हैं। फिर भी, इस कार्यक्रम की सफलता ही अब इसके अगले काम को सामने लाती है। इतनी तेज़ी से फैलने वाली किसी भी पहल में स्वाभाविक रूप से ऐसे क्षेत्र सामने आते हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत होती है – और यह योजना की संस्थागत परिपक्वता का प्रमाण है कि इनमें से कई मुद्दों को शांति और व्यवस्थित तरीके से हल किया जा रहा है, जबकि नामांकन लगातार बढ़ रहा है।

ऐसा ही एक क्षेत्र अस्पतालों में भुगतान में लगने वाला समय है। जैसे-जैसे दावों की संख्या बढ़ी है, कुछ जगहों पर रिइंबर्समेंट का समय भी बढ़ गया है, जिससे कुछ निजी सेवा प्रदाताओं ने अपनी भागीदारी कम कर दी है। इसे समझते हुए, सरकार ने नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) शुरू किया है। यह एक डिजिटल गेटवे है जो दावों के निपटान को मानकीकृत और तेज़ करता है, साथ ही लगभग तुरंत कैशलेस मंज़ूरी के लिए नियामक प्रयास भी करता है। जैसे-जैसे ये सिस्टम परिपक्व होंगे और ज़्यादा बीमा कंपनियों और अस्पतालों को जोड़ेंगे, सेवा प्रदाताओं के कैश फ्लो पर पड़ने वाला दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे निजी क्षेत्र, जो इलाज का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, मजबूती से इस व्यवस्था का हिस्सा बना रहेगा।

इससे जुड़ा एक और मुद्दा पैकेज दरों का है। पैनल में शामिल अस्पतालों, खासकर छोटे शहरों में, को आर्थिक रूप से जोड़े रखने के लिए एनएचए ने समय-समय पर अपने स्वास्थ्य लाभ पैकेज में संशोधन किया है; 2024 के संस्करण में 1,961 प्रक्रियाओं को शामिल किया गया और उनमें से 350 के लिए दरों में बढ़ोतरी की गई। इस तरह की समीक्षाओं को संस्थागत बनाने से सेवा प्रदाताओं का भरोसा और भागीदारी और बढ़ेगी।

सुरक्षा का विस्तार

तीसरा पहलू वित्तीय सुरक्षा की गहराई से जुड़ा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल है, फिर भी परिवारों के स्वास्थ्य खर्च का एक बड़ा हिस्सा दवाओं और आउटपेशेंट देखभाल (अस्पताल में भर्ती हुए बिना इलाज) पर खर्च होता है। यहाँ, सहायक कार्यक्रम चुपचाप इस कमी को पूरा कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मुफ़्त जरूरी दवाएँ और जाँच की सुविधाएं देते हैं, जबकि जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क, जिनकी संख्या अब 19,500 से ज़्यादा हो गई है और जहां जेनेरिक दवाएं 50 से 80 प्रतिशत सस्ती मिलती हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के परिवारों तक सस्ती दवाएं पहुंचाता है और रोजाना लगभग 10 से 12 लाख लोगों की सेवा करता है।

इन सभी को आयुष्मान भारत योजना के साथ और मज़बूती से जोड़ने से इलाज की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का दायरा बढ़ जाएगा।

इस कार्यक्रम की पहुंच प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों के कई पद अभी भी खाली हैं। केंद्र सरकार मेडिकल शिक्षा के बड़े पैमाने पर विस्तार के जरिए इस चुनौती का सामना कर रही है, जिसमें 75,000 का लक्ष्य रखा गया है।

स्कीम की विश्वसनीयता बनाए रखना भी एक प्राथमिकता रही है, और इस मामले में बहुत मजबूत प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एनएचए ने एक 'नेशनल एंटी-फ्रॉड यूनिट' बनाई है जो स्कीम के फंड को सुरक्षित रखने और यह पक्का करने के लिए कि हर रुपया असली लाभार्थियों तक पहुंचे, एडवांस्ड एनालिटिक्स, जैसे मशीन लर्निंग, इमेज रिकग्निशन और आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, का इस्तेमाल करती है। ऐसे सुरक्षा उपाय, जिन्हें लगातार मजबूत किया जाता है, ही इतने बड़े प्रोग्राम को बढ़ते हुए जनता का भरोसा जीतने में मदद करते हैं।

'मिसिंग मिडिल' (छूटे हुए मध्यम वर्ग) तक पहुंचना

आखिर में, कवरेज को और बढ़ाने का मौका है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आर्थिक रूप से सबसे कमजोर लोगों के लिए बनाया गया था और कमर्शियल इंश्योरेंस ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (संगठित क्षेत्र) की जरूरतों को पूरा करता है; इनके बीच एक बड़ी आबादी है जो खुद का काम करती है और अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (असंगठित क्षेत्र) में है, जिसे अक्सर 'मिसिंग मिडिल' कहा जाता है और जिसे एक किफायती, योगदान-आधारित विकल्प से फ़ायदा हो सकता है। सभी सीनियर सिटिज़न के लिए 'वय वंदना' कवर का यूनिवर्सल विस्तार इस दिशा में एक उत्साहजनक संकेत है, और इस वर्ग को कवर करने के लिए नीति आयोग का ब्लूप्रिंट सचमुच यूनिवर्सल सुरक्षा की दिशा में अगले कदम के लिए एक तैयार मॉडल पेश करता है।

कुल मिलाकर, ये किसी संघर्षरत प्रोग्राम की कमियां नहीं हैं, बल्कि एक परिपक्व होते प्रोग्राम के लिए जरूरी सुधार हैं। यह पैटर्न लगातार और भरोसा दिलाने वाला रहा है: जैसे-जैसे कोई चुनौती सामने आई, उसके जवाब में संस्थागत कदम उठाए गए। सिस्टम साफ तौर पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देने वाला है; अब काम इन सुधारों को तेज़ करने और उन्हें सही क्रम में लागू करने का है ताकि वादे को पूरी तरह से पूरा किया जा सके।

आगे का रास्ता

जो सलाह निकलकर आती है, वह सीधी और स्पष्ट है। पहला, हॉस्पिटल के क्लेम का समय पर निपटारा एक पक्के वादे के तौर पर किया जाना चाहिए, जिसमें एनएचसीएक्स-इनेबल्ड ऑटोमेशन हो और साफ समय-सीमा तय हो। दूसरा, पैकेज रेट में असल लागत से जुड़े पारदर्शी और समय-समय पर होने वाले बदलाव का सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, वित्तीय सुरक्षा को धीरे-धीरे आउटपेशेंट और दवा के खर्चों तक बढ़ाया जाना चाहिए, और साथ ही आरोग्य मंदिर और जन औषधि नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए। चौथा, 'मिसिंग मिडिल' आबादी के लिए एक समर्पित, कम लागत वाला इंश्योरेंस रास्ता होना चाहिए।

पांचवां, ग्रामीण वर्कफ़ोर्स की तैनाती मेडिकल सीटों के विस्तार के साथ-साथ होनी चाहिए। और इन सबके आधार के तौर पर, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर पब्लिक हेल्थ पर खर्च में लगातार बढ़ोतरी से सुधारों को सफल होने के लिए ज़रूरी वित्तीय गुंजाइश मिलेगी।

इनमें से कोई भी बात अब तक हासिल की गई उपलब्धियों को कम नहीं करती है। आयुष्मान भारत ने भारत के हेल्थ सेफ्टी नेट (स्वास्थ्य सुरक्षा घेरे) को पहले के किसी भी प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा बढ़ाया है और ऐसा करके करोड़ों लोगों के लिए बीमारी से जुड़े खर्चों और इलाज के समीकरण को बदल दिया है। अगला चरण मज़बूती लाने का है, यह पक्का करना कि इस पहुँच से मज़बूती आए, और हर पात्र व्यक्ति के हाथ में कार्ड होने के साथ-साथ हर नागरिक को अच्छी क्वालिटी का इलाज भी मिल सके। संस्थागत इच्छाशक्ति पहले से ही साफ़ है और सुधार की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए यह लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है।

वादे को और मजबूत करना

आयुष्मान भारत ने बहुत बड़े स्तर पर सफलता हासिल की है। लगभग सभी लोगों का एनरोलमेंट, पूरे देश में अस्पतालों का नेटवर्क, और अपनी जेब से होने वाले इलाज के खर्च में भारी कमी। अगला पड़ाव गहराई से जुड़ा है, और तीन जुड़े हुए सवाल इस प्रोग्राम के दूसरे चरण को तय करेंगे। क्या आर्थिक सुरक्षा को सिर्फ़ अस्पताल में भर्ती होने तक ही सीमित न रखकर दवाओं और आउटपेशेंट केयर (ओपीडी) तक बढ़ाया जा सकता है, जिन पर परिवार अभी भी सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं? क्या उस बड़े 'मिसिंग मिडिल' (ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बहुत अमीर हैं लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस का खर्च उठाने में मुश्किल महसूस करते हैं) को एक किफायती, योगदान-आधारित कवर के दायरे में लाया जा सकता है? और क्या हेल्थ वर्कफोर्स, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इतनी तेजी से बढ़ सकते हैं कि मौजूदा सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्टाफ़ मिल सके? अच्छी बात यह है कि इन सभी पर काम हो रहा है, जन औषधि और आरोग्य मंदिरों के जरिए, सीनियर सिटिजन के लिए यूनिवर्सल 'वय वंदना' योजना के विस्तार से और मेडिकल सीटों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी से।

अब इन कोशिशों को तेज करने और आपस में जोड़ने की जरूरत है, साथ ही पब्लिक हेल्थ पर खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य तक लगातार बढ़ाना होगा। ये चुनौतियां सफलता की हैं, न कि विफलता की, यह काम है पहुंच के मामले में हासिल की गई एक बड़ी उपलब्धि को हर भारतीय के लिए इलाज की पक्की और स्थायी गारंटी में बदलने का।

लता गुप्ता को मिली दिल्ली महिला आयोग की कमान

जनवरी, 2024 से खाली था पद, निर्मल जैन बने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के सदस्यों में श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरीका शर्मा झा और रेणु भल्ला को शामिल किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में निर्मल जैन की नियुक्ति की गई है। आयोग के सदस्यों में कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को नियुक्त किया गया है।

दरअसल, दिल्ली महिला आयोग जनवरी 2024 से निष्क्रिय पड़ा था। आयोग का कार्यालय बंद हो गया और धीरे-धीरे कई कर्मचारियों को भी हटा दिया गया जिस कारण महिलाओं के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने, सहायता पाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मामला हाई कोर्ट गया और इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस साल फरवरी में जवाब तलब किया। स्वाति मालीवाल के जनवरी 2024 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद आयोग के चेयरपर्सन का पद और फिर पांच सदस्यों के पद खाली हो गए थे। फिलहाल महिला और बाल विकास विभाग की सेक्रेटरी को आयोग का जिम्मा दिया गया था।

इस बारे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा, सम्मानजनक अवसर और समयबद्ध न्याय उपलब्ध हो। यह कदम उनके कल्याण एवं समावेशी विकास को गति प्रदान करेगा।

कौन हैं निर्मल जैन

निर्मल जैन लगभग 50 साल से आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। मंडल अध्यक्ष, शाहदरा जिला बीजेपी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अनुशासन समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। 2007 में वह दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए थे।

जिम्मेदारी: नियुक्ति के बाद शिकायतों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

कौन हैं लता गुप्ता

लता गुप्ता दिल्ली प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष थीं। इससे पहले वह दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री और शाहदरा जिला जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। लता गुप्ता महिला स्टैंडिंग कमिटी की अध्यक्ष भी रही हैं।

विश्वेश नेगी को भारत ने ईरान में बनाया राजदूत

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत ने ईरान में अपना राजदूत बदल दिया है। विदेश मंत्रालय ने विगत दिवस जारी आधिकारिक बयान में कहा कि विश्वेश नेगी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान राजदूत डॉ. मोहम्मद फतह अली की जगह लेंगे।

विश्वेश नेगी भारतीय विदेश सेवा के 2002 बैच के अधिकारी हैं। वह इस समय नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है।

विश्वेश ने 2002 से 2022 तक विदेश मंत्रालय में द्विपक्षीय कूटनीतिक दायित्व निभाए और भारत के विदेश मिशनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

भारत-ईरान संबंध, ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह, रीजनल कनेक्टिविटी, व्यापार और पश्चिम एशिया की रणनीतिक स्थिति के कारण उनकी नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण हैं।

वेदांता के नए सीईओ होंगे अरुण मिश्रा

नई दिल्ली। खनन एवं धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता लि. ने अरुण मिश्रा को सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने एक अगस्त 2026 से एक वर्ष के लिए पद संभाल लिया है।

वर्षा अगलावे बनीं जीएसआई की चीफ

नई दिल्ली। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 176 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को महानिदेशक बनाया गया है। वर्षा अशोक अगलावे ने संस्थान की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने असित साहा का स्थान लिया, जिन्होंने दो साल तक इस पद पर कार्य किया।

जीवाश्म विज्ञान (पैलियंटोलाजी) की विशेषज्ञ वर्षा को भूविज्ञान के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। भारतीय खान ब्यूरो (आइबीएम) में कार्य करने के बाद वह 1992 में जीएसआई से जुड़ी थीं।

असद आलम सियाम होंगे भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम, जिन्हें पिछली यूनुस सरकार ने देश का शीर्ष राजनयिक नियुक्त किया था, अब भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के पांच महीने बाद यह बड़ा राजनयिक फेरबदल माना जा रहा है।

'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और नेपाल में पूर्व राजदूत सलाउद्दीन नोमान चौधरी को सियाम की जगह नया विदेश सचिव बनाया जा सकता है।

इस बदलाव के तहत भारत में मौजूदा बांग्लादेशी हाई कमीशन एम. रियाज हमीदुल्लाह को जिनेवा में बांग्लादेश का स्थायी प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाएगा। असद आलम सियाम ने 20 जून 2025 को विदेश सचिव का पद संभाला था। उन्हें बांग्लादेश के सबसे अनुभवी करियर राजनयिकों में गिना जाता है। उन्होंने 1995 में बांग्लादेश विदेश सेवा जॉइन की थी और पिछले 30 साल में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई अहम राजनयिक और नीति संबंधी पदों पर काम किया है।

आईएफएससीए के चेयरमैन के. राजारामन का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) के चेयरमैन के. राजारामन का कार्यकाल अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, उन्हें 31 जुलाई 2026 के बाद दोबारा नियुक्त किया गया है और वह 65 वर्ष की आयु पूरी करने यानी 24 अक्टूबर 2028 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बने रहेंगे। राजारामन को वर्ष 2023 में पहली बार तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था।

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को मिला नया बॉस

ब्लिट्ज ब्यूरो

एयरलाइन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश रहेगी: विली वॉल्श

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिल गया है। विली वॉल्श ने आधिकारिक तौर पर कंपनी की कमान संभाल ली है। अब उनकी जिम्मेदारी इंडिगो के कारोबार को भारत के साथ-साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी तेजी से आगे बढ़ाने की होगी।

कंपनी का मानना है कि आने वाले सालों में भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में विली वॉल्श के लंबे अनुभव का फायदा इंडिगो को मिल सकता है। वह कंपनी के बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ मिलकर नई स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। बता दें कि इंडिगो के पूर्व सीईओ पीटर एल्बर्स ने पर्सनल वजहों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा ऐसे समय आया, जब एयरलाइन ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी।

ग्लोबल अनुभव का मिलेगा फायदा

विली वॉल्श के पास ग्लोबल एविएशन सेक्टर में 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पायलट के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस में टॉप पदों पर भूमिका निभाई है और हाल ही में इंटरनेशनल

एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के डॉयरेक्टर जनरल भी रहे। अब वह इंडिगो की अगली ग्रोथ की जिम्मेदारी संभालेंगे।

विली वॉल्श का मुख्य फोकस इंडिगो के इंटरनेशनल नेटवर्क को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही एयरलाइन की सर्विसेस में सुधार, ऑपरेशन को और बेहतर बनाना, नए रूट शुरू करना और यात्रियों को बेहतर अनुभव देना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटजी पर भी काम करेगी।

एयरलाइन अब अपने विकास के नए चरण में

इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने कहा कि एयरलाइन अब अपने विकास के नए चरण में प्रवेश कर रही है और विली वॉल्श का अनुभव इस सफर में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं, विली वॉल्श ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एयरलाइन मार्केट में शामिल है। ऐसे समय में इंडिगो से जुड़ना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि वह पूरी टीम के साथ मिलकर एयरलाइन को ग्लोबल लेवल पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे।

3,030 करोड़ रुपये से बनेंगे तीन भव्य रसायन पार्क

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, कैबिनेट ने दी मंजूरी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में 3,030 करोड़ रुपये से तीन भव्य रसायन पार्क बनेंगे। इसका निर्माण पांच साल में पूरा होना है। हर पार्क में कम-से-कम आठ वर्ग किलोमीटर का निर्बाध भूमि क्षेत्र होगा। ये पार्क रासायनिक उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाओं के वाहक बनेंगे। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

योजना के तहत 500 करोड़ का योगदान संबंधित राज्य सरकार देगी तो केंद्र 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। देश में तीन समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी। भव्य रसायन योजना शुरू करने से घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करके घरेलू उत्पादन क्षमता

बढ़ाकर और रोजगार सृजित करके इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी।

इन पार्कों में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र, उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा, जल आपूर्ति और वितरण प्रणालियां, भाप उत्पादन और वितरण नेटवर्क, परस्पर जुड़ा हुआ पाइपलाइन नेटवर्क व लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सुविधाएं होंगी।

कर्नाटक व आंध्र के रेल नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार, 1,264 करोड़ की परियोजना मंजूर

केंद्र सरकार ने रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने बल्लारी-गुंटकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,264 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा ईको फ्रेंडली होंगे ये नोट

नई दिल्ली। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 और 20 रुपये के प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में यह जानना बनता है कि प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट कैसे तैयार होते हैं? इन्हें बनाने में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है?

दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले बैंक नोट बड़े तकनीकी बदलाव से गुजर रहे हैं। दरअसल पारंपरिक कॉटन-फाइबर यानी कि कागजी नोटों की जगह पॉलिमर यानी प्लास्टिक के नोट ले रहे हैं। कई देश इनका इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं और कुछ ने हाल ही में इनका रुख किया है।

गौरतलब है कि ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान अपने अध्ययन में बता चुका है कि पॉलिमर नोट न सिर्फ टिकाऊ होते हैं बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी कागजी नोटों की तुलना में ज्यादा ईको फ्रेंडली होते हैं।

प्लास्टिक के नोटों का आविष्कार डेविड सोलोमन ने किया था। इस प्रोजेक्ट को 1988 में ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के अनुरोध पर शुरू किया गया था, जो कि लगभग 20 साल तक चला।

1988 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला 10 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का नोट जारी किया था। इसके बाद 1996 तक ऑस्ट्रेलिया पूरी करेंसी को पॉलिमर नोटों में बदलने वाला पहला देश बन गया था। प्लास्टिक के नोटों का बेस बीओपीपी नाम की एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल होता है। इसमें कोई रेशा या छेद नहीं होता। इसकी वजह से यह पानी, गंदगी या पसीना आदि नहीं सोखता। इसके एक हिस्से को ट्रांसपेरेंट छोड़ा जाता है। जिसकी वजह से इन्हें स्कैनर या प्रिंटर द्वारा कॉपी करना असंभव हो जाता है। इनमें खास तौर पर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग और ऑप्टिकली वेरिएबल डिवाइसेज का इस्तेमाल होता है, जिससे अलग-अलग एंगल पर इनमें अलग रंग और पैटर्न देखने को मिलते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला अब 2031 तक मिलते रहेंगे सालाना ₹6000

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को अगले पांच साल यानी 2030-31 वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस पर 3,15,614 करोड़ का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी और केंद्र सरकार की यह योजना देश भर के किसानों को निश्चित आय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता मिलती है।

यह रकम 2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) के जरिए भेजी जाती है। सरकार इस योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है।

23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा और 18,984 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई। कोविड-19 महामारी के दौरान, किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बांटी गई।

पीएम को किसान दिवस हुई है श्रृंखला के तहत महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली है, और हर चार लाभार्थियों में से लगभग एक महिला किसान है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। योजना के नियमों के तहत, यह राशि हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पिछली 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी।

बढ़ रहा एंटीफंगल रेजिस्टेंस, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता

नई दिल्ली। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को एक खामोश खतरे से आगाह किया है। यह खतरा किसी वायरस का नहीं, बल्कि फंगल इन्फेक्शन का है।

डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, दुनिया में हर साल 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके इलाज के लिए एंटीफंगल दवाएं दी जाती हैं। चिंता की बात यह है कि ये दवाएं धीरे-धीरे अपना असर खो रही हैं।

दरअसल एंटीफंगल दवाओं का इस्तेमाल इंसानों के अलावा पशुओं और खेती में भी किया जाता है। इसकी वजह से कई फंगस इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने फंगल इन्फेक्शन और एंटीफंगल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए एक ग्लोबल स्ट्रेटजी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि अगर एंटीफंगल दवाओं का बेवजह इस्तेमाल नहीं रुका, तो भविष्य में सामान्य फंगल इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल हो सकता है। कई मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।

यह सूक्ष्मजीवों (माइक्रोऑर्गेनिज्म) का एक समूह है। इसमें यीस्ट, फफूंद (मोल्ड) और मशरूम शामिल हैं। फंगस हमारे आसपास लगभग हर जगह पाए जाते हैं। ज्यादातर फंगस नुकसान नहीं पहुंचाते।

फंगल इन्फेक्शन क्या होता है?

फंगस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन को 'फंगल इन्फेक्शन' कहते हैं। यह स्किन, नाखून, मुंह, फेफड़ों या शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है।

किन अंगों में हो सकता है?

यह स्किन, स्कैल्प, नाखून, मुंह और कुछ मामलों में शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन होने पर एंटीफंगल दवाएं दी जाती हैं लेकिन अगर ये एंटीफंगल दवाएं फंगस पर असर करना बंद कर दें या उनका असर कम हो जाए, तो इसे एंटीफंगल रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे इलाज करना कठिन हो जाता है।

गाड़ियां आपस में करेंगी बात, अंधे मोड़ पर भी नहीं होगा एक्सीडेंट

ब्लिट्ज ब्यूरो

सरकार अनिवार्य करने जा रही वी2वी सिस्टम

नई दिल्ली। सोचिए, आप गाड़ी से जा रहे हों और अचानक सामने एक ऐसा मोड़ आ जाए जिस वजह से आपको सामने से आ रही गाड़ी दिखाई ही न दे। अचानक आपकी कार आपको सामने से आती गाड़ी के बारे में अलर्ट कर दे या खुद ही ब्रेक लगा दे तो आपको कैसा लगेगा। हैरान मत होइये, भारतीय सड़कों पर जल्द ही यह हकीकत बनने जा रहा है। सरकार सड़कों पर हादसों को रोकने के लिए वाहनों को आपस में स्मार्ट तरीके से जोड़ने की तैयारी कर चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब वाहनों में वी2वी यानी 'व्हीकल-टू-व्हीकल' कम्युनिकेशन तकनीक को अनिवार्य करने जा रही है।

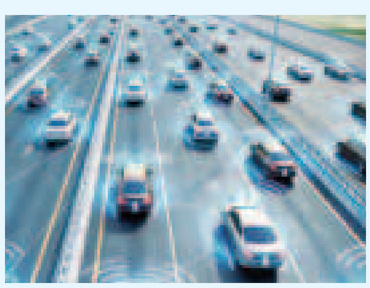

1 अक्टूबर 2028 से देश में बिकने वाली सभी नई गाड़ियों में वी2वी सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नया उप-नियम जोड़ने का फैसला किया है। यह नियम दोपहिया, तीनपहिया, कार, बस और ट्रक सभी वाहनों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2027 से अगर किसी गाड़ी में वी2वी सिस्टम लगा है, तो उसे अनिवार्य रूप से एआईएस-230 मानकों का पालन करना होगा। 1 अक्टूबर 2028 से देश में बिकने वाली सभी नई गाड़ियों में एआईएस-230 मानक वाला वी2वी सिस्टम अनिवार्य कर दिया जाएगा।

क्या है वी2वी तकनीक

वी2वी यानी 'व्हीकल-टू-व्हीकल' कम्युनिकेशन एक वायरलेस तकनीक है। इसके जरिए गाड़ियां एक-दूसरे को अपनी लोकेशन, स्पीड और ब्रेकिंग स्टेटस जैसी जानकारियां रियल-टाइम में भेजती हैं। गाड़ियों में लगे खास सेंसर और डेडिकेटेड शॉर्ट-रेंज कम्युनिकेशन (डीएसआरसी) डिवाइस आसपास की अन्य गाड़ियों को सिग्नल भेजते हैं।

यानी हम कह सकते हैं कि वे एक-दूसरे से बात कर सकती है। इस तकनीक के बहुत फायदे है और यह सड़क हादसे रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत रोड एक्सिडेंट्स में 50 फीसदी की कमी लाना चाहता है। इसीलिए वीटूवी तकनीक को अपना रहा है।

वी2वी का क्या होगा फायदा?

360 डिग्री सुरक्षा: यह सिस्टम भारी कोहरे या अंधे मोड़ (ब्लाइंड स्पॉट) में छिपे खतरों को पहले ही पहचान लेगा।

ऑटोमैटिक ब्रेक और अलर्ट: आगे वाली गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाते ही आपकी कार को सिग्नल मिल जाएगा, जिससे पीछे से टक्कर होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

जाम से मुक्ति: गाड़ियां आपस में ट्रैफिक डेटा शेयर करेंगी, जिससे आप जाम में फंसने से पहले ही रास्ता बदल सकेंगे।

'भारतीयों पर हमले बर्दाश्त नहीं'

होर्मुज में जहाजों पर अटैक को लेकर सुरक्षा परिषद में गरजा भारत

ब्लिट्ज विशेष

न्यूयॉर्क। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इन हमलों पर चिंता जताई और तत्काल तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने सुरक्षा परिषद को बताया कि इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी जबकि एक लापता है। वहीं, कई भारतीय घायल हुए हैं।

होर्मुज व मिडिल ईस्ट का मुद्दा उठाया

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो द्वारा बुलाई गई बैठक में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, हम इस महीने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कई जहाजों पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बाहिया और एमटी मोम्बासा जहाज शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत ने समुद्री यात्रियों को निशाना बनाने और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर आजाद और सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालने वाली हिंसा की निंदा की है। भारत इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए बातचीत और कूटनीति का पुरजोर समर्थन करता है।

सुरक्षा परिषद के सामने रखी मांग

भारत ने सुरक्षा परिषद से मांग की कि इस क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम लोगों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर आजाद और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

मिडिल ईस्ट भारत के लिए अहम

भारतीय प्रतिनिधि ने मध्य पूर्व को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की मांग की। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत का व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क इस क्षेत्र से मजबूती से जुड़ा है। हरीश ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र से भारत का लगभग 180 अरब डॉलर का सालाना द्विपक्षीय व्यापार, 31 अरब से ज्यादा का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और जीसीसी से भारत 52 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई हासिल होती है।

11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत को बांटने का शौक पालने वाला पाकिस्तान आज खुद टूट रहा है। पीओके में जोरदार विरोध प्रदर्शनों के बीच बलूचिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख भी फिक्स कर दी है। बलूचिस्तान 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। बलूच नेता इसके लिए दुनियाभर के देशों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वे 11 अगस्त को बलूच एकता दिखाएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं।

बलूच लिबरेशन नेता मीर यार बलूच ने कहा कि 11 अगस्त को लोग स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा अपने घरों पर फहराएं। इसके साथ ही आस-पास, बाजार, दुकानों और सार्वजनिक जगहों पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा लगाया जाए।

बलूच नेता ने कहा कि हर साल अब 11 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। विदेश में रहने वाले बलूच लोग भी इस दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएंगे।

शेख हसीना ने कहा- न फांसी की चिंता, न जेल की परवाह

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। बांग्लादेश की बेदखल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गत दिवस बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे गिरफ्तारी, जेल या मौत की सजा की आशंकाओं के बावजूद इस साल दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत की राजधानी नई दिल्ली में रह रहीं शेख हसीना ने कहा कि वे स्वदेश लौटने पर किसी भी अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हैं।

न्यूज एजेंसी को ईमेल के जरिए दिए जवाब में शेख हसीना ने कहा, मुझे मारा जा सकता है। मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे जेल में डाला जा सकता है। मुझे अपने भाग्य की पूरी जानकारी है। फिर भी मैं वापस जाना चाहती हूं क्योंकि मेरे देश के लोग मुझे पुकार रहे हैं।

इससे पहले मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी शेख हसीना ने कहा था कि वह और उनके राजनीतिक सहयोगी निर्वासन खत्म कर बांग्लादेश लौटेंगे और वहां की अदालतों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा था, "मेरे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भीषण अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर मौत आती है तो मैं चाहती हूं कि वह मेरी अपनी सरजमीं पर आए, जहां मेरे माता-पिता दफनाए गए हैं और जहां उनका खून बहा था।"

शेख हसीना को बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। यह सजा उनके शासनकाल के दौरान यानी कि 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके के चलते सुनाई गई थी। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद उनके शासन का अंत हो गया था। उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था।

आरक्षण के खिलाफ चला था अभियान

2024 में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के खिलाफ हुई थी। हालांकि, सुरक्षा बलों द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई के बाद यह आंदोलन तेजी से राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। महीनों चले इस आंदोलन में हजारों लोग घायल हुए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनों के उग्र होने के बाद अगस्त 2024 में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गईं।

सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और उनके कई पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के तहत कई मामले शुरू किए। उनकी पार्टी अवामी लीग के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हैं या कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

भारत समेत 60 देशों पर नए टैरिफ लगाकर घिरे डोनाल्ड ट्रंप

ब्लिट्ज ब्यूरो

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ (आयात शुल्क) बढ़ाने का नया कदम फिर से कोर्ट पहुंच गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर नए टैरिफ को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। टैरिफ का सामना करने वाले इन 60 साझेदार देशों में भारत भी शामिल है। इन राज्यों का तर्क है कि इस तरह के कदमों के खिलाफ कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद ट्रंप प्रशासन का नया टैरिफ लगाना कानूनी अधिकार क्षेत्र के लिहाज से ठीक नहीं है।

न्यूयॉर्क में अमेरिकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर यह मुकदमा 10 से 12.5 फीसदी के उन टैरिफ को निशाना बनाता है। यह टैरिफ पिछले महीने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लागू हुए थे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये शुल्क उन देशों के खिलाफ हैं, जो जबरन मजदूरी से बने सामान का निर्यात रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम हैं। यह ट्रंप की टैरिफ रणनीति की परीक्षा है।

ट्रंप कोर्ट की अनदेखी कर रहे'

यह मुकदमा ओरेगन और न्यूयॉर्क समेत 25 राज्यों ने दायर किया है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी (राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं) के गवर्नर या अटॉर्नी जनरल हैं। राज्यों का तर्क है कि ट्रंप अलग कानूनी आधार का इस्तेमाल करके उन व्यापक आयात करों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अदालतें पहले ही गैर-कानूनी करार दे चुकी हैं। शिकायत के अनुसार, धारा 301 अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोपी देशों या उद्योगों को निशाना बनाने के लिए है। यह अमेरिकी आयातों को प्रभावित करने के लिए नहीं है।

सिंधु जल संधि पर दो टूक, पाकिस्तान ने खुद गिराई अपनी साख: विनय क्वात्रा

ब्लिट्ज ब्यूरो

वाशिंगटन। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) सद्भावना और मित्रता की भावना के साथ की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों में इस भावना को लगातार कमजोर किया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा संधि को स्थगित रखने का फैसला केवल उस वास्तविकता को स्वीकार करना है, जिसे पाकिस्तान के व्यवहार ने पहले ही नष्ट कर दिया था।

क्वात्रा ने यह बात 'न्यूजवीक पत्रिका' में प्रकाशित अपने लेख में कही। उनका यह लेख ऐसे समय आया है, जब हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले के विरोध में एक सम्मेलन आयोजित किया था। भारत ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद लिया था, जिसमें पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी।

'संधि की प्रस्तावना में सद्भावना और मित्रता की बात'

क्वात्रा ने लिखा, यह याद रखना चाहिए कि संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि इसे 'सद्भावना और मित्रता की भावना' से संपन्न किया गया था। पाकिस्तान ने आधी सदी तक इस सद्भावना और मित्रता को खत्म करने का काम किया। संधि को स्थगित रखने का फैसला केवल उसी स्थिति को स्वीकार करता है, जिसे पाकिस्तान के आचरण ने पहले ही नष्ट कर दिया था।

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु बेसिन की छह नदियों में से तीन पर नियंत्रण मिला, जिनमें कुल जल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बहता है। वहीं, पाकिस्तान को उन नदियों पर अधिकार मिला, जिनमें करीब 80 प्रतिशत पानी बहता है। क्वात्रा ने कहा कि इस असंतुलन के कारण भारत के कई क्षेत्रों का विकास लंबे समय तक प्रभावित रहा, फिर भी भारत ने संधि का सम्मान किया।

उन्होंने कहा कि इसके जवाब में पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े। इसके अलावा उसने सीमा पार आतंकवाद जारी रखा, जिसमें 2001 का संसद हमला, 2008 का मुंबई आतंकी हमला, 2016 के उरी और पठानकोट हमले, 2019 का पुलवामा हमला और 2025 का पहलगाम आतंकी हमला शामिल हैं।

क्वात्रा ने कहा कि अगर पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग चाहता है, तो उसे सबसे पहले वर्षों में खड़े किए गए आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि संधि के तहत भारत द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के मामले में पाकिस्तान ने लगातार बाधाएं खड़ी कीं और प्रशासनिक स्तर पर देरी की।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तकनीकी बदलावों को ध्यान में रखते हुए संधि में संशोधन के भारत के प्रयासों का भी लगातार विरोध किया।

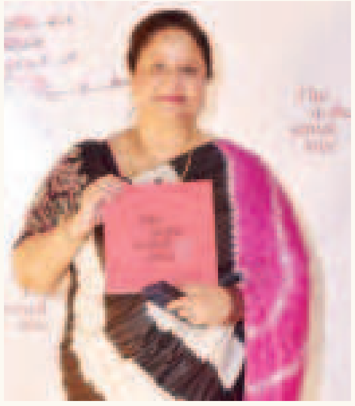

पक्षियों से सेमल तक पहुंची मण्डलायुक्त संगीता सिंह की प्रकृति से जुड़ी लेखन यात्रा

सेमल के पेड़ के नीचे हुआ 'फायर इन द सेमल ट्री' पुस्तक का विमोचन

ब्लिट्ज ब्यूरो

अलीगढ़। प्रकृति को करीब से देखने और महसूस करने का एक अनूठा अनुभव सामने आया जब मण्डलायुक्त संगीता सिंह की दूसरी पुस्तक 'फायर इन द सेमल ट्री' का विमोचन उसी सेमल के वृक्ष के नीचे किया गया, जिसके निरंतर अवलोकन से इस पुस्तक की कहानी जन्मी है। यह सेमल का पेड़ मण्डलायुक्त कैम्प परिसर में स्थित है। पुस्तक का विमोचन मण्डल के प्रशासनिक अधिकारियों, पर्यावरण प्रेमियों एवं प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ।

पुस्तक केवल एक वृक्ष की कहानी नहीं, बल्कि सेमल के माध्यम से जीवन, समय, ऋतु परिवर्तन, प्रकृति और मनुष्य के आत्मीय संबंधों को देखने का एक संवेदनशील प्रयास है। मण्डलायुक्त ने कई महीनों तक सेमल वृक्ष के बदलते रूप, उसके आसपास आने वाले पक्षियों-पशुओं और बदलती ऋतुओं का बारीकी से अवलोकन किया। इन्हीं सहज अनुभवों को सरल और संवेदनशील भाषा में पुस्तक का रूप दिया गया है।

'फायर इन दा सेमल ट्री' पुस्तक का विमोचन करतीं आयुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह व समारोह में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग।

मण्डलायुक्त संगीता सिंह ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति हमें ठहरकर देखने और महसूस करने का अवसर देती है। ऐसी पुस्तकें लोगों को अपने आसपास मौजूद प्रकृति के सूक्ष्म बदलावों को समझने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक पर्यावरणीय चेतना के साथ-साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का भी एक प्रयास है। वह कहती हैं कि पुस्तक लिखने की कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। सेमल के वृक्ष के साथ लंबे समय तक जुड़ाव और उसके आसपास घटित होने वाली प्राकृतिक गतिविधियों को देखते-देखते विचारों ने शब्दों का रूप ले लिया। पुस्तक में प्रकृति के माध्यम से जीवन के विविध आयामों को सहज और आत्मीय अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।

विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण प्रेमियों एवं गणमान्य नागरिकों ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह कृति पाठकों को प्रकृति को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करेगी। वक्ताओं ने कहा कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी और प्रशासनिक दायित्वों की व्यस्तता के बीच प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और लेखन का यह प्रयास प्रेरणादायी है।

पक्षियों से सेमल तक–प्रकृति से जुड़ी लेखन यात्रा

मण्डलायुक्त संगीता सिंह की यह दूसरी पुस्तक है। उनकी पहली पुस्तक 'वाकिंग विद विंग्स एंड ए कैमरा : एनकाउंटर्स विद बर्ड्स ऑफ अलीगढ़' हाल ही में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक अलीगढ़ क्षेत्र के पक्षी जीवन, जैव-विविधता और पक्षी संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिखी गई। प्रशासनिक दायित्वों के बीच प्रकृति के साथ बिताए गए शांत क्षणों ने उन्हें आत्मिक संतुलन और संवेदनशीलता प्रदान की। पक्षियों के अवलोकन से शुरू हुई यह लेखन यात्रा अब सेमल के एक वृक्ष तक पहुंची है। दोनों पुस्तकों में प्रकृति को केवल देखने की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को समझने और महसूस करने के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सादा समारोह के अंत में मण्डलायुक्त ने सभी अतिथियों, अधिकारियों, पर्यावरण प्रेमियों एवं उपस्थितजनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस मौके पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, एडीए वीसी कुलदीप मीणा, डीआईजी प्रभाकर चौधरी, एसएसपी नीरज जादौन, एसपी सिटी मयंक बंसल, साहित्य अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग लोग मौजूद रहे।

विकसित भारत के लिए नशा-मुक्त युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ

युवा वर्ग को भारत की 'अमृत पीढ़ी' बताया पीएम मोदी ने

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया है। एक राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने 28 हजार से अधिक स्थानों से जुड़े एक करोड़ से अधिक युवाओं सहित विविध सभा का औपचारिक रूप से अभिवादन किया।

पीएम ने युवा वर्ग को भारत की 'अमृत पीढ़ी' बताते हुए, उन्हें याद दिलाया कि उनकी ऊर्जा, कल्पनाशीलता और प्रतिभा देश को 2047 के विकास लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्म-विनाशकारी आदतों से पूरी तरह मुक्त, अत्यधिक आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी की आवश्यकता है।

अभियान की महत्वाकांक्षी 100-सप्ताह की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, पीएम मोदी ने विस्तार से बताया कि आने वाले प्रत्येक रविवार को कला, संस्कृति, खेल और ध्यान से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि नए प्रतिभागियों को लगातार जोड़ा जा सके।

यूपी के हर श्रमिक की तनख्वाह का 50 फीसदी होगा मूल वेतन

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के लाखों कामगारों और सेवायोजकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी मिल गई। इसके लागू होने के बाद अब किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र, प्रतिष्ठान या नियोजन में कार्यरत हो। संहिता में प्रावधान किया गया है कि कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा।

नई नियमावली के हिसाब से भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, सेवा समाप्ति के दो दिन के भीतर बकाया भुगतान, नियमित कार्य अवधि से अधिक काम कराने पर दोगुनी ओवरटाइम मजदूरी और वेतन पर्ची देना अनिवार्य होगा।

कौशल और काम की प्रकृति से निर्धारित होगी मजदूरी

नई श्रम संहिता के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने की व्यवस्था को सभी पात्र कर्मचारियों तक विस्तारित किया गया है। कौशल, कार्य की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मजदूरी निर्धारित होगी। केंद्र सरकार द्वारा तय 'फ्लोर वेज' से कम न्यूनतम मजदूरी कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकेगी। वहीं श्रमिकों की मजदूरी से वैधानिक कटौती की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता पर होगी। मृत कर्मचारी के बकाया भुगतान के लिए नामित व्यक्ति और उसके अभाव में विधिक उत्तराधिकारी को राशि देने का प्रावधान भी किया गया है।

नियोक्ता-श्रमिकों को नहीं जाना होगा कोर्ट

नियोक्ताओं को भी नई व्यवस्था में राहत दी गई है। पहली बार नियमों के उल्लंघन पर उपशमन का प्रावधान होगा। अनुपालन का बोझ घटाते हुए अब केवल तीन रजिस्टर और दस प्रपत्र रखने होंगे। वार्षिक विवरण सहित अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा किए जा सकेंगे। नई संहिता में श्रम निरीक्षण प्रणाली को भी पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन और जोखिम आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू होगी तथा 'श्रम निरीक्षक' की जगह 'निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता' की व्यवस्था होगी, जो नियमों के अनुपालन के साथ नियोक्ताओं और कर्मचारियों को परामर्श एवं मार्गदर्शन भी देगा। इसके अलावा विवादों में विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील की व्यवस्था की गई है। पहले इसमें हाईकोर्ट जाने की व्यवस्था थी।

पदकों की संख्या से आगे भारत की असली सफलता

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल-2026 के प्रदर्शन का आकलन केवल जीते गए पदकों की संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता। भारत ने कुल 39 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। वर्ष 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 पदक जीते थे। पहली नजर में यह कमी निराशाजनक लग सकती है, लेकिन केवल आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते।

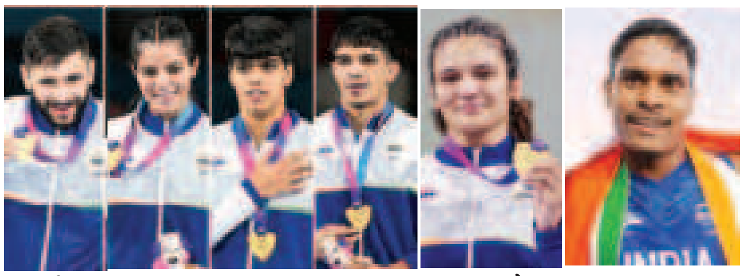

स्वर्ण विजेता : सचिन, साक्षी, प्रिया, अंकुश, अरुंधति और दिलीप

मीराबाई चानू

सोमन राणा

ग्लासगो में इस बार केवल 10 खेलों को शामिल किया गया था, जबकि बर्मिंघम में 19 खेल आयोजित हुए थे। भारत को परंपरागत रूप से अधिक पदक दिलाने वाले निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे खेल इस बार प्रतियोगिता का हिस्सा ही नहीं थे। उल्लेखनीय है कि बर्मिंघम में भारत के 61 में से 30 पदक केवल इन्हीं पांच खेलों से आए थे। इसलिए ग्लासगो में पदकों की संख्या कम होना स्वाभाविक था।

वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बदली हुई परिस्थितियों के बावजूद भारत ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखी, शीर्ष चार देशों में स्थान हासिल किया और पारंपरिक खेलों से आगे बढ़कर नए खेलों में भी अपनी बढ़ती ताकत का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

नए खेलों में भारत की बढ़ती ताकत

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का खेल आधार अब पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो रहा है।

विशेष रूप से मुक्के बाजी में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं, जीतकर नया इतिहास रच दिया।

इसी तरह जूडो में भारत ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जबकि एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की पदक संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

ये नतीजे इस बात का संकेत हैं कि भारत अब केवल कुछ पारंपरिक खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नए खेलों में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।

अब लक्ष्य लॉस एंजिलिस ओलंपिक

ग्लासगो की सफलता अब भारत के लिए अगले बड़े लक्ष्य की तैयारी का आधार बनेगी। देश की निगाहें अब लॉस एंजिलिस ओलंपिक-2028 पर टिकी हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि ग्लासगो से मिले आत्मविश्वास को और मजबूत करते हुए विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए और पेरिस ओलंपिक-2024 में जीते गए छह पदकों से आगे बढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए।

ओलंपिक में व्यापक सफलता की जरूरत

भारत की ओलंपिक यात्रा उपलब्धियों और चुनौतियों, दोनों का प्रतिबिंब रही है।

पेरिस ओलंपिक-2024 में भारत ने एक रजत और पांच कांस्य पदक जीते थे। ये पदक निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में मिले।

शर्मिला धनकड़

इन उपलब्धियों ने भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा और क्षमता को साबित किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत को अधिक से अधिक खेलों में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी।

एथलेटिक्स से बढ़ी नई उम्मीदें

हाल के वर्षों में एथलेटिक्स में मिली सफलताओं ने भारत के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। चीन के शाओशिंग में आयोजित एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत की महिला 4×100 मीटर रिले टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। श्राबनी नंदा, एस. एस. स्नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की टीम ने 43.85 सेकंड का सत्र का सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया।

ओलंपिक में सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स में दिए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और सुनियोजित तैयारी भारत की वैश्विक खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होगी।

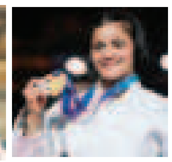

जूडो में भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ इतिहास में गोल्ड जीता। अस्मिता डे ने गोल्ड दिलाया। इसके कुछ मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड जीत लिया। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज जीतकर कुल चार मेडल दिलाए। हालांकि 14 सदस्यीय भारतीय टीम के दो खिलाड़ी अरुण कुमार और तुलिका मान डोपिंग के कारण बाहर हो गए।

सरकारी पहलों से मिला नया बल

अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारत की लगातार बढ़ती सफलता के पीछे सरकार का बढ़ा हुआ निवेश, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दिया जा रहा लक्षित सहयोग महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना और खेलो इंडिया जैसी पहलों ने देश के युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इसके अलावा निजी खेल अकादमियों, कॉर्पोरेट प्रायोजन और पेशेवर खेल लीगों ने भी भारत के खेल तंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रैंक	देश	गोल्ड	सिल्वर	ब्रॉन्ज	कुल
1	ऑस्ट्रेलिया	70	45	56	171
2	इंग्लैंड	29	45	36	110
3	कनाडा	19	20	23	62
4	भारत	13	17	9	39

भिवानी की नारी शक्ति की दुनिया में धूम, देश पर बरसाया सोना

हरियाणा को पहली बार 6 गोल्ड, भिवानी का 'गोल्डन पंच'

प्रीति

जैस्मिन

गुलशन वर्मा

नई दिल्ली। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल हैं। सबसे ज्यादा दबदबा बॉक्सिंग में रहा, जहां हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। 6 में से 5 गोल्ड अकेले भिवानी के खिलाड़ियों ने नाम रहे। भिवानी की चार महिला बॉक्सरों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।

ऐसी पहली बार हुआ, जब किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणवियों ने एकसाथ बॉक्सिंग इवेंट में 6 गोल्ड मेडल जीते। इससे पहले दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स- 2010 में हरियाणा के हिस्से बॉक्सिंग में 4 मेडल आए थे।

बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल, साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घनघस, सचिन सिवाच ने गोल्ड और नरेंद्र बेरवाल ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं, शॉटपुट में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड, डिस्कस थ्रो में सीमा कालीरमन और जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज, जबकि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता।

नरेंद्र बेरवाल को रजत

हांसी के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल इंग्लैंड के डामर थॉमस से फाइनल मुकाबला हार गए और सिल्वर से संतोष करना पड़ा।

अंकुश ने इंग्लैंड के बॉक्सर को हराया

हिसार के भेरिया गांव निवासी अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया।

सचिन सिवाच का विजयी पंच

सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के मुक्केबाज को ट्राईगेन मॉर्निंग नडेवेलो को 3-2 से हराया।

एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीतेगी

साक्षी चौधरी ने 5-0 से जीत हासिल की। उन्होंने बाएं हाथ से प्रतिद्वंद्वी के पंचों को रोका और दाएं हाथ से लगातार सटीक जवाबी हमले किए।

प्रिया घनघस 4-1 जीती

महिलाओं के 60 किग्रा फाइनल मुकाबले में प्रिया घनघस ने स्प्लिट डिसीजन (4-1) से जीत हासिल की।

54 किलो भारवर्ग में प्रीति श्रेष्ठ

प्रीति पंवार का फाइनल मुकाबला कनाडा की एस.एस. डेलगाडो से हुआ। प्रीति ने पहले राउंड से ही डेलगाडो पर बढ़त बना रखी थी। रैफरी ने उन्हें 5-0 से विजेता घोषित किया।

जैस्मिन ने 5-0 से जीता फाइनल

जैस्मिन लंबोरिया ने एम. वाल्स को 5-0 से हराकर फाइनल मैच जीता।

भिवानी एवं महिला बॉक्सरों के गांवों में जीत का जमकर जश्न मनाया गया। महिला बॉक्सरों के अभिभावकों ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। इनके परिजनों को बधाइयों का तांता लगा हुआ है।

अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली

ग्लासगो। ग्लासगो में 11 दिनों तक चले रोमांच, रिकॉर्ड और यादगार कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों का सफर अब खत्म हो गया। रंगारंग समापन समारोह के साथ 2026 राष्ट्रमंडल खेलों को भावुक विदाई दी गई और अब पूरी दुनिया की नजरें 2030 पर टिक गई है, जब मेजबानी भारत के अहमदाबाद के हाथों में होगी। भारत 2010 के दिल्ली खेलों के बाद दूसरी बार इस महाकुंभ की मेजबानी करेगा। समापन

समारोह में स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन भारत को सौंपा। इस खास पल के गवाह बने ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी।

कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन, मानुषी छिल्लर ने परफॉर्म किया। ओवो हाइड्रो एरिना में ऑस्ट्रेलियन सिंगर डेल्टा गुडरेम की परफॉर्मेंस से क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई।

8 गुना बढ़ा 'खेलो इंडिया' का बजट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 5 सालों के लिए, 'खेलो इंडिया' योजना और राष्ट्रीय खेल संघों के बजट को बढ़ाकर कुल 36,441 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें से 29,054 करोड़ रुपए सिर्फ 'खेलो इंडिया' के लिए होंगे। यह पिछली योजना से करीब 8 गुना ज्यादा है।

इस भारी-भरकम फंड का लक्ष्य भारत को 2036 ओलंपिक और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए एक 'ग्लोबल स्पोर्ट्स हब' बनाना है। जमीनी स्तर, पर छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 'इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स' नाम की एक नई कैटेगरी भी बनाई जाएगी, जिससे खिलाड़ियों का दायरा 10 गुना तक बढ़ेगा।

ब्लिट्ज ब्यूरो

देश में 576 अरबपति, 5 साल में चार गुना बढ़े

जयपुर। भारत में पांच साल में अरबपतियों की संख्या में चार गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। साल 2021-22 में 142 अरबपति थे, 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 576 हो गई है। सरकार ने अरबपतियों की संख्या बताई है, लेकिन अलग-अलग अरबपतियों की कुल आय का ब्योरा नहीं दिया है।

दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि आयकर एक्ट में अरबपति शब्द की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है लेकिन आयकर विवरण (आईटीआर) में सालाना 100 करोड़ या इससे ज्यादा की आय दिखाने वालों का ब्योरा दिया है।

सरकार के पास अरबपतियों की कुल संपत्ति का ब्योरा नहीं

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार के पास करदाताओं की कुल संपत्ति का कोई आधिकारिक या संकलित डेटा नहीं है। इसका कारण यह है कि संपत्ति कर अधिनियम, 1957 को एक अप्रैल 2016 से खत्म कर दिया गया।

कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया था

जवाब के अनुसार, घरेलू खर्च में ग्रामीण

और शहरी क्षेत्रों का अंतर कम हो रहा है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गिनी गुणांक (लोगों के बीच आय या धन की असमानता) 0.237 और शहरी क्षेत्रों के लिए 0.284 दर्ज किया गया है। यह 2022-23 के आंकड़ों से कम है, जो यह दिखाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर कम हो रहा है।

13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के श्रम बाजार कोविड-पूर्व स्तर से बेहतर स्थिति में हैं। 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2022 के 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% हो गई है।

नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के निष्कर्ष बताते हैं कि साल 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% रह गया है। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

असमानता कम करने के लिए ज्यादा आय वालों पर सरचार्ज लगाया

वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि देश में असमानता कम करने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कई मोर्चों पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अत्यधिक आय वाले व्यक्तियों पर सामान्य टैक्स के अलावा सरचार्ज लगाया है।

पेज 1 के शेष

जुकरबर्ग ने भारत सरकार से मांगी माफी

मेटा यह तय करती है कि कौन-सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा। इसलिए कंपनी को आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली 'सेफ हार्बर सुरक्षा' का लाभ नहीं मिलेगा।

उल्लेखनीय है की इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए कहीं अधिक है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य वैश्विक मंचों के करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ता हैं। ऐसे में भारत से उठने वाली डिजिटल प्लेटफार्म की जवाबदेही का संदेश दुनिया भर में मजबूती के साथ गया है।

मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत सरकार की वह राजनीतिक इच्छाशक्ति है जिसके तहत उसने दुनिया की सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में से एक से सीधे जवाब तलब किया। सरकार ने उनकी किसी भी बहानेबाजी को कोई भी तरजीह नहीं दी।

सही है कि पिछले दो दशकों में सोशल मीडिया ने दुनिया को अभूतपूर्व रूप से जोड़ा है। इसने सूचना को आम लोगों तक पहुंचाया। संवाद के नए रास्ते खोले। कारोबार तथा नए प्रयोगों के लिए अपार अवसर पैदा किए लेकिन इसके साथ गलत सूचनाओं, डीपफेक, आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामग्री, ऑनलाइन दुर्व्यवहार की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं।

इन परिस्थितियों में भारत का रुख स्पष्ट है। तकनीक और नवाचार का स्वागत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए लेकिन किसी निजी कंपनी या उसके एल्गोरिदम को ऐसी बेलगाम ताकत नहीं दी जा सकती जिससे वह बिना जवाबदेही के सार्वजनिक संवाद को जहरीला बनाए।

तथ्यात्मक सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री की पोस्ट से जुड़ी घटना ने सोशल मीडिया से जुड़े इस बुनियादी सवाल को सामने ला दिया है। अगर किसी स्वचालित व्यवस्था से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री की पोस्ट भी गलती से प्रतिबंधित हो सकती है तो सामान्य नागरिकों, पत्रकारों, संस्थानों और कारोबारियों के लिए कितनी प्रभावी सुरक्षा मौजूद है?

एल्गोरिदम की आड़ नहीं चलेगी

सही तो यह है कि कई वर्षों से दुनिया की बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां अपने मंचों पर सामग्री से जुड़े नियम और उन्हें लागू करने की व्यवस्था काफी हद तक स्वयं तय करती रही हैं।

कौन-सी सामग्री ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, किसकी पहुंच कम की जाएगी और किस सामग्री को हटा दिया जाएगा। इन फैसलों को कंपनी की एल्गोरिदम तय करेगी। भारत सरकार ने अब इस व्यवस्था के सामने जवाबदेही का महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार का संदेश साफ है कि फैसला भले ही एल्गोरिदम करे, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी कंपनी की वैश्विक पहुंच उसे उस देश के कानून से ऊपर नहीं कर सकती जहां वह कारोबार करती है।

केंद्र सरकार आजकल भारत में ऑनलाइन मंचों, गैरकानूनी सामग्री, डीपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री और डिजिटल मध्यस्थों की जवाबदेही से जुड़े नियमों को लगातार मजबूत करने के काम में जुटी हुई है।

भारत सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के मंच वैश्विक हो सकते हैं लेकिन उन्हें स्थानीय कानून और देश की कानूनी व्यवस्था का सम्मान करना ही होगा।

आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि यूरोपीय संघ ने डिजिटल सेवा कानून के माध्यम से बड़ी टेक कंपनियों के लिए कठोर जिम्मेदारियां तय की हैं। दुनिया के कई अन्य देश भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, डीपफेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चुनावी दुष्प्रचार और एल्गोरिदम की पारदर्शिता को लेकर नए नियम तैयार कर रहे हैं। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास विशाल डिजिटल आबादी, मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था, तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से जवाब मांगने की राजनीतिक शक्ति- चारों मौजूद हैं।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक विकासशील देशों के लिए भारत का यह सख्त और नसीहत भरा घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

यह विषय भी जानकारी के लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सामग्री को क्यों हटाया गया? उसकी पहुंच क्यों सीमित की गई? फैसला इंसान ने किया या मशीन ने? गलती होने पर समीक्षा की क्या व्यवस्था है? प्रभावित व्यक्ति को अपील का कितना प्रभावी अधिकार है? समय आ गया है कि दुनिया भर की सरकारों और नियामकों को अब इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे।

भारत की मोदी सरकार ने इस मुद्दे का हल निकालकर दुनिया को इसी नक्शेकदम पर आगे बढ़ने का मजबूत रास्ता दिखा दिया है। डिजिटल वर्ल्ड की भारत में हुई इस घटना ने सिलिकॉन वैली और पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में तकनीक का स्वागत है लेकिन मनमानी का नहीं। यहां नवाचार जरूरी है, लेकिन जवाबदेही भी। कुल मिलाकर सार यह है कि भारत में कोई भी एल्गोरिदम या कंपनी भारतीय कानूनों से ऊपर नहीं है।

ई20 : आत्मनिर्भर भारत की नई क्रांति

भारत ने ₹1.98 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। तथ्य यह है कि भारत को आज भी अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करना पड़ रहा है। यही कारण है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार और आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। ई20 भारत की पेट्रोल आयात पर निर्भरता घटाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की ओर एक बड़ा कदम है।

क्या बोली सरकार

ई20 पेट्रोल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने संसद में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ई20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक ईन्धन है। साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि बिना एथेनॉल वाले पुराने या 'शुद्ध' पेट्रोल को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है और यह कार्यक्रम व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही लागू किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में लिखित जवाब के जरिए यह जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि ई20 पेट्रोल को लेकर उसे वाहनों की परफॉर्मेंस से जुड़ी कोई व्यापक या पुष्ट शिकायत नहीं मिली है। सरकार ने इसके लिए देशभर में 23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के असल इस्तेमाल के अनुभव और कई स्टडीज का हवाला दिया।

इस बीच जहां एकतरफ एथेनॉल के खिलाफ सड़क पर विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मुलाकात कर एथेनॉल के समर्थन में आवाज बुलंद की है।

किसानों के अनेक संगठनों ने कहा कि एथेनॉल से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और देश की ऊर्जा भी सुरक्षित होगी। शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में किसानों ने कहा कि एथेनॉल खेती के लिए नया मौका है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने कहा कि एथेनॉल को लेकर गलत नैरेटिव को तोड़ने के लिए किसान और सरकार मिलकर काम करें। विभिन्न राज्यों से आए किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि पेट्रोल नहीं, खेत से निकला एथेनॉल देश का भविष्य है।

ई20 क्रांति के मुख्य लाभ

- **आयात में कमी :** एथेनॉल ब्लेंडिंग से 310 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के आयात को प्रतिस्थापित किया गया है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों के झटकों से देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रही है।
- **रोजगार सृजन :** ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्टिलरी और बायोफ्यूल परियोजनाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और निवेश के अवसर पैदा हुए हैं।
- **प्रदूषण में कमी :** ई20 ईन्धन के प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 54 मिलियन टन से ज्यादा की कमी आई है।
- **वाहन अनुकूलन :** ऑटोमोबाइल उद्योगों और शोध संस्थाओं (जैसे एआरएआई) के साथ व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद इसे अपनाया गया है, जहां अप्रैल 2023 से नए वाहन मटेरियल-कंपैटिबल व अप्रैल 2025 से पूरी तरह इंजन-कंपैटिबल बनाए गए हैं।
- **अन्नदाता से ऊर्जादाता :** गन्ने, मक्के और अन्य कृषि उत्पादों से एथेनॉल तैयार किया जाता है। इससे देश का अन्नदाता किसान अब ऊर्जा उत्पादक भी बन रहा है।

ई20 ईन्धन पेट्रोल में 20फीसद एथेनॉल और 80 फीसद पेट्रोल का एक मिश्रण है, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की एक अनूठी क्रांति है।

25 वर्षों की सुनियोजित तैयारी का परिणाम है ई20

इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि जिस पहल को उसके व्यापक राष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए था वह सोशल मीडिया पर फैली अधूरी जानकारियों और भ्रामक दावों तथा चंद नेताओं के राजनीतिक हितों की चाहतों के कारण विवाद का विषय बनती जा रही है।

दरअसल किसी भी नई पहल का विरोध होना आम बात है पर जब समय उसे सही साबित कर देता है तब सभी को उसके लाभ का अहसास होता है। भारत की विकास यात्रा का इतिहास भी गवाह है कि लगभग हर बड़ा परिवर्तन शुरुआत में संदेह और विरोध का शिकार बना। जब हरित क्रांति शुरू हुई, तब भी अनेक विशेषज्ञों ने संदेह किया था कि नए किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक भारतीय खेती को नुकसान पहुंचाएंगे। श्वेत क्रांति के लिए भी यह कहा गया कि गांवों में संगठित दुग्ध उत्पादन संभव नहीं होगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली आई तो अनेक लोगों ने इसे अव्यावहारिक करार दिया पर अब यही भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क का संचालन कर रहा है और दुनिया के अनेक देश इसे अपना रहे हैं।

इसी तरह ई20 को लेकर भी बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इससे वाहन का माइलेज घट जा रहा है। सरकार भी मानती है कि कुछ वाहनों में 3 से 5 प्रतिशत तक माइलेज घट सकता है किंतु क्या किसी ईन्धन का मूल्यांकन केवल माइलेज के आधार पर किया जा सकता है? सच तो यह है कि एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग अधिक होती है। इससे वाहन के इंजन में बेहतर दहन होता है, एंटी-नॉक क्षमता बढ़ती है, इंजन की कार्यक्षमता बेहतर होती है और प्रदूषण भी कम होता है जो सभी के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भविष्य में जैसे-जैसे वाहन निर्माता ई20 को ध्यान में रखकर वाहनों के इंजन डिजाइन करेंगे; वैसे-वैसे गाड़ियों का प्रदर्शन और बेहतर होते जाने की संभावना है। ई20 कोई नया प्रयोग नहीं है। यह गत 25 वर्षों की सुनियोजित तैयारी का परिणाम है।

ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि भारत ने अचानक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का निर्णय ले लिया जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। इस दिशा में काम वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। सबसे पहले सीमित स्तर पर एथेनॉल मिश्रण का परीक्षण हुआ। वर्ष 2004 में इसे औपचारिक कार्यक्रम का स्वरूप मिला और 2006 तक कई राज्यों में पांच प्रतिशत मिश्रण वाला ईन्धन उपलब्ध कराया जाने लगा था। सरकार ने इसमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। करीब दो दशक तक इस दिशा में अनेक स्तर पर काम किया गया।

WE STAND COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

BlitzINDIA Media Group

26 PLATFORMS

INDIA'S GLOBAL VOICE

8 LANGUAGES

4 NATIONAL EDITIONS (PRINT)

14 GLOBAL EDITIONS (ONLINE)

5 SOCIAL MEDIA PLATFORMS

3 WEBSITES

18 EDITIONS

www.blitzindiabusiness.com

NATIONAL (PRINT)

BlitzINDIA — DEVELOPMENT NEWS OF THE NATION

BlitzINDIA Business

ब्लिट्ज़ इंडिया

ब्लिट्ज़ इंडिया

International Editions (online)

(UN-recognised Languages)

- Blitz India in Arabic
- Blitz India Business in Arabic
- Blitz India in Chinese
- Blitz India Business in Chinese
- Blitz India in French
- Blitz India Business in French
- Blitz India in Russian
- Blitz India Business in Russian
- Blitz India in Spanish
- Blitz India Business in Spanish

(English Language)

- Blitz United States (New York)
- Blitz UK/Europe (London)
- Blitz Middle East (Dubai)
- Blitz Africa (Tanzania)

For subscription and other querries, connect

contactblitzindia@gmail.com | 9205992246 | 9205992248

A catalyst for Mission Viksit Bharat@2047

RNI No. DELHIN/2022/85477 । संपादित, मुद्रित एवं प्रकाशित द्वारा दीपक द्विवेदी : द इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301 (उ.प्र.)। संपादकीय, विज्ञापन और प्रशासनिक कार्यालय : 8-बी, वंदना बिल्डिंग, 11 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं.- 43502031, 43502032, ई-मेल: info@blitzindiamedia.com, **मुंबई ऑफिस :** 311-बी, आईएनएस टावर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051, मुख्य सलाहकार : ए.के. शर्मा, संपादक : विनोद शील, ग्रुप क्रिएटिव हैड : कौशल श्रीवास्तव
निदेशक संपादकीय बोर्ड : राकेश शर्मा (समाचार व सभी संपादकीय निर्णयों के लिए पीआरबी एक्ट के अनुसार उत्तरदायी), चेयरमैन एवं प्रधान संपादक : दीपक द्विवेदी (सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा)